नई दिल्ली
मंगलवार
01 सितंबर 2026
वर्ष: 12, अंक: 363
पृष्ठ: 08, मूल्य 2 रु0

E-mail
story@sadbhawna.today
sadbhavnatoday@gmail.com
web: www.sadbhawna.today

हिन्दी दैनिक समाचार पत्र

# सद्भावना टुडे

आवाज़ अधिकार की

25 वर्षों से लंबित सोन नदी जल बंटवारे के समाधान...पेज-05

DELHIN/2014/58158

रोहित शर्मा की टीवी पर नई पारी, 'फैमिली...पेज-06

## एक नजर

### खरगे के 'शुद्धिकरण' मामले में राहुल के खिलाफ प्राथमिकी पर कांग्रेस ने उठाए सवाल

**नई दिल्ली।** कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने उत्तराखंड में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की रैली के बाद 'शुद्धिकरण' के नाम पर कथित छुआछूत और अपमान के मामले में आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि न्याय की मांग करने वाले राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई, लेकिन खरगे के खिलाफ कथित भेदभाव करने वालों पर अब तक कार्रवाई नहीं हुई। रमेश ने सोमवार को एक्स पोस्ट में कहा कि राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दलितों के साथ हो रहे अन्याय, अपमान और भेदभाव का मुद्दा उठाया था। उन्होंने उत्तराखंड में खरगे की रैली के बाद 'शुद्धिकरण' के नाम पर किए गए छुआछूत और अपमान का मुद्दा भी उठाया तथा इसमें शामिल भाजपा कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई की मांग की थी। उन्होंने आरोप लगाया कि उत्तराखंड की भाजपा सरकार को राहुल गांधी की ओर से न्याय की मांग करना बर्दाश्त नहीं हुआ। यही कारण है कि आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, जबकि राहुल के खिलाफ अगले ही दिन एफआईआर दर्ज कर दी गई। यह उस सोच को दिखाता है जिसके सामने डॉ. भीमराव आंबेडकर का संविधान सबसे बड़ी दीवार है। रमेश ने कहा कि यह सब मुद्दे से ध्यान भटकाने और आवाज दबाने की कोशिश है। खरगे के खिलाफ शुद्धिकरण के नाम पर छुआछूत और अपमान करने वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि न्याय से कम कुछ भी मंजूर नहीं है।

### भारत के योगदान को शक्ति से नहीं, मानवता के लिए योगदान से मापा जाना चाहिए: भागवत

**टोरंटो,एजेंसी।** राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत ने भारतीयों से देश को एक बार फिर से विश्व गुरु बनाने का आह्वान करते हुए कहा है कि भारत के उत्थान को इस बात से नहीं मापा जाना चाहिए कि वह कितना शक्तिशाली बनता है, बल्कि इस बात से मापा जाना चाहिए वह मानवता के लिए कितना योगदान देता है। श्री भागवत ने यहां 'कैनेडियन हिंदूज़ फॉर आउटरीच, रिलेशंस एंड डायलॉग' (सीएचओआरडी ) की ओर से आयोजित 'हिंदू विश्व बंधु - दोस्ती के साथ दुनिया को अपनाएं' कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि भारत के उत्थान का अभिप्राय एकजुट और अधिक स्वतंत्र मानवता है। उन्होंने कहा कि एक समय भारत को महाशक्ति कहा जा सकता था, लेकिन वह महाशक्ति नहीं था। दुनिया की सेवा की और अपने चरित्र के कारण भारत 'विष्णु गुरु' बना, 'महाशक्ति' नहीं।

उन्होंने कहा कि भारत की परंपरा लोगों को विविधता में एकता देखने की शिक्षा देती है और विविधता खुद एकता का ही रूप है। उन्होंने इस विचार को 'वसुधैव कुटुंबकम' से जोड़ते हुए कहा कि पूरी दुनिया एक परिवार है और इस विचार के तहत लोगों को बाहरी अंतर से आगे बढ़कर साझा मानवता को पहचानना चाहिए। संघ प्रमुख ने इस दौरान हिंदुओं से विश्व कल्याण के लिए आगे आने भारत को फिर से विश्व गुरु बनाने का आह्वान किया है और कहा कि हिंदू जागेगा, तो ही दुनिया जागेगी। उन्होंने कहा 'जब मैं हिंदू कहता हूं, तो हिंदू शब्द को किसी खास भाषा, किसी खास पूजा-पद्धति या किसी खास जीवनशैली से परिभाषित नहीं किया जा सकता। ये इंसानों की विविधताएं हैं। हिंदू सभी का सम्मान करते हैं और उन्हें स्वीकार करते हैं।

# उ.प्र. के कौशांबी पटाखा फैक्टरी में विस्फोट से 11 लोगों की मौत

**मुख्यमंत्री ने दुख व्यक्त करते हुए मृतकों के परिजनों को दो-दो लाख रुपये और घायलों को 50-50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की**

**प्रयागराज,एजेंसी।** उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के पड़ोसी जिले कौशाम्बी के पिपरी थाना क्षेत्र में सोमवार को पटाखा फैक्टरी में हुए भीषण विस्फोट में 11 लोगों की मौत हो गई, जबकि पांच अन्य घायल हो गए। घायलों को स्वरूपरानी नेहरू चिकित्सालय समेत प्रयागराज के अन्य अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। कौशांबी के जिलाधिकारी अमित पाल शर्मा ने 11 लोगों की मौत की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि हादसे में मृतकों की संख्या 11 हो गई है। प्रशासन की ओर से घायलों के उपचार और राहत कार्य पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। घटना के कारणों की जांच भी कराई जा रही है। उन्होंने बताया कि जांच में यह जानकारी मिली है कि वर्ष 2024 में इसका लाइसेंस निरस्त कर दिया गया था। इसके खिलाफ सम्पत्ति जब्त करने की कार्रवाई की जाएगी। कौशांबी के पुलिस अधीक्षक सत्य नारायण प्रजापत के मुताबिक मामले में आदिल समेत छह लोगों के खिलाफ पिपरी थाने में गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की चार टीमें गठित की गई हैं। आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। उनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हादसे में जान गंवाने वालों में प्रियांजलि (5), प्रवीण सिंह (13), जाह्नवी (12), आदित्य (12), रवि (8), ज्ञान सिंह (40), आदित्य (8), अंजू (32), विक्रम सरोज (35), अंश (6) और नन्हा (4) शामिल हैं। हादसे में घायल पांच लोगों का उपचार स्वरूपरानी नेहरू चिकित्सालय में चल रहा है, जिनमें से तीन की हालत गंभीर है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस हादसे पर दुख व्यक्त करते हुए मृतकों के परिजनों को दो-दो लाख रुपये और घायलों को 50-50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को घायलों के समुचित उपचार और राहत कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतने के निर्देश दिए हैं। उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने घटना के दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई किए जाने की बात कही है। कौशांबी के सांसद पुष्पेंद्र सरोज ने हादसे को लेकर प्रशासनिक शिथिलता पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने घटना की उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग की है। उन्होंने कहा कि घटना के लिए जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय की जानी चाहिए और भविष्य में इस तरह के हादसे रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाने चाहिए। हादसे के बाद घटनास्थल और आसपास के क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। पुलिस मामले की जांच के साथ ही नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दे रही है।

## प. एशिया की स्थिति पर चिंता जतायी प्रधानमंत्री मोदी ने, कहा बातचीत से हो सभी मुद्दों का समाधान

**नई दिल्ली,एजेंसी।** प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव पर सोमवार को चिंता व्यक्त की और भारत के इस रूख को दोहराया कि सभी मुद्दों का समाधान संवाद और कूटनीति के माध्यम से किया जाना चाहिए। शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने किर्गिस्तान गये श्री मोदी ने सोमवार को राजधानी बिश्केक में ईरान के राष्ट्रपति डॉ. मसूद पेजेश्कियन के साथ द्विपक्षीय बैठक के दौरान यह बात कही। विदेश मंत्रालय ने बताया कि एससीओ सम्मेलन से इतर हुई बैठक में दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की। उन्होंने पश्चिम एशिया संघर्ष में हाल के घटनाक्रमों और बदलती स्थिति में पर अपने-अपने दृष्टिकोण साझा किए। श्री मोदी ने क्षेत्र में बढ़ते तनाव पर चिंता व्यक्त की और भारत के इस निरंतर रूख को दोहराया कि सभी मुद्दों का समाधान संवाद और कूटनीति के माध्यम से किया जाना चाहिए।

बैठक के बाद श्री मोदी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि भारत ईरान के साथ व्यापार के दायरे का विस्तार करते हुए इसमें विविधता चाहता है। उन्होंने कहा, 'बिश्केक में राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियन से मुलाकात की। विभिन्न क्षेत्रों में ईरान के साथ भारत की दीर्घकालिक मित्रता को मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया। हम आने वाले समय में अपने व्यापार के दायरे का विस्तार और विविधीकरण करना चाहते हैं। हमने क्षेत्र में वर्तमान स्थिति पर चर्चा की। भारत स्थायी शांति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किए जा रहे सभी प्रयासों का समर्थन करता रहेगा। प्रधानमंत्री ने क्षेत्र में स्थायी शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयासों की आवश्यकता को भी दोहराया। नौवहन और वाणिज्य की स्वतंत्रता की रक्षा का आह्वान करते हुए उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि नागरिकों और नागरिक अवसंरचना, जिसमें वाणिज्यिक जहाजरानी और नाविक शामिल हैं, को किसी भी परिस्थिति में नुकसान नहीं पहुंचाया जाना चाहिए। ब्रिक्स और एससीओ सहित बहुपक्षीय संगठनों में ईरान के साथ घनिष्ठ सहयोग की भारत की तत्परता को दोहराते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि हम ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए राष्ट्रपति पेज़ेश्कियन का भारत में स्वागत करने के लिए उत्सुक हैं।

## दिल्ली ड्राफ्ट मतदाता सूची में कम हुए 47.7 लाख मतदाता

**नई दिल्ली,एजेंसी।** दिल्ली में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की प्रक्रिया के बाद तैयार की गई मसौदा मतदाता सूची में 1 करोड़ 45 लाख से अधिक मतदाताओं में से केवल 97 लाख मतदाताओं के नाम ही शामिल किए गए हैं। यह संख्या कुल मतदाताओं की करीब 67.22 प्रतिशत है। दिल्ली में एसआईआर के तहत 30 जून से 17 अगस्त तक चले अभियान के तहत घर-घर जाकर और ऑनलाइन माध्यम से मतदाता सूची को अपडेट कराने की प्रक्रिया पूरी की गई। चुनाव आयोग के मुताबिक स्थाई रूप से पता बदलने, अपने आवास पर उपलब्ध न होने और अन्य कारणों से फॉर्म नहीं जमा कराने वाले मतदाताओं की संख्या 43,32,775 (29.86 प्रतिशत) है। इसके अलावा 2,82,412 (0.98 प्रतिशत) मतदाताओं की मृत्यु हो चुकी है और 1,41,535 (1.95 प्रतिशत) मतदाताओं का नाम एक से अधिक स्थान पर पाया गया है। कुल मिलाकर दिल्ली से 47, 56,722(67.22 प्रतिशत) नाम मसौदा मतदाता सूची में शामिल नहीं किए गए हैं। चुनाव आयोग की ओर से दिए गए आंकड़ों के अनुसार अब तक दिल्ली में 1,45,10,299 मतदाता थे। मसौदा मतदाता सूची में पुरुष मतदाताओं की संख्या 49,88,993 है। महिला मतदाताओं की संख्या 47,64,137 है। ट्रांसजेंडर की संख्या 447 है। 18 से 19 वर्ष के युवा मतदाताओं की संख्या 1,03,870 है। 85 वर्ष से अधिक आयु के 40,871 मतदाता हैं और 189 मतदाता 100 से अधिक आयु का आंकड़ा पार कर चुके हैं। चुनाव आयोग का कहना है कि राज्य के छूट गए मतदाता अब भी मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करा सकते हैं। इसके तहत अगले एक महीने यानी 30 सितंबर तक दावे और आपत्तियां फॉर्म 6 के माध्यम से एक प्रक्रिया के तहत जमा कराए जा सकते हैं। अंतिम मतदाता सूची 4 नवंबर को जारी की जाएगी। इससे पहले 29 अक्टूबर तक दावे और आपत्तियों का निपटान किया जाएगा। चुनाव आयोग के अनुसार इसी दौरान आयोग के दिशा-निर्देश में मतदान केन्द्रों की भी पुनर्व्यवस्था की गई है।

## केन्द्रीय मंत्रियों ने डॉ. प्रणब मुखर्जी को उनकी पुण्यतिथि पर दी श्रद्धांजलि

**नई दिल्ली,एजेंसी।** केन्द्रीय गृह एवं सहकारितामंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई नेताओं ने सोमवार को पूर्व राष्ट्रपति एवं भारत रत्न डॉ. प्रणब मुखर्जी को उनकी पुण्यतिथि पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी।

अमित शाह ने एक्स पर लिखा, 'पूर्व राष्ट्रपति एवं भारत रत्न डॉ. प्रणब मुखर्जी को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि। एक बेहतरीन प्रशासक और विद्वान, प्रणब दा ने सार्वजनिक जीवन में अपनी दशकों लंबी यात्रा के दौरान देश और उसके संवैधानिक मूल्यों के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का उदाहरण पेश किया। उनकी अमिट विरासत नए नेताओं के लिए प्रेरणा बनी हुई है।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि असाधारण मेधा के धनी और विद्वान राजनेता, प्रणब दा ने अपनी बुद्धिमत्ता, राजनीतिक सूझ-बूझ और संसदीय परंपराओं की गहरी समझ से भारत के सार्वजनिक जीवन को समृद्ध किया।

## देश की अर्थव्यवस्था अप्रैल-जून तिमाही में अनुमान से बेहतर 7.8 फीसदी की दर से बढ़ी

**नई दिल्ली,एजेंसी।** भारतीय अर्थव्यवस्था चालू वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही (अप्रैल-जून) में अनुमान से बेहतर 7.8 फीसदी की दर से बढ़ी है, जो पिछले वित्त वर्ष की इसी तिमाही में 6.9 फीसदी रही थी। ये वृद्धि दर पश्चिम एशिया में जारी संकट और इसकी वजह से उपजी वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता के बीच घरेलू आर्थिक गतिविधियों की मजबूती को दर्शाता है।

सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय की ओर से नेशनल मीडिया सेंटर में आयोजित पत्रकार वार्ता में मंत्रालय के सचिव डॉ. सौरभ गर्ग ने अप्रैल-जून तिमाही में देश की आर्थिक विकास दर 7.8 फीसदी पहुंचने पर अपनी प्रतिक्रिया दी। गर्ग ने कहा, 'भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती, जो हर वर्ष और हर तिमाही में दिख रही है, उसे देखते हुए सावधानी भरे अनुमान लगाना स्वाभाविक है, लेकिन मुझे लगता है कि भारतीय उपभोक्ता, भारतीय परिवार, प्राइवेट फ़ाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और कॉर्पोरेट व सरकारों के निवेश ने यह पक्का किया है कि विकास दर मजबूत बनी रहे। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) के मुताबिक चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 7.8 फीसदी वृद्धि दर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सात फीसदी के अनुमान से भी अधिक है। इस तरह भारत दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। आरबीआई ने वित्त वर्ष 2026-27 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 6.7 फीसदी रहने का अनुमान जताया है। एनएसओ के मुताबिक पश्चिम एशिया संकट से ऊर्जा कीमतों में तेज बढ़ोतरी, महंगाई के दबाव और वैश्विक मांग कमजोर होने की आशंका पैदा हुई थी। ऐसे में उम्मीद से बेहतर विकास दर से संकेत मिलता है कि बाहरी झटकों के बावजूद भारत की आर्थिक वृद्धि की गति अब तक कायम रही है। ये आंकड़ा नीति-निर्माताओं के लिए कुछ राहत लेकर आया है, क्योंकि वे वृद्धि को बनाए रखने के प्रयासों के साथ भू-राजनीतिक तनाव और जिंस बाजारों में उतार-चढ़ाव से पैदा होने वाले जोखिमों के बीच संतुलन बनाने में जुटे हैं। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) के मुताबिक चालू वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में स्थिर कीमतों पर वास्तविक जीडीपी 81.36 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान है। पिछले वित्त वर्ष 2025-26 की समान तिमाही में यह 75.46 लाख करोड़ रुपये था। मंत्रालय ने कहा, ''वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था ने पहली तिमाही में वृद्धि की गति बनाए रखी है।'' वहीं, मौजूदा कीमतों के आधार पर जीडीपी चालू वित्त वर्ष की अप्रैल-जून तिमाही में 88.27 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान है, जो पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में 80 लाख करोड़ रुपये था। इस तरह मौजूदा कीमतों पर जीडीपी में 10.3 फीसदी की वृद्धि हुई है।

## पूर्वांचल में रेल नेटवर्क मजबूत करने के लिए सात प्रमुख कॉरिडोर पर काम जारी: अश्विनी वैष्णव

**नई दिल्ली,एजेंसी।** रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोमवार को कहा कि उत्तर प्रदेश, खासकर पूर्वांचल में रेल कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए व्यापक स्तर पर काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मौजूदा दोहरी रेल लाइनों वाले सात प्रमुख रेल नेटवर्क को तीसरी और चौथी लाइन से मजबूत किया जा रहा है। वैष्णव ने यह बात नेपालगंज रोड-नानपारा-बहराइच रेलखंड के आमान परिवर्तन और विद्युतीकरण कार्य के शुभारंभ के अवसर पर वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कही। करीब 730 करोड़ रुपये की लागत से 56.15 किलोमीटर लंबे नेपालगंज रोड-नानपारा-बहराइच रेलखंड को मीटरगेज से ब्रॉडगेज में परिवर्तित करने के साथ इसका

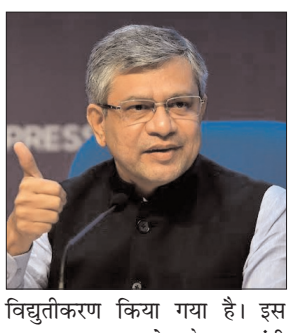

विद्युतीकरण किया गया है। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डुमरियागंज के सांसद जगदंबिका पाल, बहराइच के सांसद डॉ. आनंद कुमार गोंड और अन्य जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी मौजूद रहे।

वैष्णव ने कहा कि नेपालगंज रोड-नानपारा-बहराइच रेलखंड के ब्रॉडगेज में परिवर्तित होने से यह देश के व्यापक ब्रॉडगेज रेल नेटवर्क से जुड़ गया है। इससे बहराइच, रिसिया, मटेरा, नानपारा, बाबागंज और नेपालगंज रोड की कनेक्टिविटी बेहतर होगी। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में रेल संपर्क बढ़ाने के लिए चार मौजूदा ट्रेन सेवाओं का विस्तार नेपालगंज रोड तक किया गया है। इनमें वाराणसी-बहराइच एक्सप्रेस, वाराणसी सिटी-गोरखपुर एक्सप्रेस तथा दो जोड़ी गोंडा-बहराइच ट्रेन सेवाएं शामिल हैं। इससे नेपालगंज रोड और आसपास के यात्रियों को गोंडा, गोरखपुर, वाराणसी और अन्य प्रमुख शहरों के लिए सीधी रेल सुविधा मिलेगी। रेल मंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में प्रस्तावित हाई-स्पीड रेल कनेक्टिविटी से प्रमुख शहरों के बीच यात्रा का समय काफी कम हो जाएगा।

## उपराष्ट्रपति ने 'मिशन रंगीन मछली 2031' कार्य योजना का किया विमोचन

**नई दिल्ली,एजेंसी।** उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने लक्षद्वीप को राष्ट्र की अमूल्य समुद्री संपदा बताते हुए इसकी अपार मत्स्य पालन क्षमता पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि इसे 4,200 वर्ग किलोमीटर के लैगून क्षेत्र और लगभग 4 लाख वर्ग किलोमीटर के विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र की सहायता प्राप्त है। उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन सोमवार को केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं दुग्ध उत्पादन मंत्रालय के लक्षद्वीप के अगत्ती में आयोजित मत्स्य पालन लोकसंपर्क कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने इस दौरान आलंकारिक मत्स्य विकास के लिए 'मिशन रंगीन मछली 2031' रणनीतिक कार्य योजना का भी विमोचन किया। केंद्रीय मत्स्य विभाग ने टुना, समुद्री शैवाल और आलंकारिक मत्स्य संसाधनों जैसी उच्च मूल्य वाली प्रजातियों के सतत दोहन के साथ-साथ मत्स्य किसान उत्पादक संगठनों (एफएफपीओ) और मत्स्य सहकारी समितियों को सुदृढ़ करने पर विशेष ध्यान दिया है।

उन्होंने कहा कि यह लोकसंपर्क कार्यक्रम भारत सरकार, लक्षद्वीप प्रशासन, वैज्ञानिक

संस्थानों और मत्स्य पालन समुदायों की समुद्री अर्थव्यवस्था के माध्यम से सतत विकास और समृद्धि के एक नए युग की शुरुआत करने की सामूहिक प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने मत्स्य पालन और जलीय कृषि को अर्थव्यवस्था का एक उभरता हुआ सेक्टर बताते हुए लक्षद्वीप के लिए पीएमएमएसवाई के तहत 62 करोड़ रुपये से अधिक की मत्स्य विकास परियोजनाओं की स्वीकृति की सराहना की। उपराष्ट्रपति ने ईईजेड और खुले समुद्रों से मत्स्य संसाधनों के सतत दोहन के लिए सरकार द्वारा घोषित सक्षम ढांचे पर भी प्रकाश डाला और कहा कि इससे मछुआरों को गहरे समुद्र के संसाधनों तक जिम्मेदारी से पहुंचने और नए अवसरों का लाभ उठाने में मदद मिलेगी। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि लक्षद्वीप में एक लाख टन से अधिक की मत्स्य पालन क्षमता है, जिसमें लगभग 94,000 टन टुना और टुना जैसी प्रजातियां शामिल हैं। उन्होंने मछुआरों की आय बढ़ाने और वैश्विक समुद्री खाद्य बाजारों में भारत की स्थिति को मजबूत करने के लिए वैज्ञानिक कटाई, डिजिटल प्राधिकरण प्रणाली, पोत निगरानी, अंतरराष्ट्रीय प्रमाणन और टिकाऊ मत्स्य पालन कार्यप्रणालियों के महत्व को रेखांकित किया। इस कार्यक्रम के दौरान उपराष्ट्रपति ने पीएमएमएसवाई के तहत लाभार्थियों को लाभ वितरित किए। इन लाभार्थियों में हलीमा के चेरियादम, अध्यक्ष, मल्स्याम फिशरमेन कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, एंड्रोथ द्वीप; निजी उद्यमी अल्थाफ मुनाव्वर तनवीर, नूर मोहम्मद, अमीन बिन मोहम्मद सीएन; सादिक एस, नौशाद खान नशीदा महल, आशिक, किदावे कुन्हीकडियापाड़ा और मछुआरे अबू बकर उरियोदा और सबीह मुबारक शामिल थे।

# स्कूल और स्कूली बसों में बच्चों के साथ दुर्व्यवहार के दोषियों सख्त कार्रवाई का निर्देश

## मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बस में किशोरी से बलात्कार की घटना पर जताया दुख, दूसरे राज्यों की बसों के जीपीएस को दिल्ली के सिस्टम से जोड़ने की तैयारी

**सैफुल्लाह सिद्दीकी, वरिष्ठ पत्रकार**

**नई दिल्ली।** मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने स्कूल और स्कूली बसों में बच्चों के साथ दुर्व्यवहार की घटनाओं पर गहरा रोष व्यक्त करते हुए दोषी स्कूलों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि ऐसी घटनाओं में केवल प्रत्यक्ष दोषियों पर ही नहीं, बल्कि लापरवाही बरतने वाले स्कूल प्रबंधन और संबंधित जिम्मेदार लोगों की भी जवाबदेही तय की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि स्कूल जाने वाले मासूम बच्चों के साथ होने वाला अमानवीय व्यवहार किसी भी सभ्य समाज के लिए बेहद पीड़ादायक है। सरकार ऐसे मामलों में चुप नहीं बैठेगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बच्चों की सुरक्षा से जुड़े मामलों में तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित की जाए और दोषियों के खिलाफ कानून के तहत सख्त कदम उठाए जाएं। जाफराबाद स्थित एक निजी डे-केयर एवं प्ले स्कूल में तीन वर्षीय बच्चे के साथ कथित शारीरिक एवं यौन दुर्व्यवहार की घटना पर मुख्यमंत्री ने गहरी नाराजगी व्यक्त की है। उन्होंने संबंधित स्कूल को सील करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कानून अपना काम कर रहा है, लेकिन सरकार भी ऐसे गंभीर मामलों पर मूकदर्शक नहीं बनी रहेगी। उन्होंने यह भी कहा कि यदि पीड़ित बच्चे के परिवार को कानूनी सहायता की आवश्यकता होगी तो दिल्ली सरकार उन्हें आवश्यक सहायता उपलब्ध कराएगी। मुख्यमंत्री ने बवाना क्षेत्र में तीन वर्षीय नर्सरी छात्रा के साथ यौन शोषण की घटना पर भी गहरा दुख व्यक्त किया है। इस मामले में स्कूल बस चालक के कथित

स्पष्ट किया कि भविष्य में किसी स्कूली बस के स्टाफ की संलिप्तता सामने आती है तो संबंधित स्कूल प्रबंधन की जिम्मेदारी भी तय की जाएगी। सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि स्कूलों, डे-केयर केंद्रों और स्कूली परिवहन व्यवस्था में बच्चों की सुरक्षा के लिए तय जिम्मेदारियों का पूरी तरह पालन हो और लापरवाही सामने आने पर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री ने दिल्ली-एनसीआर में उत्तर प्रदेश की 16 वर्षीय किशोरी के साथ चलती बस में बलात्कार की घटना पर भी गहरा दुख व्यक्त किया है। घटना में बस चालक और परिचालक की भूमिका पर चिंता जताते हुए उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाएं पूरे सभ्य समाज को झकझोर देती हैं। दिल्ली सरकार इस विषय पर पड़ोसी राज्यों की सरकारों से भी बातचीत करेगी ताकि दिल्ली आने-जाने वाली बसों में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को और मजबूत किया जा सके। उन्होंने कहा कि ऐसी व्यवस्था विकसित करने पर काम किया जाएगा, जिसके तहत दूसरे राज्यों से दिल्ली में प्रवेश करने वाली बसों का जीपीएस सिस्टम दिल्ली के संबंधित विभाग के सिस्टम से जुड़ा हो। इससे बस की लोकेशन सहित आवश्यक जानकारी पर निगरानी रखी जा सकेगी और किसी आपात स्थिति में त्वरित कार्रवाई में मदद मिलेगी।

# राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर के विरोध में कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन आज

**शाहनवाज सैफ, सद्भावना टुडे**

**नई दिल्ली।** दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ उत्तराखंड में एफआईआर दर्ज किए जाने के विरोध में दिल्ली कांग्रेस मंगलवार, 1 सितंबर को राजधानी के सभी 14 संगठनात्मक जिलों में विरोध प्रदर्शन करेगी। उन्होंने कहा कि इस प्रदर्शन में हजारों कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल होंगे। देवेंद्र यादव ने कहा कि राहुल गांधी ने दलितों के साथ हो रहे अन्याय, अपमान और भेदभाव के मुद्दे को उठाया था। उन्होंने आरोप लगाया कि उत्तराखंड में कांग्रेस अध्यक्ष एवं राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे की रैली के बाद रैली स्थल का कथित रूप से 'शुद्धिकरण' किया गया। राहुल गांधी ने इसी मामले में संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी।

दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करना 'उल्टा चोर कोतवाल को डांटे' वाली कहावत को चरितार्थ करता है। उन्होंने सवाल किया कि एक आम व्यक्ति की शिकायत पर राहुल गांधी के खिलाफ मामला दर्ज किया जा सकता है, लेकिन कथित तौर पर शुद्धिकरण करने और अपमानजनक कृत्य में शामिल लोगों के खिलाफ अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई। यादव ने आरोप लगाया कि भाजपा की मानसिकता संविधान और सामाजिक न्याय के मूल्यों के विपरीत है। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर का संविधान समानता और सामाजिक न्याय की गारंटी देता है और कांग्रेस संविधान की रक्षा के लिए लगातार संघर्ष करती रहेगी।

देवेंद्र यादव ने कहा कि घटना को 20 दिन से अधिक समय बीत जाने के बावजूद कथित रूप से शुद्धिकरण करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि 'शुद्धिकरण' के नाम पर किसी व्यक्ति या समुदाय का अपमान करना सामाजिक भेदभाव की मानसिकता को दर्शाता है और ऐसे मामलों में कानून के अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ कथित तौर पर किए गए अपमान को पार्टी किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करेगी। कांग्रेस ने मांग की कि राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज एफआईआर वापस ली जाए तथा शुद्धिकरण की घटना में शामिल लोगों के खिलाफ तत्काल मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाए।कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि 1 सितंबर को दिल्ली के सभी 14 जिलों में होने वाले विरोध प्रदर्शनों के जरिए पार्टी संविधान, समानता, सामाजिक न्याय और दलित सम्मान के मुद्दे को प्रमुखता से उठाएगी।

# दिल्ली सरकार ने पिंक टिकट व्यवस्था को 17 सितंबर तक बढ़ाया

**नई दिल्ली।** दिल्ली सरकार ने दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) बसों में महिलाओं के लिए मुफ़्त यात्रा की सुविधा देने वाले मौजूदा पेपर-बेस्ड 'पिंक टिकट' को 17 सितंबर तक बढ़ा दिया है। यह फैसला 'पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड' आधारित सिस्टम में आसानी से बदलाव सुनिश्चित करने और आगामी त्योहारों के दौरान महिला यात्रियों को किसी भी तरह की परेशानी से बचाने के मकसद से लिए लिया गया है। परिवहन मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने कहा कि पिंक टिकट की व्यवस्था 17 सितंबर तक जारी रहेगी, जिससे महिलाएं इस दौरान पिंक टिकट मुफ्त बस यात्रा सुविधा का लाभ उठाती रहेंगी। इसके बाद मुफ्त यात्रा सुविधा का लाभ उठाने के लिए 'पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड' सिस्टम पूरी तरह से लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह विस्तार ऐसे समय में किया गया है, जब जन्माष्टमी, तीज, गणेश चतुर्थी समेत कई महत्वपूर्ण त्योहारों का आयोजन हो रहा है। इन धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक मौकों पर महिलाएं और परिवार ज़्यादा यात्रा करते हैं। इस दौरान 'पिंक टिकट' सुविधा जारी रहने से पात्र महिला यात्रियों को बिना किसी रुकावट के मुफ़्त बस यात्रा की सुविधा मिलती रहेगी। मंत्री ने कहा कि 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का जन्मदिन भी है और इसी दिन से 17 सितंबर से 2 अक्तूबर तक मनाए जाने वाले 'सेवा पखवाड़ा' की शुरुआत होती है।

# महापौर प्रवेश वाही ने दक्षिणी पूर्वी जोन का किया निरीक्षण

**नई दिल्ली,एजेंसी।** दिल्ली के महापौर प्रवेश वाही ने राजधानी की सफाई व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए सोमवार को दक्षिणी पूर्वी जोन के विभिन्न क्षेत्रों का व्यापक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान महापौर ने विजय कैंप में निर्माणाधीन फिक्सड कॉम्पेक्टर ट्रांसफर स्टेशन (एफसीटीएस) के निर्माण के विकास कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को फिक्स्ड कॉम्पेक्टर को जल्द से जल्द स्थापित करने के निर्देश दिए, जिससे क्षेत्रवासियों को बेहतर सुविधा उपलब्ध हो सके।

इस अवसर पर महापौर ने निगमायुक्त संजीव खिरवार के साथ लाजपत नगर स्थित ऐनिमल बर्थ कंट्रोल (एबीसी) सेंटर का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने सेंटर की व्यवस्थाओं एवं कार्यप्रणाली को बारीकी से देखा और पशु चिकित्सा अधिकारियों से बात की। सेंटर में बहुत से आवारा कुत्तों की ठीक देखभाल नहीं होने पर निगमायुक्त संबंधित संस्था एवं अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने के निर्देश दिए। वाही ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि एबीसी सेंटर में आवारा कुत्तों का उचित इलाज एवं देखभाल में कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डॉग शेल्टर में पर्याप्त संसाधन सुनिश्चित किया जाए और किसी भी प्रकार की कोताही ना बरती जाए। उन्होंने कहा कि दिल्ली नगर निगम पशु कल्याण एवं नागरिकों सुविधाओं में निरंतर सुधार के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने अधिकारियों को एबीसी सेंटर में आवारा कुत्तों के उचित देखभाल और निगरानी के सख्त निर्देश दिए।

महापौर ने लाजपत नगर सेंट्रल मार्केट स्थित पार्किंग के समीप निर्माणाधीन फिक्सड कॉम्पेक्टर को भी यथाशीघ्र पूरा किए जाने का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि उक्त आधारभूत सुविधाएं अतिशीघ्र जनता की सुविधा के लिए शुरू की जाए। महापौर वाही ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि लाजपत नगर क्षेत्र में स्वच्छता संबंधित सभी विकास कार्यों को सितम्बर माह तक निश्चित रूप से पूरे किए जाने चाहिए। उन्होंने दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र के सभी वार्डों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन व्यवस्था की समीक्षा करते हुए उन सभी स्थानों को तत्काल साफ करने के निर्देश दिए जहां से ढलाव बंद कर फिक्स्ड कंपेक्टर ट्रांसफर स्टेशन में स्थानांतरित किए गए हैं।

# बच्चे से दरिंदगी मामले में मौजपुर के प्ले स्कूल को सील करने की कार्रवाई शुरू

**नई दिल्ली।** बच्चे के साथ दरिंदगी मामले में मौजपुर (जाफराबाद) इलाके के प्ले स्कूल को सील करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। दिल्ली सरकार ने बच्चे के साथ हुई भयावह घटना को गंभीरता से लिया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के निर्देश पर जिला मजिस्ट्रेट ने स्कूल परिसर को सील करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस जांच चल रही है। दिल्ली सरकार ने दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। उल्लेखनीय है कि जाफराबाद के प्ले स्कूल में मासूम के साथ दरिंदगी मामला सामने आया है। पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर स्कूल की निदेशिका, प्रधानाचार्या, शिक्षिका और आया के खिलाफ जाफराबाद थाने में पॉक्सो एक्ट, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट और भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न गंभीर धाराओं के तहत मुकदमा 28 अगस्त को दर्ज किया है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को कब्जे में लेकर मामले की विस्तृत जांच कर रही है।

# केजरीवाल ने दिल्ली एसआईआर की आलोचना की, कहा 47 लाख वोटरों के नाम ड्राफ्ट लिस्ट से गायब

**नई दिल्ली।** आम आदमी पार्टी (आआपा) के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत दिल्ली की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट आने पर चुनाव आयोग पर निशाना साधा। अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा कि दिल्ली एसआईआर के तहत जारी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में करीब 1.5 करोड़ मतदाताओं में से 47 लाख लोगों के नाम शामिल नहीं हैं। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि एसआईआर के जरिए बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम हटाए जा रहे हैं। उन्होंने आयोग पर कटाक्ष करते हुए कहा कि केंद्र सरकार को जनसंख्या को लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं। चुनाव आयोग देश की जनसंख्या कम कर देगा। उल्लेखनीय है कि दिल्ली की ड्राफ्ट रोल सोमवार को प्रकाशित किया गया, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी के 1.45 करोड़ मतदाताओं में से 47.7 लाख के नाम हटाए गए हैं। आयोग का कहना है कि लगभग 43 लाख मतदाताओं ने आयोग के समक्ष फार्म जमा नहीं कराए हैं।

# एमसीडी आयुक्त ने सैनिटेशन स्टाफ के साथ की ओपन हाउस बैठक, जिम्मेदारी और सकारात्मक सोच के साथ काम करने पर दिया जोर

**शबाना बेगम, वरिष्ठ पत्रकार**

**नई दिल्ली।** दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) आयुक्त संजीव खिरवार ने सोमवार को सिविक सेंटर स्थित केदारनाथ साहनी ऑडिटोरियम में निगम के स्वच्छता सुपरवाइजरों एवं कर्मचारियों के साथ ओपन हाउस बैठक की। बैठक का उद्देश्य स्वच्छता कर्मचारियों को अपनी समस्याएं, सुझाव और जमीनी अनुभव सीधे निगम आयुक्त के सामने रखने का अवसर देना था। इस दौरान अपर आयुक्त अरुण कुमार मिश्रा सहित सभी 12 जोनों के उपायुक्त भी मौजूद रहे।

बैठक में आयुक्त संजीव खिरवार ने स्वच्छता कर्मचारियों की समस्याओं और सुझावों को गंभीरता से सुना। उन्होंने कहा कि स्वच्छता एमसीडी की सबसे बुनियादी और महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों में शामिल है तथा दिल्ली को साफ-सुथरा बनाए रखने में प्रत्येक स्वच्छता कर्मचारी की महत्वपूर्ण भूमिका है। आयुक्त ने कहा कि वर्तमान मानसून सीजन एमसीडी के लिए पिछले कुछ वर्षों की तुलना में बेहतर रहा है। उन्होंने मानसून के दौरान स्वच्छता व्यवस्था बनाए रखने और नागरिक सेवाओं को सुचारु रखने के लिए स्वच्छता कर्मचारियों एवं अधिकारियों के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि आने वाले महीने निगम के लिए स्वच्छता के लिहाज से काफी चुनौतीपूर्ण रहने वाले हैं। सितंबर में प्रस्तावित ब्रिक्स सम्मेलन, इसके बाद

त्योहारी सीजन और सर्दियों के मौसम को देखते हुए सफाई व्यवस्था को और मजबूत करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि सर्दियों में प्रदूषण नियंत्रण भी एक बड़ी चुनौती होगी, इसलिए एमसीडी को पहले से पूरी तैयारी करनी होगी।

संजीव खिरवार ने अधिकारियों और स्वच्छता कर्मचारियों से अपनी जिम्मेदारियों को पूरी गंभीरता से निभाने तथा सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ काम करने का आह्वान किया। उन्होंने सभी उपायुक्तों को अपने-अपने जोन में स्वच्छता कर्मचारियों की शत-प्रतिशत उपस्थिति और प्रभावी तैनाती सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। आयुक्त ने कहा कि नियमित रूप से लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, जबकि ईमानदारी और समर्पण के साथ काम करने वाले कर्मचारियों को प्रोत्साहित एवं पुरस्कृत किया जाना चाहिए। उन्होंने नियमित निगरानी, जवाबदेही और टीमवर्क को स्वच्छता व्यवस्था की सफलता के लिए आवश्यक बताया। सोशल मीडिया की बढ़ती भूमिका का उल्लेख करते हुए आयुक्त ने कहा कि आज नागरिक सोशल मीडिया के माध्यम से नागरिक सुविधाओं से जुड़ी समस्याएं निगम के सामने रखते हैं। उन्होंने अधिकारियों से ऐसी शिकायतों को सकारात्मक रूप से लेने की अपील की। उन्होंने कहा कि नागरिकों द्वारा उठाई गई समस्याएं निगम के लिए अपनी सेवाओं में सुधार का अवसर हैं। जो नागरिक किसी समस्या की ओर निगम का ध्यान आकर्षित करते हैं, उनके सहयोग और सकारात्मक प्रतिक्रिया की सराहना की जानी चाहिए।

# सुकेश चंद्रशेखर की याचिका का दिल्ली पुलिस ने किया विरोध

**नई दिल्ली।** दिल्ली पुलिस ने सुकेश चंद्रशेखर की उस याचिका का उच्च न्यायालय में विरोध किया है, जो उसने खुद को उच्चतम न्यायालय का जज बनकर भ्रष्टाचार निरोधक कानून के स्पेशल जज को प्रभावित करने की कोशिश करने के मामले में आठ साल तक की लगातार सश्रम कैद की सजा देने के ट्रायल कोर्ट के आदेश में की गई प्रतिकूल टिप्पणी को हटाने के खिलाफ दायर की है। दिल्ली पुलिस ने जस्टिस मधु जैन की बेंच के समक्ष इस याचिका के सुनवाई योग्य होने पर सवाल उठाया। मामले की अगली सुनवाई 3 नवंबर को होगी।

इस मामले में 29 अगस्त को सुकेश चंद्रशेखर को आठ साल तक की लगातार सश्रम कैद की सजा सुनाई गई थी। कोर्ट ने कहा था कि पहचान का ढोंग करना केवल एक व्यक्ति के साथ धोखाधड़ी नहीं है, यह न्यायपालिका की संस्थागत विश्वसनीयता पर गंभीर हमला है। ऐसे अपराधों का असर उस व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता, जिसे धोखा दिया गया हो। कोर्ट ने सजा की अवधि तय करते समय सुकेश चंद्रशेखर की ओर से कोई पछतावा नहीं दिखाये जाने और शिकायतकर्ता पर ही सवाल उठाने पर गौर किया था। तीस हजारी कोर्ट ने पाया था कि आरोपित की ओर से सजा कम कराने की कोशिश के बजाय कार्यवाही में देरी की कोशिश की गई। तीस हजारी कोर्ट ने सुकेश को भारतीय दंड संहिता की धारा 170, 189 और 507 के तहत दोषी करार दिया था। सुकेश पर आरोप था कि उसने न्यायिक हिरासत में रहते हुए कांस्टेबल मनजीत के मोबाइल फोन तक पहुंच हासिल की। कांस्टेबल मनजीत के मोबाइल फोन से उसने भ्रष्टाचार मामले की सुनवाई कर रहे स्पेशल जज के आधिकारिक लैंडलाइन नंबर पर संपर्क किया। कोर्ट ने कांस्टेबल मनजीत की भूमिका की दोबारा जांच करने का भी निर्देश दिया था। कोर्ट ने कहा था कि इस बात की जांच होनी चाहिए कि सुकेश मनजीत के फोन तक कैसे पहुंचा और इस पूरी साजिश में कांस्टेबल मनजीत की क्या भूमिका थी।

# बवाना के निजी स्कूल में नाबालिग छात्रा से यौन शोषण, आरोपित कर्मचारी गिरफ्तार

**नई दिल्ली।** दिल्ली पुलिस ने बाहरी उत्तर जिले के बवाना (पूठ खुर्द) स्थित एक निजी स्कूल में नाबालिग छात्रा के साथ यौन शोषण मामले में एक आरोपित स्कूल कर्मचारी को गिरफ्तार किया है। इस मामले की विस्तृत जांच के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित किया है। पुलिस के अनुसार 24 अगस्त को बवाना थाना पुलिस को घटना की सूचना प्राप्त हुई थी। पुलिस टीम ने तुरंत मौके पर पहुंचकर परिजनों और शिकायतकर्ता से संपर्क किया। आरोपित के खिलाफ बवाना थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई। उसके खिलाफ पॉक्सो एक्ट की धारा तथा भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 74 के तहत मामला दर्ज किया गया है। पीड़िता का नियमानुसार मेडिकल परीक्षण कराया गया और बाल-सुलभ वातावरण में सीडब्ल्यूसी, अदालत के समक्ष बयान दर्ज कराए गए।

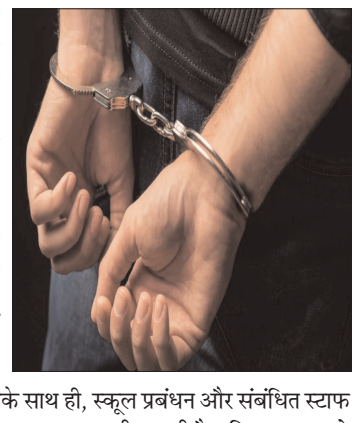

पुलिस ने घटनास्थल से इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य और सीसीटीवी फुटेज जब्त कर फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिए हैं। आरोपी की आपराधिक पृष्ठभूमि की भी जांच की जा रही है। इसके साथ ही, स्कूल प्रबंधन और संबंधित स्टाफ को जांच के दायरे में शामिल कर पूछताछ की जा रही है ताकि यह स्पष्ट हो सके कि सुरक्षा मानकों में कोई लापरवाही तो नहीं बरती गई थी। पुलिस का कहना है कि तय समयसीमा के भीतर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की जाएगी। बाहरी उत्तर जिला पुलिस ने स्कूल प्रबंधन और अभिभावकों से बच्चों की सुरक्षा को लेकर अतिरिक्त सतर्कता बरतने की अपील की है। पुलिस ने कहा है कि स्कूलों में ड्राइवर, हेल्पर, गार्ड और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति केवल पुलिस सत्यापन के बाद की जाए। बच्चों को लाने-ले जाने के लिए बिना सत्यापन वाले निजी या गैर-कमर्शियल वाहनों का इस्तेमाल नहीं किया जाए। इसके लिए परमिट वाले पंजीकृत कमर्शियल वाहनों को ही इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है। स्कूलों में सीसीटीवी कैमरे चालू हालत में रखने और उनकी रिकॉर्डिंग का बैकअप सुरक्षित रखने को भी कहा गया है। छोटे बच्चों की सुरक्षा के लिए महिला स्टाफ की तैनाती सुनिश्चित करने की सलाह दी गई है। पुलिस ने स्पष्ट किया कि बच्चों से जुड़े किसी भी तरह के दुर्व्यवहार की जानकारी तुरंत 112 या चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 पर दी जाए। पॉक्सो एक्ट के तहत ऐसी घटना की जानकारी नहीं देना भी दंडनीय है। पुलिस ने कहा कि बच्चों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और बच्चों के खिलाफ अपराध के मामलों में जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्रवाई जारी रहेगी।

# स्वस्थ विद्यार्थी और सशक्त शिक्षक ही विकसित भारत की मजबूत नींव : जय भगवान यादव

**एम.जबिउल्लाह, सद्भावना टुडे**

**नई दिल्ली।** दिल्ली नगर निगम के विद्यालयों में शारीरिक शिक्षा, फिटनेस और स्वस्थ जीवनशैली को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित 15 दिवसीय शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण शिविर का सोमवार को नजफगढ़ क्षेत्र के ककरौला स्थित डॉ. साहब सिंह वर्मा स्टेडियम में भव्य समापन हुआ। प्रशिक्षण शिविर में दिल्ली नगर निगम के सभी जोनों से करीब एक हजार शिक्षकों ने भाग लिया।

शिविर के दौरान शिक्षकों को शारीरिक शिक्षा, योग, व्यायाम, फिटनेस, खेल गतिविधियों तथा स्वस्थ एवं अनुशासित जीवनशैली से जुड़े विभिन्न व्यावहारिक पहलुओं का प्रशिक्षण दिया गया। समापन समारोह में प्रतिभागी शिक्षकों ने स्वस्थ, स्वच्छ एवं नशामुक्त भारत के निर्माण का संकल्प भी लिया। समारोह में सांसद कमलजीत सहरावत, दिल्ली नगर निगम के नेता सदन जय भगवान यादव, नजफगढ़ क्षेत्र वार्ड समिति के अध्यक्ष जयवीर राणा, उपाध्यक्ष सुषमा पवन राठी, शिक्षा समिति के अध्यक्ष योगेश वर्मा, उपाध्यक्ष अमित खरखड़ी, पार्षद सुदेश गहलोत, अपर आयुक्त शिक्षा संजीव मित्तल, नजफगढ़ क्षेत्र के उपायुक्त शाश्वत सौरभ, निदेशक शिक्षा निखिल तिवारी सहित वरिष्ठ अधिकारी, प्रशिक्षक, शिक्षक-शिक्षिकाएं और विद्यार्थी

मौजूद रहे। समारोह को संबोधित करते हुए सांसद कमलजीत सहरावत ने प्रशिक्षण शिविर के सफल आयोजन की सराहना की। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम युवाओं और विद्यार्थियों में स्वस्थ जीवनशैली, अनुशासन तथा आत्मविश्वास विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। निगम के नेता सदन जय भगवान यादव ने कहा कि दिल्ली नगर निगम की प्राथमिकताओं में शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान है। उन्होंने कहा कि निगम के विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता के साथ विद्यार्थियों के स्वास्थ्य, खेलकूद और व्यक्तित्व विकास पर भी समान रूप से ध्यान दिया जाना जरूरी है। उन्होंने कहा, 'स्वस्थ विद्यार्थी एवं सशक्त शिक्षक ही विकसित भारत की मजबूत नींव हैं।' उन्होंने प्रशिक्षण कार्यक्रम को विद्यालयी व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल बताते हुए शिक्षकों से प्रशिक्षण में हासिल जानकारी को अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक पहुंचाने का आह्वान किया।

शिक्षा समिति के अध्यक्ष योगेश वर्मा ने कहा कि शारीरिक शिक्षा विद्यार्थियों के समग्र विकास का आवश्यक हिस्सा है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन और सकारात्मक सोच का विकास होता है। उन्होंने शिक्षकों से विद्यालयों में खेल और शारीरिक गतिविधियों को केवल अतिरिक्त गतिविधि के रूप में न देखने, बल्कि उन्हें शिक्षा की मुख्यधारा का हिस्सा बनाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि यदि सामान्य शिक्षक भी बच्चों की फिटनेस, खेलकूद और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता विकसित करने में सक्रिय भूमिका निभाएं तो इसका सकारात्मक प्रभाव विद्यालय के प्रत्येक विद्यार्थी तक पहुंच सकता है। 15 दिनों तक चले इस प्रशिक्षण शिविर की खास बात यह रही कि इसे केवल विशेषज्ञ शारीरिक शिक्षा शिक्षकों तक सीमित नहीं रखा गया, बल्कि सामान्य शिक्षकों को भी शारीरिक शिक्षा और फिटनेस से जोड़ा गया।

प्रशिक्षण के दौरान शिक्षकों को योग, व्यायाम, फिटनेस और विभिन्न खेल गतिविधियों के साथ-साथ बच्चों में स्वस्थ जीवनशैली एवं अनुशासन विकसित करने के व्यावहारिक तरीकों की जानकारी दी गई। कार्यक्रम को राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 की भावना से जोड़ते हुए विद्यार्थियों के शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक विकास पर विशेष जोर दिया गया। शिक्षकों को बताया गया कि शिक्षा का उद्देश्य केवल शैक्षणिक उपलब्धियां हासिल करना नहीं, बल्कि विद्यार्थियों में आत्मविश्वास, टीम भावना, अनुशासन और सकारात्मक सोच विकसित करना भी है। समापन अवसर पर प्रशिक्षण शिविर के सफल आयोजन के लिए अतिथियों, वरिष्ठ अधिकारियों, प्रशिक्षकों, आयोजन समिति तथा प्रतिभागी शिक्षक-शिक्षिकाओं के प्रति आभार व्यक्त किया गया।

## एक नजर

### ग्रेटर नोएडा के कासना में लाइसेंसी पिस्टल से चली गोली

**ग्रेटर नोएडा।** ग्रेटर नोएडा के कासना कस्बे में लाइसेंसी पिस्टल से अचानक गोली चलने से 16 साल का किशोर घायल हो गया। गोली किशोर के पेट में लगी। घटना के वक्त वह सैलून में काम कर रहा था। वह जिम्स अस्पताल में उपचाराधीन है। उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। पुलिस ने जांच के बाद पिस्टल के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। कासना कस्बे में अलीगढ़ के थाना टप्पल अटारी गांव निवासी 16 वर्षीय प्रिंस उर्फ राजा सैलून की दुकान पर काम करता है। रविवार रात वह दुकान पर काम कर रहा था। उसी दौरान अचानक गोली लगने के बाद घायल हो गया पुलिस जांच में सामने आया है कि विकल सिंह के पास उसके भतीजे शिवा की लाइसेंसी पिस्टल थी। इसी दौरान अचानक पिस्टल से गोली चल गई। गोली पास में हेयर सैलून में मौजूद प्रिंस के पेट में जा लगी। गोली चलने के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। स्वजन ने घायल किशोर को अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस ने घटना में इस्तेमाल पिस्टल बरामद कर विकल सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। घायल किशोर के पिता की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि लाइसेंसी पिस्टल विकल सिंह के पास किस तरह पहुंची और घटना के समय वहां कौन-कौन मौजूद था।

### सफाई कर्मचारियों व फायर कर्मियों का धरना 26वें दिन भी जारी

**नूंह।** नूंह जिले में सफाई कर्मचारी और फायर विभाग के कर्मचारी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर छह अगस्त से धरने पर बैठे हुए हैं। सोमवार को कर्मचारियों का धरना 26वें दिन भी जारी रहा। कर्मचारियों का कहना है कि वे लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर सरकार और संबंधित विभाग के अधिकारियों के समक्ष अपनी बात रखते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक उनकी मांगों का ठोस समाधान नहीं हुआ है। इसी के चलते कर्मचारियों ने आंदोलन का रास्ता अपनाया है। सफाई कर्मचारियों ने अपनी मांगों के समर्थन में कामकाज बंद कर हड़ताल जारी रखी हुई है। कर्मचारियों के हड़ताल पर रहने से शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में नियमित सफाई कार्य प्रभावित हो रहा है। कई स्थानों पर सफाई व्यवस्था को लेकर लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं, फायर विभाग के कर्मचारी भी धरने में शामिल होकर अपनी मांगों को लेकर आवाज उठा रहे हैं। कर्मचारियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। कर्मचारियों ने धरना स्थल पर एकजुट होकर अपनी मांगों के समर्थन में आवाज बुलंद की। उनका कहना है कि वे शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचा रहे हैं और उम्मीद है कि जल्द ही उनकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा।

### पांच सौ रुपए मांगने पर युवक की हत्या

**फरीदाबाद।** फरीदाबाद में पांच सौ रुपए मांगने को लेकर हुए विवाद में एक युवक की हत्या कर दी गई। साथ काम करने वाले युवक ने शराब के नशे में पहले बीयर की बोतल उसके सिर में फोड़ी। इसके बाद कांच गले में घोंप दिया। गंभीर रूप से घायल युवक को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। एनआईटी थाना पुलिस ने हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी से पूछताछ की जा रही है। मृतक की पहचान गांधी कॉलोनी निवासी सागर (26) के रूप में हुई है। वह आरोपी कालू के साथ चेन-कुप्पी (भारी सामान उठाना) का काम करता था। कालू भी गांधी कॉलोनी का ही रहने वाला है। कालू ठेकेदार है और सागर उसके साथ मजदूरी करता था। पुलिस के अनुसार, रविवार रात सागर और कालू रेलवे स्टेशन के पास बैठकर शराब पी रहे थे। इसी दौरान किसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हो गया। आरोप है कि शराब पीने के दौरान सागर ने कालू से अपने 500 रुपए मांगे। इसी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी शुरू हो गई। कुछ ही देर में विवाद बढ़कर झगड़े में बदल गया। आरोप है कि झगड़े के दौरान कालू ने बीयर की बोतल सागर के सिर पर मारकर फोड़ दी। इसके बाद आरोपी ने टूटी हुई बोतल के कांच से सागर के गले और पेट पर वार कर दिए। गंभीर चोट लगने के बाद सागर जमीन पर गिर गया। घटना के बाद परिजन घायल सागर को इलाज के लिए ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल लेकर पहुंचे। वहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। डॉक्टरों ने बताया कि सागर के गले में कांच लगने से नसें कट गई थीं, जिसके कारण उसकी मौत हुई।

### जंगल में मिला पुजारी का शव, हत्या की आशंका

**फरीदाबाद।** सेक्टर-31 थाना क्षेत्र में मंदिर के पास पुजारी का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बीके अस्पताल के शवगृह में भिजवा दिया है। पुलिस ने पुजारी के सिर पर चोट के निशान मिलने की बात कही है। हालांकि, पुलिस अभी मौत के कारणों को लेकर जांच कर रही है। पुलिस के अनुसार, मृतक की पहचान ओम प्रकाश यादव के रूप में हुई है। उनकी उम्र करीब 55 वर्ष बताई जा रही है। बताया गया है कि ओम प्रकाश यादव पिछले करीब एक साल से इसी मंदिर में रहकर पूजा-पाठ करते थे। सोमवार सुबह पुलिस को सूचना मिली कि मंदिर के पुजारी की हत्या हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मंदिर में जाकर तलाशी ली, तो मंदिर के पीछे नहर किनारे जंगल में शव पड़ा हुआ मिला।

# सामूहिक दुष्कर्म के मामले में दो आरोपित गिरफ्तार

**नई दिल्ली,एजेंसी।** दिल्ली पुलिस ने कथित तौर पर सामूहिक दुष्कर्म के मामले में दो आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है। यह घटना 4 अगस्त को ग्रेटर नोएडा से दिल्ली आ रही एक बस में घटी। पुलिस के मुताबिक, पीड़िता मूलरूप से उत्तर प्रदेश के मैनपुरी की रहने वाली है और कक्षा 11 में पढ़ती है। चार अगस्त की रात मां की डांट से नाराज होकर वह घर से निकल गई थी। वह नोएडा सेक्टर-63 में रहने वाले अपने रिश्तेदार के घर जाने के लिए निकली थी। रात करीब नौ बजे बारिश के दौरान वह गलती से परी चौक उतर गई। वहां उसे पता चला कि वह रिश्तेदार के घर से करीब 25 किलोमीटर दूर है। बारिश में वह साधन तलाश रही थी, तभी एक बस उसके पास आकर रुकी। कंडक्टर ने उसे बताया कि बस नोएडा सेक्टर-63 जा रही है और वह उसे वहां उतार देगा। उसकी बात पर भरोसा करके किशोरी बस में सवार हो गई। हालांकि, बस नियमित यात्री सेवा में नहीं थी। ट्रैवल कंपनी के मुताबिक बस में तकनीकी खराबी आने के बाद उसे मरम्मत के लिए सूरजपुर स्थित वर्कशाप भेजा गया था। चालक कुलदीप (39) और कंडक्टर संदीप (26), दोनों कानपुर के रहने वाले हैं, शाम करीब पांच बजे बस को वर्कशाप से लेकर निकले थे।

जांच में पाया गया कि बस सूरजपुर से परी चौक, एडवेंट क्षेत्र और नोएडा सेक्टर-93 होते हुए दिल्ली की तरफ चली गई। इसी दौरान बस में किशोरी के साथ कथित तौर पर दुष्कर्म किया गया। आरोप है कि कंडक्टर ने उसके साथ अश्लील हरकत की और चालक की मिलीभगत से उसका यौन उत्पीड़न किया। विरोध करने पर दोनों ने उसे जान से मारने की धमकी दी। बाद में आरोपी बस को दिल्ली के कश्मीरी गेट क्षेत्र तक ले गए और रिंग रोड के पास किशोरी को उतारकर फरार हो गए। उत्तर जिले की डीसीपी निहारिका भट्ट ने बताया कि किशोरी चार अगस्त की रात कश्मीरी गेट थाने पहुंची थी जहां उसने नोएडा में बस के अंदर उसके साथ दुष्कर्म होने की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने तत्काल उसका चिकित्सकीय परीक्षण कराया और प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की। सीसीटीवी कैमरों की मदद से बस की पहचान कर ली गई और दोनों आरोपितों को उसी दिन उत्तरी दिल्ली के तिमारपुर स्थित पार्किंग से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने बस को भी कब्जे में लेकर फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया है। जांच के दौरान बस के अंदर से किशोरी के बाल के नमूने मिले हैं। बस में लगे सीसीटीवी कैमरे मरम्मत के दौरान चालू नहीं थे। वहीं, स्लीपर सीटों पर कंपनी की ओर से लगाए गए पर्दे थे, जिनसे अंदर की गतिविधियां बाहर से दिखाई नहीं देती थीं। पुलिस करीब 43 किलोमीटर लंबे पूरे रूट के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। यह भी पता लगाया जा रहा है कि इतने लंबे रास्ते में बस कहां-कहां रुकी और बिना नियमित जांच के दिल्ली तक कैसे पहुंची। पुलिस दोनों आरोपितों के आपराधिक इतिहास की भी जांच कर रही है। साथ ही ट्रैवल कंपनी ने चालक और कंडक्टर की नियुक्ति से पहले उनके पृष्ठभूमि सत्यापन की प्रक्रिया पूरी की थी या नहीं, इसकी भी जांच की जा रही है। दोनों आरोपित दो साल से अधिक समय से ट्रैवल कंपनी के साथ काम कर रहे थे। पुलिस के अनुसार घटना की सूचना उसी रात किशोरी के स्वजन को दे दी गई थी। महिला पुलिसकर्मी उसके साथ रहीं और परिजनों के दिल्ली पहुंचने तक उसकी मदद की। बाद में किशोरी को बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया गया, जहां से आदेश मिलने के बाद उसे उसके पिता के सुपुर्द कर दिया गया। पुलिस ने आरोपितों का पोटेंसी टेस्ट भी कराया है। मामले में किसी अन्य व्यक्ति की संलिप्तता है या नहीं, इसकी भी जांच की जा रही है।

# गौतमबुद्ध नगर में बेकाबू हुआ स्वाइन फ्लू

**नोएडा।** राजधानी दिल्ली के बेहद करीब गौतमबुद्ध नगर में एच1एन1 संक्रमण के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। स्वास्थ्य विभाग को 48 घंटे के अंदर स्वाइन फ्लू के 19 और नए केस मिले हैं। इसी के साथ मरीजों की कुल आंकड़ा प्रदेश में सबसे ज्यादा 209 पर पहुंच गई है।

सभी मरीजों की प्राइवेट अस्पतालों में हुई जांच और किसी के अभी तक गंभीर स्थिति में नहीं होने के कारण स्वास्थ्य विभाग के शीर्ष अधिकारी राहत में हैं। सीएमओ के निर्देश पर जनपद के सभी अस्पताल प्रबंधन और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अलर्ट पर हैं। जिला अस्पताल में सोमवार से शुरू हुई फीवर ओवर में पहले दिन 60 मरीजों ने जांच एवं परामर्श का लाभ लिया। पिछले दिनों हुई झमाझम वर्षा के बाद मौसम बदलने से ज्यादातर लोग बुखार,खांसी, जुकाम और सिर दर्द समेत अन्य समस्या से जूझ रहे हैं। जिला अस्पताल में सोमवार सुबह से ही मरीजों की लंबी कतार देखने को मिली। सबसे ज्यादा भीड़ बाल रोग विभाग, नेत्र रोग विभाग, जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग विभाग और बीपी मापने की ओपीडी में देखी गई। प्रबंधन के आंकड़ों के अनुसार, रक्षाबंधन के बाद अस्पताल में 4249 मरीजों ने विभिन्न ओपीडी में चिकित्सकों से जांच एवं परामर्श का लाभ लिया जबकि ओपीडी नंबर-10 फीवर क्लीनिक में सुबह आठ बजे से दोपहर दो बजे तक कुल 60 महिला एवं पुरुष मरीज जांच कराने पहुंचे।

## नोएडा में बेकाबू ट्राला वाहन डिवाइडर तोड़कर कार से टकराया, पिता-पुत्र समेत चार की मौत

**नोएडा।** जेवर थाना क्षेत्र के यमुना एक्सप्रेसवे पर रविवार की देर रात को एक बेकाबू ट्राला क्रैश बीम बैरियर तोड़ते हुए दूसरी तरफ से जा रही कार को टक्कर मार दिया। घटना में कार सवार पिता-पुत्र समेत चार लोगों की मौत हो गई है। हादसे की वजह से यमुना एक्सप्रेस-वे पर चार किलोमीटर लंबा जाम लग गया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने क्रेन और कटर की सहायता से कार के अंदर फंसे शवों को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अपर पुलिस उपायुक्त संतोष कुमार ने सोमवार को जानकारी देते हुए बताया कि रविवार देर रात को यमुना एक्सप्रेसवे पर एक ट्राला दिल्ली के रास्ते आगरा की ओर जा रहा था।

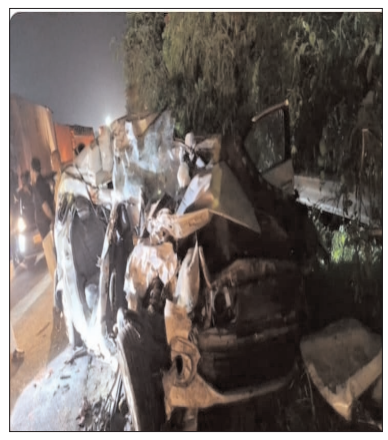

यमुना एक्सप्रेसवे के 36 किमी सबौता इंटरचेंज के पास वह अनियंत्रित हो गया और क्रैश बीम बैरियर को तोड़ते हुए दूसरी तरफ जा पहुंचा। वहीं, आगरा से दिल्ली की तरफ आ रही बलेनो कार को ट्राला ने टक्कर मारते हुए उसे घसीटते हुए आगे बढ़ा। इसी बीच एक मोटरसाइकिल और एक छोटा हाथी भी टकरा गए। इस घटना में कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई, और उसमें सवार चार लोग अंदर ही फंस गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने क्रेन और कटर की सहायता से कार में फंसे लोगों को बाहर निकालकर अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां पर डॉक्टरों ने चारों लोगों को मृत घोषित कर दिया है। इनकी पहचान महाराजगंज निवासी विकास गुप्ता, डीएन पांडेय व उनके पुत्र आयुष पांडेय तथा धौलपुर राजस्थान निवासी चालक विजय सिंह निवासी के रूप में हुई है। घटना के बाद हाइवे पर वाहनों का लंबा जाम लग गया था। पुलिस ने क्रेन की मदद से दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को सड़क से हटाकर जाम खुलवाया गया।

## गाजियाबाद के कनावनी में किसानों की महापंचायत, आंदोलन तेज करने का एलान

**अशोक कुमार, सद्भावना टुडे**

**साहिबाबाद।** गाजियाबाद के कनावनी गांव में 17 दिन से धरना दे रहे किसानों ने रविवार को महापंचायत की। इसमें नौ गांवों दुजाना, अच्छेजा, बड़पुरा, खैरपुर गुर्जर, कूड़ी खेड़ा, तिलपता, अकूदपुर, मोहियापुर और रसूलपुर नवादा के किसान शामिल हुए। मुआवजे की मांग लेकर महापंचायत में किसानों द्वारा आगे आंदोलन तेज करने का निर्णय लिया। किसान प्रवीण नागर का कहना है कि प्रशासन और जीडीए के अधिकारियों से कई दौर की बातचीत के बाद कोई हल नहीं निकल रहा है इसलिए आगे भी धरना जारी रहेगा। आगे आंदोलन को और तेज किया जाएगा। धरने में नेताओं और मंत्रियों को बुलाया जाएगा। उनके सामने अपनी बात रखी जाएगी।

महापंचायत की अध्यक्षता अर्थला के वीरपाल डबास और मंच का संचालन कैलाश नागर ने किया। अन्य गांवों से पहुंचे किसानों ने अपना समर्थन दिया। महापंचायत में मौजूद किसानों और ग्रामीणों ने कहा कि जब तक कनावनी गांव के किसानों की मांगों को पूरा नहीं किया जाता, तब तक संघर्ष जारी रहेगा। ग्रामीणों ने कहा कि कनावनी के किसानों की लड़ाई अब केवल कनावनी तक सीमित नहीं है। आसपास के सभी गांव इस संघर्ष में कनावनी के किसानों के साथ मजबूती से खड़े हैं और आगे की लड़ाई में भी हर संभव सहयोग और समर्थन दिया जाएगा। महापंचायत में करमवीर नागर, ज्ञानेंद्र नागर, सतपाल यादव, सुमित त्यागी, पृथ्वीराज कसाना, ओमप्रकाश नागर, महेंद्र नागर, रघुनाथ सिंह आदि मौजूद रहे।

## बागपत कलेक्ट्रेट में किसानों का धरना, 13 सितंबर से आंदोलन की चेतावनी

**बागपत।** उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में किसानों की विभिन्न मांगों को लेकर किसान अधिकार आंदोलन ने सोमवार को कलेक्ट्रेट पर धरना-प्रदर्शन किया। आंदोलनकारियों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि कई बार समस्याओं से अवगत कराने के बावजूद किसानों की शिकायतों पर कोई ठोस समाधान नहीं हो रहा है। बागपत कलेक्ट्रेट पर 31 अगस्त को दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक किसानों ने सांकेतिक धरना देकर अपनी आवाज उठाई।

किसानों का कहना है कि ग्रामीण क्षेत्र के किसान आर्थिक और सामाजिक समस्याओं से जूझ रहे हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से अपेक्षित कार्रवाई नहीं हो रही। किसानों ने ज्ञापन में कई अहम मांगें रखीं, जिनमें किसानों को पूर्ण रूप से कर्जमुक्त किया जाए और छोटी जोत वालों की न्यूनतम आय सुनिश्चित की जाए, घरेलू बिजली के बकाये माफ कर मुफ्त बिजली देने, गन्ने का मूल्य चीनी के भाव के अनुपात में तय करने, गन्ना प्रजातियों के मूल्य अंतर को सीमित करने, गन्ना तुलाई में धांधली और कटौती पर रोक लगाने, आवारा गोवंश की समस्या के समाधान करने, गोपालकों को आर्थिक सहायता देने, भूमि अधिग्रहण में उचित मुआवजा देने, शिक्षा, चिकित्सा और सुरक्षा की बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग रखी गयी। ज्ञापन में समस्या समाधान के लिए किसान नेता नरेंद्र राणा ने 12 सितंबर 2026 तक का समय दिया है। चेतावनी दी गई है कि यदि तब तक मांगों का समाधान नहीं हुआ, तो 13 सितंबर को काठा देवी मंदिर पर खुली पंचायत कर बड़ा आंदोलन शुरू किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। इस मौके पर काफी संख्या में किसान मौजूद रहे।

### गाजियाबाद में जीएसटी फर्जीवाड़े पर पुलिस का शिकंजा

**गाजियाबाद।** गाजियाबाद में जीएसटी से जुड़े फर्जीवाड़े के मामलों में प्रभावी कार्रवाई के लिए पुलिस ने थानास्तर पर विशेष जांच टीम (एसआइटी) का गठन किया है। नगर जोन में कोतवाली और ट्रांस हिंडन जोन में इंदिरापुरम थाने में एसआइटी बनाई गई है। दोनों टीमों को करीब 10-10 मुकदमे जांच के लिए सौंपे गए हैं। वहीं, क्राइम ब्रांच में पहले से गठित एसआइटी अलग से 15 मामलों की जांच कर रही है। इस तरह जीएसटी फर्जीवाड़े के मामलों की जांच के लिए तीन टीमें सक्रिय हो गई हैं। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, जिले में पिछले एक वर्ष में जीएसटी फर्जीवाड़े से जुड़े 30 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हुए हैं। इनमें से अधिकांश मामलों में पुलिस अभी तक आरोपितों की गिरफ्तारी नहीं कर पाई है। जांच में अपेक्षित प्रगति नहीं होने के कारण अब थानास्तर पर अलग से एसआइटी बनाकर मामलों की निगरानी और विवेचना कराई जा रही है। जीएसटी फर्जीवाड़े के इन मामलों में करीब 10 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी सामने आई है।

## गाजियाबाद में मामूली विवाद बना खूनी संघर्ष का कारण, एक किसान की मौत

**मुरादनगर।** थाना क्षेत्र के कन्नौजा गांव में मामूली बात को लेकर विवाद में रविवार देर शाम दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हो गया। दोनों पक्षों के लोगों ने एक दूसरे पर लाठी डंडे और धारदार हथियारों से हमला किया। इसमें किसान की मौत हो गई। इसके अलावा दोनों पक्षों के पांच लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। थाना क्षेत्र के कन्नौजा गांव में देवेंद्र शर्मा (57) अपने परिवार के साथ रहते थे। रविवार शाम को देवेंद्र अपने भतीजे अंकित के साथ किसी काम से जा रहे थे। घर से निकलते ही उनके भतीजे और गली में रहने वाले युवक के बीच कहासुनी हो गई। दूसरे पक्ष का युवक उसके नाम के आगे भैया न लगाने पर गाली देने लगा।

इस बात पर दोनों पक्षों के लोग आमने-सामने आ गए। दोनों पक्षों के लोगों ने एक-दूसरे पर लात-घूसों और लाठी-डंडों से हमला किया। संघर्ष के चलते गली में अफरातफरी मच गई। इस बीच दूसरे पक्ष के लोग गांव के एक हिस्ट्रीशीटर और उसके साथियों को बुला लिया। हिस्ट्रीशीटर ने मौके पर पहुंचे ही धारदार हथियारों से हमला शुरु कर दिया, जिसके चलते देवेंद्र गंभीर रूप से घायल हो गए। स्वजन ने देवेंद्र को सीएचसी में भर्ती कराया, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गए। इसके अलावा अंकित और उसका भाई रिशांत भी गंभीर रूप से घायल हुए है। दोनों का अस्पताल में उपचार चल रहा है। संघर्ष के बाद से आरोपित हिस्ट्रीशीटर और उसके साथी फरार चल रहे हैं। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। फोरेंसिक टीम ने जरूरी साक्ष्य मौके से जुटाए। डीसीपी ग्रामीण समेत पुलिस के आलाअधिकारियों ने घटनास्थल पर निरीक्षण किया। खबर लिखे जाने पर कोई शिकायत थाने में नहीं दी गई है। गांव में तनाव को देखते हुए भारी पुलिस बल मौके पर तैनात कर दिया गया है। एसीपी मसूरी सुनील कुमार ने बताया कि मामूली विवाद के चलते कन्नौजा गांव में दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हुआ। संघर्ष में गंभीर रूप से घायल हुए किसान की मौत हो गई। पुलिस टीम मौके पर जाकर जांच कर रही है।

## नोएडा में मानसिक तनाव ले रहा जान, तीन दिनों में छह महिलाओं समेत नौ लोगों ने की आत्महत्या

**नोएडा,एजेंसी।** औद्योगिक नगरी नोएडा में लोगों में मानसिक तनाव बढ़ता जा रहा है। यही कारण है कि बीते तीन दिनों में यहां अलग -अलग कारणों से छह महिलाओं समेत नौ लोगों ने आत्महत्या कर ली। चिकित्सकों के अनुसार नोएडा महानगर के लोग आधुनिक जीवन शैली की भाग दौड़, बेरोजगारी, नौकरी की तलाश, पढ़ाई का तनाव, प्रेम में विफलता और एकाकीपन के चलते अवसाद ग्रसित हो रहे हैं। पुलिस आयुक्त लक्ष्मी सिंह के मीडिया प्रभारी उमेश नैथानी ने सोमवार को बताया कि थाना सेक्टर 126 क्षेत्र के सेक्टर 125 स्थित एक यूनिवर्सिटी में काम करने वाले राजकुमार (46) पुत्र राममूर्ति सिंह मूल निवासी हरि नगर दिल्ली ने यूनिवर्सिटी कैंपस में बने लॉन्ड्री रूम में जाकर कुंडे फंदा लगाकर बीती रात को आत्महत्या कर लिया। उन्होंने बताया कि मौके पर पहुंची थाना सेक्टर 126 पुलिस में शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

मीडिया प्रभारी ने बताया कि थाना नॉलेज पार्क क्षेत्र में रहने वाली नर्सिंग की छात्रा निशिका (23) पुत्री हनुमान प्रसाद ने अपने हास्टल मे पंखे से फंदा लगाकर आत्महत्या कर लिया। उन्होंने बताया कि घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। उन्होंने बताया कि वह शारदा यूनिवर्सिटी से नर्सिंग की पढ़ाई कर रही थी। जांच में पुलिस को पता चला है कि वह एक युवक से शादी करना चाह रही थी। उसके परिजन कह रहे थे कि पढ़ाई पूरी करने के बाद शादी करो। इसी बात से वह तनाव में थी। मीडिया प्रभारी ने बताया कि थाना ईकोटेक-तीन क्षेत्र के कुलेसरा हिंडन बैराज से संजना (19) नामक युवती ने बीती रात को छलांग लगाकर आत्महत्या कर लिया। उनके अनुसार वह एक युवक से प्रेम करती थी। उसके घर वाले दहेज की मांग कर रहे थे। प्रेमी ने दहेज की मांग पूरी न होने पर शादी से इनकार कर दिया था। उन्होंने बताया की युवती के शव की तलाश की जा रही है। आज सुबह तक उसका शव नहीं मिला है। एनडीआरएफ और पुलिस शव की तलाश में जुटी है। उन्होंने बताया कि थाना फेस -तीन क्षेत्र में रहने वाली ज्योति पांडा (30) पत्नी सुदेश कुमार ने रविवार की रात को अपने घर पर पंखे से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। उन्होंने बताया कि महिला की अभी 2 वर्ष पूर्व शादी हुई थी। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंचे अपर पुलिस उपायुक्त ग्रेटर नोएडा की मौजूदगी में शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। उन्होंने बताया कि थाना फेस -3 पुलिस मामले की जांच कर रही है। उन्होंने बताया कि एक अन्य मामले में थाना फेस- तीन क्षेत्र के ग्राम गढ़ी चौखंडी में रहने वाली अंकिता (19) पुत्री तेजराम ने 29 अगस्त की रात को अपने घर पर पंखे से फंदा लगाकर आत्महत्या कर लिया। उन्होंने बताया कि मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

उन्होंने बताया कि थाना सेक्टर 63 क्षेत्र के बहलोल पुर गांव में रहने वाली तनु (19) पुत्री विजेंद्र सिंह ने 29 अगस्त की देर रात को अपने घर पर पंखे से फंदा लगाकर आत्महत्या कर लिया। उन्होंने बताया कि पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। उन्होंने बताया कि थाना दादरी क्षेत्र में रहने वाले विनय (29) पुत्र नेपाल ने 29 अगस्त को अपने घर पर पंखे से फंदा लगाकर आत्महत्या कर लिया। उन्होंने बताया कि थाना दादरी पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इसी प्रकार थाना सेक्टर 113 क्षेत्र में रहने वाले रोहित (31) पुत्र सुखबीर ने मानसिक तनाव के चलते अपने घर पर 28 अगस्त को पंखे से फंदा लगाकर आत्महत्या कर लिया। उन्होंने बताया कि थाना सेक्टर 113 पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मीडिया प्रभारी ने बताया कि थाना दनकौर क्षेत्र में रहने वाली खुशबू पत्नी प्रवीण उम्र 35 वर्ष ने 28 अगस्त को मानसिक तनाव के चलते अपने घर पर जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर लिया। उन्होंने बताया कि थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस बाबत बात करने पर गौतम बुद्ध नगर के वरिष्ठ चिकित्सक और आईएमए के पूर्व अध्यक्ष डॉ एन के शर्मा ने बताया कि लोग आधुनिकता भरी जिंदगी में इतने व्यस्त हो गए हैं कि वे अपनी मन की बात किसी से खुलकर नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रानिक सर्विलांस और सोशल मीडिया ने अपने लोगों को एक दूसरे से काफी दूर कर दिया है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा बेरोजगारी, पढ़ाई की टेंशन, प्रेम में विफलता, जैसे कुछ ऐसे विषय हैं, जिसके चलते बच्चे आत्मघाती कदम उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज की पीढ़ी में सहनशक्ति की काफी कमी होती जा रही है। बच्चे छोटी-छोटी बातों पर उग्र और नाराज हो जा रहे हैं। यह भी आत्महत्या का एक कारण है।

# बिहार के 'सहयोग मॉडल' से बाकि राज्यों को भी सीखने की जरूरत

**संजीव कुमार मिश्र**

क्या किसी सरकारी स्कूल या हॉस्टल में गंदा पानी, खराब खाना या बिजली की किल्लत जैसी रोजमर्रा की समस्याओं का समाधान 30 दिन के भीतर पाना संभव है?...जहां देश के अधिकांश राज्यों में छात्र ऐसी बुनियादी सुविधाओं के लिए महीनों प्रशासनिक चक्कर काटने या सड़कों पर उतरने को मजबूर होते हैं, वहीं बिहार सरकार ने एक पारदर्शी ऑनलाइन व्यवस्था से इस धारणा को बदलने की कोशिश की है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी द्वारा शुरू की गई इस नई पहल ने छात्र शिकायतों के निपटारे का एक ऐसा मॉडल पेश किया है, जिसकी गूंज अब देश भर में सुनाई दे रही है। छात्रों की शिकायतें अक्सर लंबे समय तक अनसुलझी रहती हैं, इसकी बड़ी वजह प्रशासनिक प्रक्रिया की जटिलता है। किसी छात्र को हॉस्टल की सफाई, भोजन की गुणवत्ता, बिजली-पानी या फीस से जुड़ी दिक्कत होने पर पहले वार्डन, फिर प्रिंसिपल और जरूरत पड़ने पर जिला शिक्षा कार्यालय तक जाना पड़ता है। इस प्रक्रिया में न तो कोई तय समयसीमा होती है और न ही स्पष्ट जवाबदेही तय होती है, जिस वजह से छोटी शिकायतें भी हफ्तों-महीनों तक लंबित रह जाती हैं।

बिहार सरकार के विद्यार्थी सहयोग पोर्टल की खासियत यह है कि शिकायत दर्ज कराने के लिए दो अलग कैटेगरी बनाई गई हैं — पहली, शैक्षणिक संस्थान यानी विद्यालय, महाविद्यालय या विश्वविद्यालय से संबंधित विद्यार्थियों के लिए, और दूसरी, छात्रावास यानी हॉस्टल में रहने वाले विद्यार्थियों के लिए। पोर्टल के होमपेज पर ही यह दोनों विकल्प दिए गए हैं, जिससे छात्र सही कैटेगरी चुनकर सीधे संबंधित फॉर्म तक पहुंच जाता है। कैटेगरी चुनने के बाद छात्र के सामने एक सीधा-सादा फॉर्म खुलता है, जिसमें नाम, लिंग, पिता का नाम, जन्म तिथि और मोबाइल नंबर जैसी बुनियादी जानकारी भरनी होती है। ईमेल आईडी को वैकल्पिक रखा गया है, ताकि जिन छात्रों के पास ईमेल नहीं है वे भी शिकायत दर्ज करा सकें, जबकि मोबाइल नंबर को ओटीपी से वेरिफाई किया जाता है ताकि हर शिकायत असली छात्र की ओर से ही दर्ज हो। पोर्टल पर छात्रों के लिए तीन सुविधाएं दी गई हैं। शिकायत दर्ज कराने का विकल्प हॉस्टल सुविधाओं, भोजन, स्वच्छता, सुरक्षा और बिजली से जुड़ी समस्याओं के लिए है। इसके अलावा छात्र व्यवस्था सुधारने से जुड़े अपने सुझाव भी साझा कर सकते हैं, और सबसे अहम बात यह कि एक बार शिकायत दर्ज करने के बाद छात्र उसकी मौजूदा स्थिति और उस पर हुई कार्रवाई को ट्रैक भी कर सकता है। पोर्टल पर सबसे ज्यादा दर्ज होने वाली शिकायतों को भोजन, पेयजल, बिजली, शौचालय-सफाई, सुरक्षा, बुनियादी ढांचे और इंटरनेट जैसी कैटेगरी में पहले से बांटा गया है, जिससे शिकायत सीधे संबंधित विभाग तक पहुंचती है और निपटारे में देरी नहीं होती।

पोर्टल पर दर्ज हर शिकायत का 30 दिनों के भीतर निपटारा सुनिश्चित करने की व्यवस्था की गई है। समाधान के बाद संबंधित छात्र को लिखित रूप से इसकी सूचना भी दी जाती है, ताकि यह साफ रहे कि उसकी शिकायत पर वाकई कार्रवाई हुई है। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि शिकायतकर्ता छात्र-छात्राओं की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी, जिससे छात्र बिना किसी डर के अपनी बात रख सकें। जिन छात्रों के पास ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराने की सुविधा नहीं है, उनके लिए टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 1100 भी उपलब्ध कराया गया है। पोर्टल का मकसद छात्रों की शैक्षणिक, परीक्षा, छात्रावास, छात्रवृत्ति और अन्य संस्थागत समस्याओं का पारदर्शी और जवाबदेह तरीके से समाधान करना है। सरकारी पोर्टल और हेल्पलाइन की घोषणाएं आमतौर पर होती रहती हैं, लेकिन इनमें से ज्यादातर व्यवहार में उतनी असरदार साबित नहीं होतीं। लेकिन बिहार सरकार की अब तक की कोशिशों को देखें तो ऐसा लगता है कि सरकार गंभीरता से छात्रों की समस्याओं को सुनने की ओर अग्रसर है। इस पोर्टल की खासियत है कि इसमें एक जवाबदेही तंत्र भी जोड़ा गया है — तय समयसीमा में शिकायत का समाधान न होने पर संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई का भी प्रावधान रखा गया है, जिससे यह सिर्फ कागजी व्यवस्था बनकर नहीं रह जाती। पोर्टल के साथ-साथ सरकार ने हर महीने सहयोग शिविर आयोजित करने की व्यवस्था भी बनाई है, जिनमें मंत्री, विधायक, सांसद और संबंधित अधिकारी सीधे स्कूल-कॉलेजों में जाकर छात्रों से बातचीत करेंगे। इन शिविरों में मिलने वाली शिकायतों और सुझावों को भी उसी पोर्टल पर दर्ज कर ट्रैक किया जाता है, जिससे पूरा सिस्टम एक जगह जुड़ा रहता है। यह व्यवस्था खासकर उन इलाकों में उपयोगी मानी जा रही है, जहां छात्र ऑनलाइन माध्यम के बजाय सीधी बातचीत में ज्यादा सहज महसूस करते हैं।

जिन राज्यों में छात्र आंदोलन और कैंपस में असंतोष की घटनाएं सामने आती रही हैं, उनके लिए बिहार का यह मॉडल कुछ स्पष्ट संकेत देता है। शिकायत निवारण तंत्र तभी प्रभावी होता है जब उसमें तय समयसीमा और जवाबदेही दोनों शामिल हों। शिकायत और छात्रावास की समस्याओं को अलग-अलग कैटेगरी में बांटने और फॉर्म को आसान रखने से समाधान की रफ्तार तेज होती है, जबकि स्टेटस ट्रैक करने की सुविधा से छात्रों को भरोसा रहता है कि उनकी बात पर वाकई काम हो रहा है। साथ ही, सिर्फ डिजिटल पोर्टल पर निर्भर रहने के बजाय हेल्पलाइन और जमीनी शिविर जैसे विकल्प भी जरूरी हैं, ताकि हर वर्ग का छात्र इस व्यवस्था से जुड़ सके। शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए बड़ी घोषणाओं के साथ-साथ जमीनी क्रियान्वयन भी उतना ही जरूरी है। बिहार का अनुभव यह दिखाता है कि अगर शिकायत निवारण तंत्र में पारदर्शिता, आसान प्रोसेस और जवाबदेही तय की जाए, तो नतीजे भी सामने आते हैं। अब देखना यह होगा कि अन्य राज्य इस मॉडल से कितना सीखते हैं और अपने यहां इसे किस रूप में लागू करते हैं।

**अमेरिका में भारतीय मूल के नागरिकों की औसत वार्षिक आय स्थानीय औसत आय की तुलना में काफी अधिक बताई जाती है। सिलिकॉन वैली से लेकर यूरोपीय देशों तक भारतीय प्रतिभा की उपस्थिति आज स्पष्ट दिखाई देती है। प्रवासी भारतीयों द्वारा भारत भेजी जाने वाली धनराशि भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है। पिछले वर्ष भारतीय मूल के नागरिकों ने लगभग 14,000 करोड़ अमेरिकी डॉलर भारत भेजे। यह दुनिया में किसी देश को प्राप्त होने वाली सबसे बड़ी रेमिटेंस राशि के रूप में सामने आती है। कौशल बनेगा वैश्विक रोजगार का पासपोर्टदेश से प्रतिवर्ष लाखों लोग रोजगार और व्यवसाय के अवसरों की तलाश में विदेशों का रुख कर रहे हैं। जापान, इजराइल, वियतनाम, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा, फ्रांस और जर्मनी जैसे देशों में भारतीय कुशल कामगारों की मांग बढ़ रही है। अनुमान है कि वर्ष 2030 तक इन देशों में करोड़ों कुशल कामगारों की कमी उत्पन्न हो सकती है। भारत सरकार ने इस वैश्विक अवसर को ध्यान में रखते हुए युवाओं के कौशल विकास के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, उड़ान, संकल्प, प्रशिक्षु अधिनियम के अंतर्गत प्रशिक्षण, महिलाओं के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम, प्रधानमंत्री कौशल केंद्र, कौशल ऋण योजना और भारतीय कौशल संस्थान जैसी अनेक पहलें शुरू की हैं। भारत हर वर्ष 25 लाख से अधिक कुशल कामगार तैयार कर रहा है।**

# युवा शक्ति के हाथों फिर विश्वगुरु बनेगा भारत

**प्रहलाद सबनानी**

भारत आज दुनिया के सबसे युवा देशों में अपनी पहचान बना चुका है। विश्व के अनेक विकसित देशों में जन्म दर लगातार घट रही है, औसत आयु बढ़ रही है और कार्यशील जनसंख्या का अनुपात कम हो रहा है। ऐसे समय में भारत के पास विशाल युवा शक्ति मौजूद है। यही युवा शक्ति आने वाले दशकों में भारत की अर्थव्यवस्था, तकनीक, उद्योग, विज्ञान और वैश्विक प्रभाव की दिशा तय करेगी। भारत की लगभग 68 प्रतिशत आबादी 15 से 64 वर्ष आयु वर्ग में है। 26 प्रतिशत आबादी 10 से 24 वर्ष के बीच है। 50 प्रतिशत से अधिक भारतीयों की आयु 25 वर्ष से कम है, जबकि 65 प्रतिशत से अधिक आबादी 35 वर्ष से कम आयु की है। भारतीय नागरिकों की औसत आयु लगभग 28.4 वर्ष है। यह स्थिति भारत को एक बड़े जनसांख्यिकी लाभांश का अवसर देती है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के अनुसार जनसांख्यिकी लाभांश उस आर्थिक क्षमता को कहा जाता है, जो आबादी की आयु संरचना में बदलाव से उत्पन्न होती है। जब कार्यशील आयु वर्ग की आबादी गैर-कार्यशील आयु वर्ग से अधिक हो जाती है, तब देश के सामने आर्थिक प्रगति का बड़ा अवसर पैदा होता है। भारत इस अवसर की खिड़की में प्रवेश कर चुका है और आगामी दशकों तक इसका लाभ उठा सकता है। दुनिया की जरूरत अनुमान है कि वर्ष 2030 तक भारत में कार्यशील आयु वर्ग के नागरिकों की संख्या 104 करोड़ तक पहुंच जाएगी। इसी अवधि में भारत का निर्भरता अनुपात अपने इतिहास के न्यूनतम स्तर 31.2 प्रतिशत तक पहुंचने का अनुमान है। आगामी दशक में वैश्विक कार्यबल में होने वाली वृद्धि में भारत की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रहने वाली है। यूरोप, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कई अन्य विकसित देशों के सामने वृद्ध होती आबादी तथा कुशल कामगारों की कमी बड़ी चुनौती बन रही है। स्वास्थ्य सेवा, इंजीनियरिंग, विज्ञान, अनुसंधान, तकनीक, निर्माण और प्रशासन जैसे क्षेत्रों में भारतीय प्रतिभाओं की मांग तेजी से बढ़ी है।

भारतीय मूल के लगभग चार करोड़ लोग आज दुनिया के विभिन्न देशों में रह रहे हैं। वे अपनी कर्मभूमि के देशों में योगदान देते हुए भारत की संस्कृति, कार्यशीलता और उद्यमशीलता का परिचय भी देते हैं। अमेरिका में भारतीय मूल के नागरिकों की औसत वार्षिक आय स्थानीय औसत आय की तुलना में काफी अधिक बताई जाती है। सिलिकॉन वैली से लेकर यूरोपीय देशों तक भारतीय प्रतिभा की उपस्थिति आज स्पष्ट दिखाई देती है। प्रवासी भारतीयों द्वारा भारत भेजी जाने वाली धनराशि भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है। पिछले वर्ष भारतीय मूल के नागरिकों ने लगभग 14,000 करोड़ अमेरिकी डॉलर भारत भेजे। यह दुनिया में किसी देश को प्राप्त होने वाली सबसे बड़ी रेमिटेंस राशि के रूप में सामने आती है। कौशल बनेगा वैश्विक रोजगार का पासपोर्टदेश से प्रतिवर्ष लाखों लोग रोजगार और व्यवसाय के अवसरों की तलाश में विदेशों का रुख कर रहे हैं। जापान, इजराइल, वियतनाम, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा, फ्रांस और जर्मनी जैसे देशों में भारतीय कुशल कामगारों की मांग बढ़ रही है। अनुमान है कि वर्ष 2030 तक इन देशों में करोड़ों कुशल कामगारों की कमी उत्पन्न हो सकती है। भारत सरकार ने इस वैश्विक अवसर को ध्यान में रखते हुए युवाओं के कौशल विकास के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, उड़ान, संकल्प, प्रशिक्षु अधिनियम के अंतर्गत प्रशिक्षण, महिलाओं के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम, प्रधानमंत्री कौशल केंद्र, कौशल ऋण योजना और भारतीय कौशल संस्थान जैसी अनेक पहलें शुरू की हैं। भारत हर वर्ष 25 लाख से अधिक कुशल कामगार तैयार कर रहा है। इसके बावजूद बड़ी संख्या में युवा ऐसे हैं जो शिक्षा, प्रशिक्षण या रोजगार से जुड़े हुए नहीं हैं। एक हालिया प्रतिवेदन के अनुसार लगभग आठ करोड़ युवा आज अध्ययन, कौशल विकास या रोजगार की मुख्यधारा से बाहर हैं। यह स्थिति भारत के सामने मौजूद अवसर को बड़ी चुनौती में भी बदल सकती है। युवा शक्ति की संख्या अपने आप आर्थिक शक्ति में परिवर्तित नहीं होती। इसके लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, डिजिटल दक्षता, स्वास्थ्य, अनुशासन, उद्यमशीलता और रोजगार के अवसरों का मजबूत तंत्र आवश्यक है।

विदेशों से समझौते और नए रास्तेभारत विभिन्न देशों के साथ प्रवास एवं गतिशीलता साझेदारी समझौतों के माध्यम से युवाओं के लिए अंतरराष्ट्रीय रोजगार के रास्ते सुगम बना रहा है। जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ हुए समझौतों का उद्देश्य भारतीय कामगारों और पेशेवरों की आवाजाही को अधिक व्यवस्थित बनाना है। भारत विभिन्न देशों के साथ पारस्परिक मान्यता समझौतों पर भी काम कर रहा है। इससे भारतीय युवाओं की शिक्षा और कौशल को विदेशी संस्थानों में मान्यता मिलने का रास्ता आसान होगा। विदेश जाकर काम करने वाले भारतीयों की सामाजिक सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर भी समझौते महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इस पूरी प्रक्रिया का व्यापक उद्देश्य यही है कि भारतीय युवा वैश्विक श्रम बाजार में सम्मानजनक अवसर प्राप्त करें और भारत अपनी विशाल मानव संसाधन शक्ति को आर्थिक सामर्थ्य में बदल सके। विदेश जाएं, सीखें और भारत लौटकर रोजगार पैदा करेंभारत की युवा शक्ति का महत्व विदेशों में रोजगार प्राप्त करने तक सीमित नहीं होना चाहिए। विदेशों में काम करने वाले भारतीय नई तकनीक, प्रबंधन पद्धति, उत्पादन तकनीक और वैश्विक बाजार की समझ हासिल कर भारत लौट सकते हैं। वे अपने अनुभव और पूंजी के आधार पर देश में नए व्यवसाय स्थापित कर सकते हैं। यही प्रक्रिया भारत में रोजगार के नए अवसर पैदा कर सकती है। इससे उत्पादन बढ़ेगा, निर्यात को गति मिलेगी और भारतीय उद्योग वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में अपनी हिस्सेदारी बढ़ा सकेंगे। भारत के लिए आज युवा वर्ग एक अमूल्य राष्ट्रीय संपत्ति है। इसकी शक्ति को सही दिशा देना आने वाले वर्षों की सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में शामिल होना चाहिए। युवा ऊर्जा को अराजकता नहीं, राष्ट्र निर्माण चाहिएहाल में दिल्ली के जंतर-मंतर पर जेन-जी युवाओं से जुड़े आंदोलन ने युवा शक्ति की दिशा पर भी चर्चा को जन्म दिया। किसी भी लोकतांत्रिक समाज में युवाओं को अपनी बात रखने और असहमति व्यक्त करने का अधिकार है। साथ ही सार्वजनिक विमर्श की भाषा, सामाजिक मर्यादा और भारतीय सांस्कृतिक संस्कारों का ध्यान रखना भी आवश्यक है। भारत जिस समय वैश्विक नेतृत्व की ओर बढ़ रहा है, उस समय युवा ऊर्जा को रचनात्मक दिशा देना अत्यंत महत्वपूर्ण है। असंतोष को ज्ञान, संवाद, नवाचार, उद्यम और सामाजिक परिवर्तन की शक्ति में बदलना होगा। देश के युवाओं के सामने आज रोजगार की तलाश के साथ राष्ट्र निर्माण का भी बड़ा अवसर है। विश्वगुरु बनने की राह युवा शक्ति से होकर जाएगीभारत ने लंबे ऐतिहासिक संघर्ष के बाद आर्थिक और सामाजिक पुनर्निर्माण की यात्रा तय की है। कभी भारत विश्व व्यापार में महत्वपूर्ण स्थान रखता था। वस्त्र, मसाले, इस्पात और अनेक उत्पादों के कारण भारत को समृद्ध देश के रूप में देखा जाता था। औपनिवेशिक काल में भारत की आर्थिक शक्ति को भारी क्षति पहुंची। स्वतंत्रता के बाद भी लंबे समय तक आर्थिक विकास की गति अपेक्षाकृत धीमी रही। 1991 के आर्थिक सुधारों और उसके बाद विभिन्न चरणों में हुए आर्थिक बदलावों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को नई गति दी। वर्ष 2014 के बाद आर्थिक सुधारों, बुनियादी ढांचे के विस्तार, डिजिटल अर्थव्यवस्था, विनिर्माण और उद्यमिता पर बढ़े जोर ने भारत के विकास को नई दिशा दी है। आज भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था में तेजी से अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहा है। इस यात्रा को स्थायी और व्यापक बनाने में युवा शक्ति निर्णायक भूमिका निभा सकती है।

## विचार

# नेपाल की त्रासदी से भारत को सबक लेने की जरूरत

**ललित गर्ग**

नेपाल में 26 अगस्त 2026 को आई विनाशकारी बाढ़ और हिमस्खलन ने एक बार फिर यह कठोर सत्य सामने ला दिया है कि प्रकृति के साथ खिलवाड़ और पहाड़ों की संवेदनशीलता की अनदेखी मानव सभ्यता के लिए कितनी भारी पड़ सकती है। भोटेकोशी नदी तंत्र में ग्लेशियर के बड़े हिस्से के टूटने, बर्फ-पत्थरों के विशाल मलबे के नीचे आने और नदी के प्रवाह में अस्थायी अवरोध बनने के बाद अचानक बाढ़ का जो रौद्र एवं भयावह रूप सामने आया, उसने नेपाल और चीन के तिब्बती क्षेत्र में भारी तबाही मचाई। 29 अगस्त तक उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार नेपाल में 579 और तिब्बत में 5 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है तथा लगभग 2,482 लोग लापता बताए जा रहे हैं। हजारों लोगों को बचाया गया है, लेकिन दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों और लगातार बने नए खतरे के कारण राहत एवं बचाव कार्य अभी भी चुनौतीपूर्ण हैं। यह घटना केवल नेपाल की प्राकृतिक त्रासदी नहीं है, बल्कि पूरे हिमालयी क्षेत्र के लिए भविष्य का भयावह संकेत है। प्रारंभिक वैज्ञानिक आकलन बताते हैं कि ग्लेशियर का हिस्सा टूटकर नीचे गिरा, जिससे बर्फ, चट्टान, मिट्टी और मलबे का विशाल प्रवाह पैदा हुआ। इसने नदी के प्रवाह को अवरुद्ध किया और बाद में जमा पानी तथा मलबे के दबाव से अचानक विनाशकारी बाढ़ आई। विशेषज्ञों के अनुसार ऐसे घटनाक्रम को केवल सामान्य बाढ़ कहना भूल होगी, यह ग्लेशियर, भूस्खलन, मलबा-प्रवाह और नदी-बाढ़ जैसे अनेक खतरों के एक साथ सक्रिय होने वाली 'बहु-आपदा' का उदाहरण है। इस त्रासदी का सबसे बड़ा संदेश जलवायु परिवर्तन से जुड़ा है। हिमालय केवल बर्फ से ढकी पर्वतमाला नहीं, बल्कि एशिया की जल-सुरक्षा का आधार है। तापमान बढ़ने के साथ ग्लेशियर तेजी से पीछे हट रहे हैं और अनेक नई ग्लेशियर झीलें बन रही हैं। इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट के अनुसार हिंदूकुश हिमालय क्षेत्र में लगभग 25,000 ग्लेशियर झीलें हैं और बढ़ता तापमान ग्लेशियर झीलों के फटने यानी (जीएलओएफ) के जोखिम को बढ़ा रहा है। नेपाल में 1920 के दशक से अब तक 90 से अधिक ग्लेशियर झील विस्फोट बाढ़ दर्ज की जा चुकी हैं। इसलिए यह मान लेना उचित नहीं होगा कि नेपाल की घटना का एकमात्र कारण ग्लोबल वार्मिंग ही है। भूकंपीय गतिविधियां, भूगर्भीय अस्थिरता, अत्यधिक वर्षा, हिमस्खलन और प्राकृतिक ढलानों की कमजोरी भी महत्वपूर्ण कारक हैं। लेकिन जलवायु परिवर्तन इन जोखिमों को बढ़ाने वाली पृष्ठभूमि अवश्य तैयार कर रहा है। गर्म होता हिमालय ग्लेशियरों और पर्वतीय भूभाग को अस्थिर कर रहा है, जिससे ऐसी घटनाओं की संभावित तीव्रता और व्यापकता बढ़ सकती है। वैज्ञानिकों ने भी इस बात पर सावधानी बरती है कि किसी एक घटना को सीधे जलवायु परिवर्तन का परिणाम घोषित करने के बजाय दीर्घकालिक जलवायु और भूगर्भीय बदलावों को साथ देखकर समझना चाहिए।

नेपाल की घटना भारत के लिए भी गहरी चेतावनी है। इस चेतावनी से सीख लेने की जरूरत है। उत्तराखंड की केदारनाथ त्रासदी, 2021 की ऋषिगंगा आपदा और हिमालयी राज्यों में बार-बार आने वाली बाढ़, भूस्खलन एवं बादल फटने की घटनाएं पहले ही बता चुकी हैं कि पहाड़ों की सहनशीलता असीमित नहीं है। हिमालय में सड़कें, सुरंगें, जलविद्युत परियोजनाएं, होटल, बस्तियां और अन्य निर्माण आवश्यकताओं को पूरा करने के नाम पर तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या इनके लिए पर्वतीय पर्यावरण की वहन क्षमता का पर्याप्त आकलन हो रहा है? विकास जरूरी है, मगर ऐसा विकास जो पहाड़ों को खोखला करके ही संभव हो, अंतत: मानव जीवन और स्वयं विकास दोनों के लिए संकट बन सकता है। आज सबसे बड़ी आवश्यकता 'आपदा के बाद राहत' से आगे बढ़कर 'आपदा से पहले तैयारी' की है। अत्याधुनिक सैटेलाइट निगरानी, ड्रोन, रडार, नदी सेंसर, ग्लेशियर और ग्लेशियर झीलों की निरंतर निगरानी तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित पूर्वानुमान प्रणालियों को हिमालयी क्षेत्र में व्यापक स्तर पर विकसित करना होगा। शुरुआती चेतावनी प्रणाली केवल राजधानी या प्रशासनिक केंद्र तक सीमित न रहे, बल्कि पहाड़ के अंतिम गांव तक मोबाइल संदेश, सायरन, रेडियो और स्थानीय स्वयंसेवी तंत्र के माध्यम से पहुंचे। नेपाल में वर्तमान त्रासदी के बाद भी एक और संभावित झील के फटने की आशंका ने स्पष्ट कर दिया है कि एक आपदा समाप्त होते ही दूसरी आपदा का खतरा पैदा हो सकता है। नदियां राजनीतिक सीमाओं को नहीं पहचानतीं। भोटेकोशी जैसी सीमापार नदी प्रणालियों के लिए नेपाल, चीन, भारत और अन्य हिमालयी देशों के बीच वास्तविक समय में जल-प्रवाह, वर्षा, भूस्खलन, ग्लेशियर झील और हिमस्खलन संबंधी सूचनाओं का आदान-प्रदान आवश्यक है। किसी एक देश के पास उपलब्ध महत्वपूर्ण चेतावनी दूसरे देश के नागरिकों की जान बचा सकती है।

## एक नजर

### सुपौल में अगस्त में नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 18 मामले दर्ज, 25 आरोपित गिरफ्तार

**सुपौल,एजेंसी।** जिले में मादक पदार्थों की तस्करी, बिक्री और अवैध कारोबार पर प्रभावी नियंत्रण को लेकर सोमवार को समाहरणालय स्थित लहटन चौधरी सभागार में नारको कोऑर्डिनेशन सेंटर की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिलाधिकारी सावन कुमार ने की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित बैठक में प्रवर्तन एजेंसियों और संबंधित विभागों के पदाधिकारियों के बीच समन्वय, नशामुक्ति अभियान एवं जन-जागरूकता गतिविधियों की समीक्षा की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने अगस्त माह के मासिक प्रगति प्रतिवेदन की समीक्षा की। बताया गया कि 1 अगस्त से 31 अगस्त तक जिले में मादक पदार्थों से संबंधित कुल 18 प्राथमिकी दर्ज की गईं। इस दौरान पुलिस एवं संबंधित एजेंसियों ने कार्रवाई करते हुए 842 किलोग्राम गांजा, स्मैक/चरस/ब्राउन शुगर 546.32 ग्राम तथा 638 लीटर कोडिन युक्त कफ सिरप जब्त किया। इसके अलावा 446 एमएल इंजेक्शन भी बरामद किया गया। मादक पदार्थों से जुड़े मामलों में कुल 25 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। कार्रवाई के दौरान 6 मोटरसाइकिल, 13 मोबाइल फोन, एक चार पहिया वाहन, एक तीन पहिया वाहन, एक पिस्टल और 17 कारतूस भी बरामद किए गए। जिलाधिकारी सावन कुमार ने सीमावर्ती क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरतने का निर्देश दिया। उन्होंने मादक पदार्थों की तस्करी पर प्रभावी नियंत्रण के लिए संबंधित विभागों एवं प्रवर्तन एजेंसियों के बीच सूचना का त्वरित आदान-प्रदान और संयुक्त कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा। साथ ही नशामुक्ति एवं जन-जागरूकता से जुड़ी गतिविधियों को और प्रभावी बनाने पर जोर दिया। बैठक में पुलिस अधीक्षक, सभी अनुमंडल पदाधिकारी, सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, पटना से एनसीबी के प्रतिनिधि सहित अन्य संबंधित पदाधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े रहे।

### वार्षिक उर्स में नीतीश कुमार ने मजार पर की चादरपोशी

**पटना,एजेंसी।** पटना हाईकोर्ट परिसर के उत्तरी गेट के समीप स्थित हजरत शाह जलाल शहीद की दरगाह पर आयोजित तीन वार्षिक उर्स समारोह में जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं तत्कालीन मुख्यमंत्री सह राज्यसभा सदस्य नीतीश कुमार, मंत्री अशोक चौधरी एवं बिहार विधान परिषद के सदस्य तथा सत्तारूढ़ दल के उपनेता ललन कुमार सर्राफ शामिल हुए। दरगाह पर श्रद्धापूर्वक चादरपोशी के बाद पत्रकारों से बातचीत में नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार की पहचान हमेशा से आपसी भाईचारे, प्रेम, शांति और सामाजिक सद्भाव की रही है। उर्स जैसे आयोजन समाज में एकता और भाईचारे की भावना को मजबूत करते हैं। उन्होंने प्रदेशवासियों की सुख-शांति, समृद्धि और खुशहाली की कामना की। ललन कुमार सर्राफ ने कहा कि उर्स का यह पवित्र अवसर हमें प्रेम, सद्भाव और इंसानियत का संदेश देता है। बिहार में आपसी भाईचारा और सामाजिक समरसता की मजबूत परंपरा रही है। उन्होंने प्रदेश की तरक्की, अमन-चैन एवं खुशहाली के लिए दुआ की। अशोक चैधरी ने कहा कि ऐसे धार्मिक एवं सामाजिक आयोजन हमारी साझा संस्कृति और गंगा-जमुनी तहजीब की मिसाल हैं। हमें मिल-जुलकर समाज में शांति, सौहार्द और भाईचारे को मजबूत करना चाहिए। मौके पर मंत्री जनाब जमा खां, सुन्नी वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष ईरशादउल्लाह, पूर्व सांसद जनाब अशफाक करीम सैकड़ो लोग उपस्थित थे।

### छपरा विधायक छोटी कुमारी ने मंत्री के सामने उठाई क्षेत्र से संबंधित सड़क की समस्या

**सारण।** छपरा विधानसभा क्षेत्र की सड़कों की खस्ताहाल स्थिति से जनता को राहत दिलाने के लिए विधायक छोटी कुमारी ने ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री से मुलाकात कर प्रभुनाथ नगर कदम्ब चौक से अतिथि विहार भवन होते हुए टाड़ी गांव के रास्ते एनएच-722 तक सड़क निर्माण का प्रस्ताव रखा। विधायक ने मंत्री को अवगत कराया कि सड़क की जर्जर स्थिति और बड़े-बड़े गड्ढों के कारण स्थानीय निवासियों और राहगीरों को आवागमन में अत्यधिक कठिनाई हो रही है। जनसमस्या की गंभीरता को देखते हुए मंत्री ने त्वरित कार्रवाई का आश्वासन दिया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि तत्काल राहत के तहत निर्माण कार्य शुरू होने से पहले सड़क के सभी गड्ढों को शीघ्र भरकर आवागमन सुगम बनाया जाए। साथ ही स्थायी निर्माण के लिए एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से वार्ता कर नए सड़क निर्माण की प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाने का आदेश दिया। विधायक छोटी कुमारी ने कहा कि क्षेत्रवासियों को तात्कालिक राहत देने के साथ-साथ सड़क का स्थायी समाधान कराना उनकी प्राथमिकता है। मंत्री के इस त्वरित आदेश से प्रभुनाथ नगर और टाड़ी गांव सहित आसपास के ग्रामीणों में खुशी की लहर है और उन्हें जल्द बेहतर सड़क मिलने की उम्मीद है।

# 25 वर्षों से लंबित सोन नदी जल बंटवारे के समाधान की दिशा में ऐतिहासिक कदम, बिहार-झारखंड के बीच एमओयू

**नई दिल्ली,एजेंसी।** कर्तव्य भवन, नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता एवं सी.आर.पाटिल, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री; सम्राट चौधरी, मुख्यमंत्री, बिहार सरकार एवं हेमंत सोरेन, मुख्यमंत्री, झारखंड सरकार, विजय कुमार चौधरी उप मुख्य (जल संसाधन) मंत्री की उपस्थिति में बिहार सरकार और झारखंड सरकार के बीच सोन नदी जल बंटवारा हेतु समझौता ज्ञापन पर सोमवार को हस्ताक्षर किया गया। समझौता ज्ञापन पर सी.आर.पाटिल, सम्राट चौधरी, हेमंत सोरेन ने हस्ताक्षर किया। इसके साथ ही सोन नदी के जल बंटवारे से संबंधित वर्षों से लंबित विषय के समाधान की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। वर्ष 1973 में हुए बाणसागर समझौते के तहत सोन नदी के कुल उपलब्ध 14.25 मिलियन एकड़ फीट जल में से उत्तर प्रदेश को 1.25 मिलियन एकड़ फीट, मध्य प्रदेश को 5.25 मिलियन एकड़ फीट तथा एकीकृत बिहार को 7.75 मिलियन एकड़ फीट जल आवंटित किया गया था।

वर्ष 2000 में झारखण्ड के अलग राज्य के रूप में गठन के पश्चात बिहार एवं झारखण्ड के बीच सोन नदी के जल बंटवारे का विषय सामने आया, जो पिछले 25 वर्षों से ज्यादा समय से लंबित था। इस महत्वपूर्ण विषय के समाधान की दिशा में 10 जुलाई 2025 को रांची में केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता एवं उप मुख्य (जल संसाधन) मंत्री विजय कुमार चौधरी की उपस्थिति में आयोजित पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 27वीं बैठक में बिहार को 5.75 एमएएफ तथा झारखण्ड को 2 एम एएफ सोन नदी का जल आवंटित किए जाने पर दोनों राज्यों के बीच महत्वपूर्ण सहमति बनी। उक्त सहमति को औपचारिक रूप प्रदान करने के लिए बिहार एवं झारखण्ड के बीच हस्ताक्षरित किए जाने वाले समझौता ज्ञापन का प्रारूप केंद्रीय जल आयोग द्वारा तैयार कर दोनों राज्यों को उनकी सहमति हेतु प्रेषित किया गया था, जिस पर दोनों राज्यों द्वारा सहमति प्रदान की गई। इस महत्वपूर्ण अवसर पर बिहार सरकार के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत, झारखंड सरकार के मुख्य सचिव अविनाश कुमार, जल संसाधन विभाग के सचिव डॉ. चंद्रशेखर सिंह, अभियंता प्रमुख ब्रजेश मोहन सहित विभाग के अन्य पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। इस समझौते से वर्षों से लंबित इन्द्रपुरी जलाशय परियोजना के निर्माण का मार्ग प्रशस्त होगा, जिससे बिहार के भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद, पटना, गया एवं अरवल जिलों में सिंचाई सुविधा को स्थायित्व प्रदान किया जा सकेगा।

# जदयू के 'फरक्का जल संधि पर नीतीश संवाद' कार्यक्रम के प्रथम चरण की 5 सितंबर से होगी शुरुआत

**पटना,एजेंसी।** फरक्का बैराज और फरक्का जल संधि के मुद्दे पर जनता दल यूनाईटेड (जदयू) की ओर से 5 सितंबर से 'फरक्का जल संधि पर नीतीश संवाद' कार्यक्रम के प्रथम चरण की शुरुआत की जाएगी। इसके तहत पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा एवं प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा संयुक्त रूप से संवाद करेंगे।

इस संबंध में जानकारी देते हुए प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने सोमवार को बताया कि गंगा किनारे बसे बिहार के सभी 12 जिलों में चरणबद्ध तरीके से संवाद कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। प्रथम चरण में चार जिलों में कार्यक्रम होंगे, जिसकी शुरुआत बक्सर से होगी। उन्होंने कहा कि संवाद के माध्यम से फरक्का बैराज और फरक्का जल संधि के बिहार पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभावों एवं आम लोगों की समस्याओं और चिंताओं पर विस्तार से विचार-विमर्श किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बिहार पिछले 30 वर्षों से फरक्का बैराज और फरक्का जल संधि की भारी कीमत चुका रहा है। नीतीश कुमार लंबे समय से फरक्का के कारण बिहार को हो रहे नुकसान और बिहार के जल हितों को लेकर लगातार आवाज उठाते रहे हैं। उन्होंने हर मंच पर बिहार के हितों को मजबूती से रखने और फरक्का बैराज के दुष्प्रभावों से बिहार को निजात दिलाने की मांग की है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि फरक्का बैराज के कारण गंगा में भारी मात्रा में गाद जमा होने से नदी की गहराई और जलधारण क्षमता प्रभावित हुई है। इसके चलते बिहार को हर वर्ष बाढ़ की त्रासदी झेलनी पड़ती है, जिससे किसानों की फसलें तबाह होती हैं और खेती-किसानी पर प्रतिकूल असर पड़ता है। फरक्का का मुद्दा बिहार के जल, कृषि और भविष्य से जुड़ा गंभीर विषय है। उन्होंने कहा कि फरक्का जल संधि के कारण बिहार को गंगा और उसकी सहायक नदियों के जल का फरक्का बैराज के लिए उपलब्ध कराना पड़ता है। वहीं, बिहार तेजी से विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है। प्रदेश में नए उद्योग और कल-कारखाने स्थापित हो रहे हैं, ऐसे में पानी की आवश्यकता भी लगातार बढ़ रही है। इसलिए फरक्का जल संधि का नवीनीकरण नहीं होना चाहिए और अगर हो भी, तो बिहार की वर्ष 2050 तक की जल आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ऐसी नीति सुनिश्चित की जानी चाहिए, जिसमें बिहार के हितों से कोई समझौता न हो।

# बाढ़ के पानी में मिली अज्ञात मछलियों से रहें सावधान, सीवान प्रशासन ने जारी की एडवाइजरी

**सीवान।** नेपाल की ओर से बाढ़ के पानी के साथ बिहार के कुछ क्षेत्रों में पहुंची अज्ञात एवं असामान्य मछलियों को लेकर सीवान जिला प्रशासन ने आम लोगों को सतर्क किया है। प्रशासन ने लोगों से ऐसी मछलियों का सेवन नहीं करने और बिना पहचान व संबंधित विभाग की पुष्टि के किसी भी अपरिचित मछली को खाने योग्य नहीं मानने की अपील की है। डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार सरकार के मत्स्य प्रभाग की ओर से जारी एडवाइजरी के आधार पर जिला प्रशासन ने यह सावधानी बरतने की सलाह दी है।

विभाग को नेपाल से बाढ़ के पानी के साथ बिहार के कुछ क्षेत्रों में अज्ञात और असामान्य प्रकार की मछलियों के पहुंचने की सूचना मिली है। ऐसी मछलियों के सेवन के बाद कुछ लोगों के बीमार पड़ने की भी जानकारी सामने आई है। प्रशासन के अनुसार, बाढ़ के दौरान तालाबों, नदियों, झीलों और अन्य जलाशयों से मछलियां निकलकर पानी के साथ दूर-दूर तक फैल जाती हैं। बाढ़ का पानी गंदी नालियों, मृत जानवरों और अन्य दूषित पदार्थों के संपर्क में रहता है, जिससे उसमें मौजूद मछलियां जीवाणु, विषाणु और कवक आदि से प्रदूषित हो सकती हैं। ऐसी स्थिति में बाढ़ के पानी से पकड़ी गई मछलियों का सेवन स्वास्थ्य के लिए प्रतिकूल हो सकता है। जिला प्रशासन ने लोगों से बाढ़ के पानी से पकड़ी गई अज्ञात अथवा असामान्य दिखने वाली मछलियों को खरीदने-बेचने और खाद्य उपयोग में लाने से बचने की अपील की है। प्रशासन ने कहा है कि जब तक जल एवं वातावरण की स्थिति सामान्य नहीं हो जाती और प्राकृतिक रूप से गंदगी व रोग फैलाने वाले कारक समाप्त नहीं हो जाते, तब तक बाढ़ के पानी से पकड़ी गई मछलियों के सेवन से बचना जरूरी है। प्रशासन ने यह भी कहा है कि यदि ऐसी मछली खाने के बाद किसी व्यक्ति को उल्टी, दस्त, पेट दर्द, चक्कर, सांस लेने में कठिनाई अथवा अन्य असामान्य लक्षण दिखाई दें तो तत्काल नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र या अस्पताल में चिकित्सकीय परामर्श लें। कहीं ऐसी अज्ञात या असामान्य मछली मिलने पर संबंधित जिला मत्स्य पदाधिकारी या स्थानीय प्रशासन को सूचना देने की अपील की गई है।

# सहकारी समितियों को स्वायत्त, लोकतांत्रिक एवं व्यावसायिक रूप से सशक्त बनाने पर जोर : राम कृपाल यादव

**पटना,एजेंसी।** बिहार राज्य सहकारी नीति 2026 के प्रभावी कार्यान्वयन तथा इसके अनुरूप बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम एवं नियमावली में आवश्यक संशोधनों के संबंध में आज सहकारिता मंत्री राम कृपाल यादव की अध्यक्षता में केन्द्रीय सहकारी बैंकों के अध्यक्षों, पैक्स अध्यक्षों एवं शीर्ष सहकारी समितियों के अध्यक्षों एवं प्रतिनिधियों के साथ बैठक हुई । बैठक में सहकारिता विभाग के सचिव धर्मेन्द्र सिंह तथा निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहा रजनीश कुमार सिंह सहित विभागीय पदाधिकारी एवं सहकारी क्षेत्र के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

बैठक में विभागीय पदाधिकारियों ने बिहार राज्य सहकारी नीति 2026 के प्रावधानों के आलोक में सहकारी अधिनियम, नियमावली एवं उपविधियों में आवश्यक संशोधन के लिए चिन्हित प्रमुख क्षेत्रों पर प्रस्तुतीकरण दिया। इसके साथ ही सहकारी समितियों के प्रतिनिधियों से अन्य आवश्यक क्षेत्रों में संशोधन एवं सुधार के संबंध में सुझाव आमंत्रित किए गए। बैठक में सहकारी समितियों की सदस्यता प्रक्रिया को अधिक सरल एवं प्रभावी बनाने तथा सदस्यता से संबंधित अपील की प्रक्रिया को सुगम करने पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया। सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कार्यप्रणाली, लोकतांत्रिक नियंत्रण एवं पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण की समुचित व्यवस्था किए जाने की आवश्यकता पर भी चर्चा हुई। बैठक में सहकारी समितियों के कर्मचारियों से संबंधित विषयों पर भी

महत्वपूर्ण सुझाव प्राप्त हुए। कर्मचारियों को नौकरी की सुरक्षा तथा नियमित वेतन भुगतान सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक व्यवस्था किए जाने, कर्मचारियों के लिए न्यूनतम योग्यता निर्धारित करने तथा वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन में अनावश्यक विलंब अथवा उल्लंघन की स्थिति में आर्थिक दायित्व निर्धारित करने संबंधी प्रावधानों में आवश्यक संशोधन पर चर्चा की गई। साथ ही, समितियों के लाभ से एक विशेष तकनीकी विकास कोष के गठन तथा कमजोर सहकारी समितियों के पुनरुद्धार के लिए विशेष सहकारी संरचना/समिति के गठन की संभावनाओं पर भी विचार-विमर्श किया गया। बैठक में सहकारी समितियों के शीघ्र भंग होने से संबंधित वर्तमान प्रावधानों की भी समीक्षा की आवश्यकता व्यक्त की गई। प्रतिनिधियों द्वारा सुझाव दिया गया कि आधे से अधिक सदस्यों के त्यागपत्र देने की स्थिति में समिति के भंग होने संबंधी प्रावधान को आवश्यकतानुसार शिथिल किया जाए, ताकि कार्यशील एवं उपयोगी सहकारी समितियों का निरंतर संचालन सुनिश्चित किया जा सके। बैठक में मंत्री ने विशेष रूप से पैक्सों में व्यवसाय विविधीकरण एवं आय के नए स्रोत विकसित करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में पैक्सों को केवल पारंपरिक गतिविधियों तक सीमित रखने के बजाय विभिन्न आर्थिक एवं व्यावसायिक गतिविधियों से जोड़कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की आवश्यकता है।

# जनगणना में मातृभाषा मैथिली को अधिक से अधिक संख्या में शामिल करने हेतु चेतना समिति की बैठक आयोजित

**सहरसा,एजेंसी।** चेतना समिति द्वारा आयोजित जनगणना में मातृभाषा के रूप में मैथिली को अधिक से अधिक संख्या में शामिल करने हेतु प्रारंभिक बैठक देव रिसोर्ट गंगाजला सहरसा के सभागार में प्रो कुलानन्द झा की अध्यक्षता मे संपन्न हुई। इस अवसर पर महिषी के विधायक ने डॉ गौतम कृष्ण ने कहा कि मैथिली मिथिला में रहने वाले सभी जाति धर्म के लोगों की एकमात्र भाषा है और यह हमलोगों का पुनीत कर्तव्य है कि आगामी में जनगणना में मैथिली को अपनी मातृभाषा के रूप में अंकित कराए। समारोह में बिहार सरकार के पूर्व मंत्री आलोक रंजन झा ने कहा कि माँ मातृभूमि और मातृभाषा का सम्मान करना किसी भी सभ्य समाज के लिए नितान्त आवश्यक है।इस हेतु आयोजन किए जाने वाले किसी भी कार्यक्रम में अभी सहभागिता देने के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। उन्होंने लोगो में अपनी भाषा की प्रति चेतना जागृत करने के लिए चेतना समिति के इस प्रयास की सराहना की। कार्यक्रम के अध्यक्ष प्रख्यात भाषाविद प्रो कुलानन्द झा ने कहा कि सहरसा मिथिला के साहित्य चिंतकों की उर्वरा भूमि रही है और मैथिली भाषा के विकास के लिए समय समय वे जन आंदोलन में यहाँ के लोगों की सक्रिय भागीदारी रही है उन्होंने विश्वास दिलाया कि आगामी जनगणना में सहरसा जिला मैथिली भाषा भाषियों की संख्या शत प्रतिशत होगी।

उन्होंने कहा कि जहां मैथिली भाषी लोगों की संख्या कम है वहां इस प्रकार के अभियान चलाकर जागरूकता पर बल दिया।उन्होने इसे प्रखंड एवं पंचायत स्तर तक पहुंचाने मे हर संभव मदद का आश्वासन दिया।उन्होने कहा कि चेतना समिति मिथिला मैथिली हेतु कार्यरत सभी संस्थाओं के साथ समन्वय स्थापित कर इस अभियान को सफल बनाएं। इस अवसर राजद के प्रदेश महासचिव धनिक लाल मुखिया ने कहा कि कुछ लोगो के द्वारा यह भ्रम फैलाया जाता है कि मैथिली किसी खाश जाति की भाषा है मिथिला में रहने वाले लोगों की भाषा सिर्फ़ मैथिली ही है।इस में कोई संशय नहीं है। नगर निगम की महापौर बैन प्रिया ने कहा कि हम सबों को अपने दैनिक उपयोग में भी मैथिली को प्रमुख स्थान देनी चाहिए। साथ ही जनगणना मे मातृभाषा मैथिली को अवश्य दर्ज कराने का आग्रह किया। इस अवसर पर चेतना समिति के अध्यक्ष विवेकानन्द ने कहा कि सहरसा हमेशा से मिथिला की प्रमुख केन्द्र रही है। यहाँ बोली जाने वाली भाषा ही असली मैथिली है। चेतना समिति विभिन्न लोगो से प्राप्त सुझाव पर ध्यान देते हुए उसे कार्यान्वित करने का हरसंभव प्रयास करेगी।

# सीमांचल के मक्का कारोबार को एनएफआर ने दी रफ्तार: कटिहार रेल मंडल ने 43 रैक लोड कर कमाए 29.72 करोड़

**कटिहार।** पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे (एनएफआर) ने माल ढुलाई परिचालन को सुगम बनाने और राजस्व में वृद्धि के उद्देश्य से कई नई ग्राहक अनुकूल पहलों की शुरुआत की है। इन पहलों के तहत मक्का लोडिंग में कटिहार रेल मंडल ने उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करते हुए अकेले 29.72 करोड़ रुपये का भारी राजस्व जुटाया है। यह जानकारी पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी (सीपीआरओ) कपिंजल किशोर शर्मा ने दी।

**कटिहार मंडल से 43 रैक मक्के का लदान**

सीपीआरओ के अनुसार, कटिहार मंडल के अधीन पूर्णिया, कटिहार, रानीपतरा, अररिया, जलालगढ़, रहमतपुर, बथनाहा, सूर्यकमल और डालखोला स्टेशनों से मक्के के कुल 43 रैक लोड किए गए, जिससे रेलवे को 29.72 करोड़ रुपये की आय प्राप्त हुई। इसके अलावा अलीपुरद्वार मंडल के फालाकाटा से राणिबेन्नूर के लिए मक्के का एक रैक लोड करने से 0.74 करोड़ रुपये और तूफानगंज से जिराणीया तक चावल के एक रैक से 0.29 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित हुआ।

**लामडिंग मंडल में सीमेंट, तेल और स्टोन चिप्स की रिकॉर्ड ढुलाई**

एनएफआर के लामडिंग मंडल में भी विभिन्न प्रकार की सामग्रियों के परिवहन में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। मंडल से सीमेंट के 1,921 वैगनों की बुकिंग से 9.06

करोड़ रुपये, पेट्रोलियम, तेल एवं लुब्रिकेंट (पीओएल) के 196 वैगनों से 2.38 करोड़ रुपये तथा स्टोन चिप्स के 315 वैगनों से 1.37 करोड़ रुपये का माल राजस्व हासिल किया गया।

**नए स्टेशनों पर माल व सैन्य आवाजाही शुरू**

माल परिवहन को और अधिक कुशल बनाने के लिए आधारभूत ढांचे का विस्तार भी किया गया है। इसके तहत तिनसुकिया मंडल के खराहाट स्टेशन पर पीएससी स्लीपर के आवक परिवहन की सुविधा शुरू की गई है, जबकि रंगिया मंडल के न्यू मिसामारी स्टेशन को आवक मिलिट्री ट्रैफिक (सैन्य संचालन) के लिए खोल दिया गया है। सीपीआरओ ने बताया कि इन कदमों से रेल आधारित लॉजिस्टिक्स सुदृढ़ हुआ है और कार्गो परिवहन के नए अवसर पैदा हुए हैं, जिससे क्षेत्रीय व्यापार एवं समग्र आर्थिक विकास को गति मिल रही है।

## एक नजर

### बारिश के चलते यूपी टी-20 लीग के प्लेऑफ और फाइनल अब लखनऊ में

**कानपुर,एजेंसी।** कानपुर में लगातार हो रही बारिश और खराब मौसम के मद्देनजर यूपी टी-20 लीग सीजन-4 के प्लेऑफ और फाइनल मुकाबलों को लखनऊ स्थानांतरित कर दिया गया है। अब ये सभी निर्णायक मुकाबले पूर्व निर्धारित तिथियों पर लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाएंगे। यूपी टी-20 लीग गवर्निंग कार्उसिल के चेयरमैन डॉ संजय कपूर ने सोमवार को कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में आयोजित पत्रकार वार्ता में इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों की सुरक्षा, सभी टीमों को समान परिस्थितियां उपलब्ध कराना और मुकाबलों की गुणवत्ता बनाए रखना लीग प्रबंधन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। डॉ. कपूर ने कहा कि कानपुर में लगातार बारिश के कारण मैचों को पूरा कराना चुनौतीपूर्ण हो रहा है। गीली आउटफील्ड से खिलाड़ियों के चोटिल होने का खतरा भी बढ़ जाता है। ऐसे में प्लेऑफ जैसे महत्वपूर्ण मुकाबलों में सभी टीमों को पूरे 20 ओवर खेलने का समान अवसर मिलना जरूरी है। उन्होंने कहा कि मौसम के पूर्वानुमान में आने वाले दिनों में भी कानपुर में बारिश की संभावना को देखते हुए यह फैसला लेना पड़ा। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह निर्णय किसी टीम के पक्ष या विपक्ष में नहीं, बल्कि खेल की निष्पक्षता और खिलाड़ियों के हित में लिया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि बारिश के कारण मुकाबलों के बार-बार बाधित होने और देर रात तक मैच चलने से खिलाड़ियों पर शारीरिक और मानसिक दबाव बढ़ सकता है। लखनऊ में बेहतर परिस्थितियों में मैच आयोजित होने से खिलाड़ियों को अपनी पूरी क्षमता दिखाने का अवसर मिलेगा और दर्शक भी निर्बाध क्रिकेट का आनंद ले सकेंगे। लीग प्रबंधन ने कानपुर चरण के दौरान दर्शकों, खिलाड़ियों, टीमों, अधिकारियों और सहयोगी संस्थाओं से मिले सहयोग के लिए आभार जताया। पत्रकार वार्ता में उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन की मीडिया कमेटी के चेयरमैन मोहम्मद फहीम, यूपी टी-20 लीग गवर्निंग कार्उसिल के सदस्य संजीव कुमार सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे।

### रियल मैड्रिड ने 19 वर्षीय मिडफील्डर सर्जियो मार्टिनेज के साथ किया करार

**मैड्रिड।** स्पेनिश दिग्गज रियल मैड्रिड ने रेसिंग सैंटेंडर के 19 वर्षीय मिडफील्डर सर्जियो मार्टिनेज को अपनी टीम में शामिल कर लिया है। रेसिंग सैंटेंडर ने सोमवार को इसकी पुष्टि की। मार्टिनेज ने मौजूदा सत्र के शुरुआती मुकाबले में गोल भी किया था। रियल मैड्रिड ने मार्टिनेज के लिए 30 लाख यूरो की रिलीज क्लॉज को सक्रिय किया और उनके साथ जून 2030 तक का करार किया है। इस बीच, रियल मैड्रिड के मुख्य कोच जोस मोरिन्हो ने कहा है कि क्लब की इस गर्मियों की ट्रांसफर गतिविधियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। उन्होंने कहा कि वह मौजूदा टीम से संतुष्ट हैं और फिलहाल किसी नए खिलाड़ी की मांग नहीं की है।

मोरिन्हो ने गुरुवार को रियल सोसिएदाद के खिलाफ होने वाले रियल मैड्रिड के ला लीगा के शुरुआती मुकाबले से पहले पत्रकारों से कहा, 'मेरे लिए टीम पूरी है, लेकिन ट्रांसफर बाजार अभी खुला है। सैद्धांतिक तौर पर कोई और सौदा नहीं होगा, लेकिन कुछ भी हो सकता है। मेरे दिमाग में टीम पूरी है और मैंने किसी खिलाड़ी की मांग नहीं की है। मैं अपने खिलाड़ियों से बहुत खुश हूं। रियल मैड्रिड को ट्रांसफर विंडो के दौरान मिडफील्ड में और मजबूती के लिए कई खिलाड़ियों से जोड़ा गया था। क्लब की नजर रोद्री पर भी थी, लेकिन वह अंतत: बार्सिलोना से जुड़ गए। लुका मोड्रिच और टोनी क्रूस के जाने के बाद रियल मैड्रिड के मिडफील्ड में बड़ा बदलाव आया है। ऐसे में मोरिन्हो के सामने ऑरेलियन तचुआमेनी, एडुआर्डो कामाविंगा, फेडेरिको वाल्वेर्दे और बर्नार्डो सिल्वा जैसे खिलाड़ियों के साथ नई मिडफील्ड संरचना तैयार करने की चुनौती है। हालांकि, मोरिन्हो खिलाड़ियों को पारंपरिक पोजिशन तक सीमित रखने के पक्ष में नहीं हैं। उन्होंने कहा, 'मैं तचुआमेनी को नंबर छह, कामाविंगा को नंबर छह, फेडे को नंबर आठ या बर्नार्डो को नंबर 10 के रूप में तय नहीं करना चाहता। मैच के दौरान भूमिकाएं बदलती रहती हैं। मोरिन्हो की रणनीति में किलियन एमबाप्पे, विनीसियस जूनियर और जूड बेलिंगहैम की अहम भूमिका रहने की उम्मीद है। हालांकि, तीनों स्टार खिलाड़ियों को एक साथ मैदान पर उतारते हुए टीम में सही सामंजस्य बनाना मोरिन्हो के सामने बड़ी चुनौती होगी। उन्होंने कहा, 'कोच के लिए समस्या शीर्ष खिलाड़ियों का होना नहीं है। मैं तीनों को एक साथ चाहता हूं। उनकी सकारात्मक खूबियां उनकी किसी भी सामरिक कमी की भरपाई करती हैं। यही वह जगह है जहां मैं उनकी मदद कर सकता हूं। मार्टिनेज के जुड़ने से रियल मैड्रिड को मिडफील्ड में एक युवा विकल्प भी मिला है, जबकि मोरिन्हो ने साफ कर दिया है कि फिलहाल वह अपने मौजूदा खिलाड़ियों के साथ ही सत्र की शुरुआत करने को लेकर संतुष्ट हैं।

### यूएस ओपन के पहले दौर में सोफिया केनिन ने वीनस विलियम्स को हराया

**न्यूयॉर्क।** अमेरिकी वाइल्ड कार्ड खिलाड़ी सोफिया केनिन ने 46 वर्षीय हमवतन वीनस विलियम्स को यूएस ओपन-2026 के पहले दौर में 6-2, 7-6 (6) से हराकर दूसरे दौर में प्रवेश किया। यह मुकाबला न्यूयॉर्क में आधी रात के बाद शुरू हुआ और महिला यूएस ओपन इतिहास का सबसे देर से शुरू होने वाला मुकाबला बन गया। आर्थर ऐश स्टेडियम में मुकाबला नोवाक जोकोविच और मारियानो नावेने के बीच पांच सेट के मुकाबले के बाद शुरू हुआ। देर रात होने के बावजूद बड़ी संख्या में दर्शक वीनस को देखने के लिए स्टेडियम में रुके रहे। वीनस अपने करियर के 96वें ग्रैंड स्लैम मुख्य ड्रॉ में वाइल्ड कार्ड के जरिए उतरी थीं। वीनस ने कहा, 'यह बेहद देर से शुरू हुआ। मैंने इससे पहले कभी इतनी देर से मुकाबला नहीं खेला। मुझे खुशी है कि इतने सारे लोग इसके लिए रुके रहे। उनके सामने खेलना मेरे लिए सम्मान की बात थी। केनिन ने पहले ही गेम में वीनस की सर्विस तोड़ दी और शुरुआती सेट में लगातार दबदबा बनाए रखा। उन्होंने 3-0 की बढ़त बनाई। वीनस ने वापसी करते हुए एक गेम जीता, लेकिन केनिन ने फिर सर्विस ब्रेक हासिल कर सेट 6-2 से अपने नाम कर लिया। दूसरे सेट में भी केनिन ने 3-1 की बढ़त बना ली। हालांकि सात बार की ग्रैंड स्लैम चैंपियन वीनस ने कुछ बेहतरीन शॉट लगाकर वापसी की कोशिश की। दोनों खिलाड़ियों के बीच मुकाबला 5-5 की बराबरी तक पहुंचा और फिर टाईब्रेक में चला गया। टाईब्रेक में वीनस के पास सेट जीतने के सात मौके आए, लेकिन वह इनमें से किसी को भी भुना नहीं सकीं। केनिन ने धैर्य बनाए रखते हुए टाईब्रेक 8-6 से जीतकर मुकाबला अपने नाम कर लिया। वीनस ने कहा, 'यह आदर्श स्थिति नहीं थी। मैं निश्चित रूप से कुछ और चाहती। पहली बार में ही रात एक या दो बजे अपना लय हासिल करना और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना आसान नहीं है, लेकिन मैंने अपनी पूरी कोशिश की।'

# ऑस्ट्रेलिया सीरीज से पहले बीसीसीआई ने अंडर-19 खिलाड़ियों के लिए लगाए विशेष ट्रेनिंग

**बेंगलुरु।** भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने आगामी घरेलू और अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों से पहले अंडर-19 पुरुष क्रिकेटरों की तैयारियों को धार देने के लिए बेंगलुरु स्थित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (सीओई) में विशेष प्रशिक्षण शिविरों की श्रृंखला पूरी कर ली है। इन शिविरों में देशभर से चुने गए युवा विकेटकीपर, स्पिन गेंदबाज और तेज गेंदबाज शामिल हुए। खिलाड़ियों ने विशेषज्ञ कोचिंग स्टाफ की निगरानी में अपनी बुनियादी तकनीक को मजबूत करने के साथ-साथ खेल से जुड़ी बारीकियों पर काम किया।

बीसीसीआई ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि अंडर-19 खिलाड़ियों के लिए विकेटकीपिंग, स्पिन और तेज गेंदबाजी के अलग-अलग प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए गए। इन शिविरों का उद्देश्य युवा खिलाड़ियों की तकनीकी क्षमता को निखारना और उन्हें भविष्य में मिलने वाले अवसरों के लिए बेहतर तरीके से तैयार करना था। सीओई के फील्डिंग कोच दिशांत याग्निक और स्पिन गेंदबाजी कोच सुनील जोशी भी खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देते नजर आए। इस दौरान खिलाड़ियों ने अपनी कमजोरियों पर काम करने के साथ कौशल में सुधार पर ध्यान दिया। बेंगलुरु स्थित सीओई में इस समय विभिन्न गतिविधियां चल रही हैं। चोट से उबर रहे पुरुष और महिला क्रिकेटरों के पुनर्वास के अलावा वरिष्ठ पुरुष खिलाड़ियों के लिए लक्षित शिविर और प्री-सीजन फिटनेस परीक्षण भी आयोजित किए जा रहे हैं। भारतीय अंडर-19 टीम को सितंबर में ऑस्ट्रेलिया अंडर-19 के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज खेलनी है। मुकाबले 18, 21 और 23 सितंबर को राजकोट में होंगे। इसके बाद

दोनों टीमों के बीच दो बहुदिवसीय मुकाबले भी खेले जाएंगे। सीरीज के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम में लेग स्पिन ऑलराउंडर आर्यवीर सहवाग और विकेटकीपर-बल्लेबाज अन्वय द्रविड़ को भी शामिल किया गया है। उत्तराखंड के बल्लेबाज लक्ष्य रायचंदानी वनडे टीम की कप्तानी करेंगे, जबकि मध्य प्रदेश के यशवर्धन चौहान उपकप्तान होंगे। बहुदिवसीय मुकाबलों में दोनों खिलाड़ी अपनी भूमिकाएं आपस में बदलेंगे। पहला बहुदिवसीय मैच 27 सितंबर से राजकोट में और दूसरा 05 अक्टूबर से अहमदाबाद के नरेन्द्र मोदी स्टेडियम 'बी' ग्राउंड में खेला जाएगा।

## मयंक अग्रवाल ने डरहम के साथ चार मैचों का काउंटी चैंपियनशिप करार किया

**चेस्टर-ले-स्ट्रीट।** भारतीय सलामी बल्लेबाज मयंक अग्रवाल ने इंग्लैंड की काउंटी टीम डरहम के साथ मौजूदा काउंटी चैंपियनशिप डिविजन-दो सत्र के अंतिम चरण के लिए चार मैचों का करार किया है। डरहम ने सोमवार को इसकी घोषणा की। 35 वर्षीय मयंक अग्रवाल टीम के मुख्य कोच रयान कैंपबेल की अगुआई वाली डरहम टीम से जुड़ेंगे।

टीम डिविजन-दो से पदोन्नति हासिल करने की कोशिश में जुटी है। मयंक आगामी मुकाबले में नॉर्थम्पटनशायर के खिलाफ डरहम के लिए उपलब्ध रहेंगे। वह दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाज डेविड बेडिंघम की जगह लेंगे, जो अपने देश लौट गए हैं। कैंपबेल ने कहा, 'हमें खुशी है कि मयंक डरहम के साथ काउंटी चैंपियनशिप के अंतिम चरण में जुड़ रहे हैं। डेविड बेडिंघम के दक्षिण अफ्रीका लौटने के बाद हमारे लिए जरूरी था कि हम एक उच्च स्तर के अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर को टीम में शामिल करें। मयंक ने भारत के लिए 21 टेस्ट मैचों में 1,488 रन बनाए हैं। उनके नाम चार शतक हैं, जिसमें 2019 में इंदौर में बांग्लादेश के खिलाफ बनाया गया 243 रन का सर्वश्रेष्ठ स्कोर भी शामिल है। उन्होंने भारत के लिए पांच एकदिवसीय मैच भी खेले हैं, जिसमें 86 रन बनाए हैं। कैंपबेल ने मयंक के प्रथम श्रेणी रिकॉर्ड की तारीफ करते हुए कहा कि टीम को उनसे डिविजन-दो से डिविजन-एक में वापसी की कोशिश में काफी उम्मीदें हैं। मयंक को इंग्लैंड की परिस्थितियों में खेलने का अनुभव भी है। उन्होंने 2025 काउंटी चैंपियनशिप सत्र के अंतिम चरण में यॉर्कशायर का प्रतिनिधित्व किया था। इस दौरान उन्होंने 201 रन बनाए थे, जिसमें डरहम के खिलाफ उनकी आखिरी पारी में खेली गई 175 रन की मैच जिताऊ पारी भी शामिल थी। मयंक अपने प्रथम श्रेणी करियर में 9,000 रन पूरे करने के करीब हैं। उनके नाम 21 शतक भी दर्ज हैं। इसके अलावा उन्होंने विभिन्न भारतीय प्रीमियर लीग टीमों के लिए टी20 क्रिकेट में 5,000 से अधिक रन बनाए हैं। वह 2025 में खिताब जीतने वाली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु टीम का भी हिस्सा थे, जहां उन्होंने चोटिल देवदत्त पडिक्कल की जगह टीम में प्रवेश किया था। डिविजन-दो की अंक तालिका में डरहम फिलहाल शीर्ष पर है और टीम को उम्मीद है कि मयंक का शीर्ष क्रम का अनुभव उसे अगले सत्र में डिविजन-एक में वापसी दिलाने में अहम भूमिका निभाएगा। इंग्लैंड के घरेलू सत्र में इस समय कई भारतीय खिलाड़ी भी खेल रहे हैं। बाएं हाथ के स्पिनर मानव सुथार वार्विकशायर से फिर जुड़ रहे हैं, जबकि कलाई के स्पिनर कुलदीप यादव यॉर्कशायर के लिए खेलेंगे। सरे की टीम में भारत के लेग स्पिनर राहुल चाहर और बल्लेबाजी ऑलराउंडर महिपाल लोमरोर भी शामिल हैं।

## देहरादून टी20 लीग 2026 में हिस्सा लेने वाली सभी 6 टीमों का ऐलान

**देहरादून।** देहरादून टी-20 लीग 2026 की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। टूर्नामेंट की शुरुआत से ठीक पहले सभी 6 फ्रेंचाइजी टीमों ने अपने पूरे स्क्वॉड का आधिकारिक ऐलान कर दिया है। 2 से 9 सितंबर तक देहरादून की अभिमन्यु क्रिकेट अकादमी में यह टूर्नामेंट खेला जाएगा। इसमें उत्तराखंड के युवा खिलाड़ियों के साथ-साथ आईपीएल और घरेलू क्रिकेट के बड़े नाम भी अपना जलवा दिखाएंगे। खिलाड़ियों के ड्रॉफ्ट के दौरान उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे। खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करते हुए उन्होंने कहा, 'उत्तराखंड में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। देहरादून टी20 लीग हमारे युवाओं को एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे रही है, जहां वे खुद को साबित करके नेशनल लेवल पर अपनी पहचान बना सकते हैं। राज्य सरकार हमेशा खेलों और खिलाड़ियों का साथ देने के लिए तैयार है। मुझे पूरा यकीन है कि यह लीग उत्तराखंड क्रिकेट के लिए एक बड़ा कदम साबित होगी।

कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में पहुंचे बीसीसीआई के पूर्व उपाध्यक्ष माहिम वर्मा ने कहा, 'यह लीग सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं है, बल्कि हमारे लोकल क्रिकेटरों के लिए आगे बढ़ने का बहुत बड़ा मौका है। जब हमारे युवा खिलाड़ी आईपीएल और घरेलू क्रिकेट के अनुभवी कप्तानों व खिलाड़ियों के साथ डगआउट शेयर करेंगे, तो उनका कॉन्फिडेंस और खेल का स्तर काफी बेहतर होगा। वहीं, देहरादून टी20 लीग के सीईओ नवनीत मिश्रा ने तैयारियों की जानकारी देते हुए कहा, 'हमने खिलाड़ियों को वर्ल्ड क्लास सुविधाएं और बेहतरीन ग्राउंड देने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। हमारा मकसद ऐसा माहौल तैयार करना है जहां हर खिलाड़ी खुलकर अपना बेस्ट खेल सके। फैंस को 8 दिनों तक काफी रोमांचक क्रिकेट देखने को मिलेगा। इस दौरान क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के मुख्य संरक्षक पी. सी. वर्मा, सीएडी के अध्यक्ष संदीप रावत और सीएडी के सचिव पीयूष कुमार रघुवंशी भी मौजूद रहे और उन्होंने सभी टीमों को शुभकामनाएं दीं।

## एशियाई खेल: भवानी देवी की अगुआई में भारत की 20 सदस्यीय तलवारबाजी टीम घोषित

**नई दिल्ली,एजेंसी।** ओलंपियन सीए भवानी देवी आगामी एशियाई खेलों के लिए घोषित भारत की 20 सदस्यीय तलवारबाजी टीम की अगुआई करेंगी। तलवारबाजी संघ ने रविवार को राष्ट्रीय रैंकिंग और 2026 में प्रमुख अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में खिलाड़ियों के प्रदर्शन के आधार पर टीम की घोषणा की। चयनित खिलाड़ी 01 से 15 सितंबर तक पटियाला स्थित नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान में राष्ट्रीय तैयारी शिविर में हिस्सा लेंगे। इसके बाद भारतीय दल 16 सितंबर को आइची-नागोया के लिए रवाना होगा, जहां प्रतियोगिता से पहले अंतिम अनुकूलन की तैयारी की जाएगी। टीम का चयन एशियाई सीनियर तलवारबाजी चैंपियनशिप, विश्व तलवारबाजी चैंपियनशिप और राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप में खिलाड़ियों के प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए किया गया है। भवानी देवी की अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में वापसी से भारत की महिला सेबर टीम को मजबूती मिली है।

भारतीय तलवारबाजी की अग्रणी खिलाड़ियों में शामिल भवानी ने इस साल एशियाई सीनियर तलवारबाजी चैंपियनशिप के दौरान दो महीने के ब्रेक के बाद प्रतिस्पर्धी मुकाबलों में वापसी की थी। राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करने वाले कई खिलाड़ियों से भी भारतीय टीम को उम्मीदें हैं। महिला एपे में तनिक्षा खत्री और प्राची लोहान ने क्रमश: स्वर्ण और कांस्य पदक जीता था। पुरुष सेबर में करण सिंह गुर्जर ने राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर एशियाई खेलों के लिए अपनी दावेदारी मजबूत की। वहीं, पुरुष फॉयल

में तेजस मनोज पाटिल ने राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रचा। वह इस प्रतियोगिता में सीनियर फॉयल वर्ग में पदक जीतने वाले पहले भारतीय तलवारबाज बने।

भारत की 20 सदस्यीय तलवारबाजी टीम

पुरुष फॉयल: सचिन, सनासम हेमाश सिंह, आदित्य और तेजस मनोज पाटिल।

महिला फॉयल: जॉयस अशिता स्टालिनराज, नाओरेम मीना देवी, कनुप्रिया चावला और सोनिया देवी वैखोम।

महिला एपे: तनिक्षा खत्री, प्राची लोहान, मित्वा चौधरी और यशकीरत कौर हेयर।

पुरुष सेबर: करण सिंह, गिशो निधि केपी, लक्ष्य बादसर और विशाल थापर।

महिला सेबर: भवानी देवी सीए, श्रेया गुप्ता, जेफरलिन जेएस और श्रुति जोशी।

## कर्नाटक के गांव से एशियाई खेलों तक का सफर : सेना में मिली निशानेबाजी ने बदली केदारलिंग की जिंदगी

**नई दिल्ली,एजेंसी।** कर्नाटक के एक छोटे से गांव से निकलकर भारतीय सेना में भर्ती होने वाले केदारलिंग बालकृष्ण उचागनवे ने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन वह अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। वर्ष 2018 में सेना में शामिल होने वाले 27 वर्षीय नायब सूबेदार केदारलिंग अब आगामी एशियाई खेलों में भारतीय निशानेबाजी टीम का हिस्सा बनने जा रहे हैं। हालांकि, उनकी नजर इससे भी बड़े लक्ष्य पर है—लॉस एंजिल्स ओलंपिक में पदक जीतना। कृषि पर निर्भर परिवार से आने वाले केदारलिंग के माता-पिता आज भी खेती करते हैं। संयुक्त परिवार में पले-बढ़े केदारलिंग ने बचपन में जिला स्तर पर 1500 मीटर दौड़ में हिस्सा लिया था, लेकिन तब उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि खेल के जरिए अंतरराष्ट्रीय पहचान बनाएंगे।

निशानेबाजी से उनका परिचय भी लगभग संयोग से हुआ। सेना में भर्ती होने के बाद उन्हें पता चला कि वहां शूटिंग रेंज है और प्रतिभाओं की पहचान की जा रही है। इसी प्रक्रिया में उनका चयन हुआ और उन्होंने पहली बार पिस्टल थामी। केदारलिंग ने साई मीडिया से बातचीत में बताया, 'सेना में शामिल होने से पहले मुझे निशानेबाजी के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। स्कूल या कॉलेज के समय सामान्य ज्ञान में अभिनव बिंद्रा का नाम जरूर सुना था। 2018 में सेना में आने के बाद मुझे शूटिंग रेंज और प्रतिभा पहचान कार्यक्रम के बारे में पता चला। मेरा चयन हुआ और तभी मुझे वास्तव में

निशानेबाजी के बारे में जानकारी मिली। शुरुआत में उन्हें इस खेल में करियर की संभावनाओं का अंदाजा नहीं था। घरेलू प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने, अनुभवी निशानेबाजों को देखने और प्रशिक्षण के दौरान मिले अनुभवों ने उनकी सोच बदल दी। उन्होंने कहा, 'शुरुआत में हमें इस खेल के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। हम सिर्फ बंदूक से अभ्यास करते थे। लेकिन जब हमें बाहर जाकर प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने और शूटिंग से जुड़े वीडियो देखने का मौका मिला, तब समझ आया कि इसे करियर बनाया जा सकता है। हम नौकरी के साथ देश के लिए भी खेल सकते हैं। यहीं से मेरे अंदर इच्छा पैदा हुई। दौड़ के मुकाबले निशानेबाजी की अलग प्रकृति ने भी उन्हें आकर्षित किया। केदारलिंग के मुताबिक, इसमें बाहरी परिस्थितियों के बजाय खुद पर नियंत्रण, एकाग्रता और सटीकता महत्वपूर्ण होती है। सेना उनके लिए सिर्फ नौकरी का माध्यम नहीं रही, बल्कि यहीं से उनके निशानेबाजी करियर को मजबूत आधार मिला। शुरुआती प्रशिक्षकों ने उन्हें खेल जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया। सेना की टीम में जगह बनाने के बाद उन्हें प्रशिक्षकों के साथ-साथ खेल चिकित्सा विशेषज्ञों और पोषण विशेषज्ञों की सुविधाएं भी मिलीं।

सेना ने उन्हें शुरुआती दौर में पिस्टल भी उपलब्ध कराई। साझा हथियार से अभ्यास शुरू करने के बाद प्रदर्शन बेहतर होने पर उन्हें व्यक्तिगत पिस्टल दी गई। अब उनके पास सेना की ओर से मिली पिस्टल के अलावा एक अतिरिक्त पिस्टल भी है। हालांकि, उनका सफर चुनौतियों से भी भरा रहा। खेती पर निर्भर परिवार के लिए निशानेबाजी में इस्तेमाल होने वाले उपकरण और गोलियों का खर्च एक बड़ी चिंता थी। सेना, भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ, भारतीय खेल प्राधिकरण और प्रायोजक की मदद से उन्हें प्रशिक्षण शिविरों और प्रतियोगिताओं में जरूरी सुविधाएं मिलती रहीं। केदारलिंग के लिए ध्यान भी तैयारी का अहम हिस्सा है। वह दिन की शुरुआत ध्यान और सांसों पर ध्यान केंद्रित करके करते हैं। उनका मानना है कि शांत रहना निशानेबाजी में बेहतर प्रदर्शन के लिए बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा, 'सबसे पहले अगर हम शांत रहें तो सब कुछ ठीक रहेगा। ध्यान के दौरान मैं अपनी सांस और परिस्थिति पर ध्यान देता हूं, ताकि वर्तमान में रह सकूं।

## रोहित शर्मा की टीवी पर नई पारी, 'फैमिली फुल हाउस' से करेंगे मनोरंजन जगत में डेब्यू

**मुंबई,एजेंसी।** भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज और 2024 टी20 विश्व कप विजेता कप्तान रोहित शर्मा अब क्रिकेट के मैदान के बाद टेलीविजन की दुनिया में भी नई पारी शुरू करने जा रहे हैं। सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स इंडिया ने अपने आगामी शो 'फैमिली फुल हाउस विद रोहित शर्मा' के नाम की घोषणा की है। यह शो 19 सितंबर 2026 से प्रसारित होगा। रोहित शर्मा इस शो के मुख्य आकर्षण होंगे और इसके जरिए उनका बहुप्रतीक्षित टेलीविजन डेब्यू होगा। पारिवारिक मनोरंजन पर आधारित इस कार्यक्रम को दर्शकों के लिए एक नए और मनोरंजक अंदाज में पेश किया जाएगा।

रोहित ने टेस्ट और टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है और अब वह केवल एकदिवसीय क्रिकेट में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। 39 वर्षीय रोहित के भविष्य और 2027 एकदिवसीय विश्व कप में उनके खेलने को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपने प्रदर्शन से आलोचकों को जवाब दिया है। हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ तीन मैचों की एकदिवसीय श्रृंखला में रोहित ने शानदार बल्लेबाजी की। भारत यह श्रृंखला 1-2 से हार गया, लेकिन रोहित ने तीन मैचों में 58.33 की औसत से 175 रन बनाए। उनके बल्ले से एक शतक भी निकला। श्रृंखला के तीसरे और निर्णायक मुकाबले में लॉर्ड्स के मैदान पर रोहित ने 110 गेंदों पर 138 रनों की तूफानी पारी खेली। उन्होंने अपनी पारी में 17 चौके और पांच छक्के लगाए। इस मुकाबले में उन्होंने अपने लंबे समय के बल्लेबाजी साथी विराट कोहली के साथ शतकीय साझेदारी भी की। कोहली ने 60 गेंदों पर 74 रन बनाए। हालांकि, भारत यह मुकाबला 27

रन से हार गया। इससे पहले तीसरे एकदिवसीय मैच को लेकर यह अटकलें भी लगाई जा रही थीं कि लॉर्ड्स में होने वाला मुकाबला रोहित का भारत के लिए आखिरी अंतरराष्ट्रीय मैच हो सकता है। हालांकि, उनकी शानदार 138 रन की पारी ने एक बार फिर साबित किया कि वह अभी भी बड़े मुकाबलों में प्रभाव छोड़ने की क्षमता रखते हैं। रोहित शर्मा अब तक 288 एकदिवसीय मैचों की 280 पारियों में 48.95 की औसत और 93.04 के स्ट्राइक रेट से 11,895 रन बना चुके हैं। उनके नाम 34 शतक और 62 अर्धशतक हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 264 रन है। वह एकदिवसीय क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाजों की सूची में सातवें स्थान पर हैं और भारत की ओर से विराट कोहली तथा सचिन तेंदुलकर के बाद तीसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। वर्ष 2026 में भी रोहित का बल्ला प्रभावी रहा है। उन्होंने नौ एकदिवसीय मैचों की नौ पारियों में 42.11 की औसत से 379 रन बनाए हैं, जिसमें एक शतक और एक अर्धशतक शामिल है।

## एक नजर

### खार्ग द्वीप पर ट्रंप की पोस्ट ईरान के लिए संदेश थीः उपराष्ट्रपति वेंस

**वाशिंगटन,एजेंसी।** अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ईरान के खार्ग द्वीप को लेकर सोशल मीडिया पर की गई पोस्ट को लेकर उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि इसका मकसद ईरान को एक संदेश देना था। वेंस के इस बयान के बाद दोनों देशों के बीच पहले से जारी तनाव के बीच कूटनीतिक और सैन्य हलचल और बढ़ गई है। वेंस ने सोमवार को कहा कि ट्रंप सोशल मीडिया पर अपनी बात अलग-अलग अंदाज में रखते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि राष्ट्रपति आमतौर पर सोशल मीडिया के जरिए सैन्य अभियानों की औपचारिक घोषणा नहीं करते, लेकिन खार्ग द्वीप से जुड़ी पोस्ट के जरिए ईरान को संदेश जरूर दिया गया। ट्रंप ने 30 अगस्त को एक संक्षिप्त सोशल मीडिया पोस्ट के साथ एक वीडियो साझा किया था, जिसमें ईरान के प्रमुख ऊर्जा केंद्र खार्ग द्वीप को तबाह किए जाने का दृश्य दिखाया गया था। हालांकि, एक अमेरिकी अधिकारी ने सोमवार को स्पष्ट किया कि रातभर की अमेरिकी सैन्य कार्रवाई में खार्ग द्वीप को निशाना नहीं बनाया गया था। दूसरी ओर, ईरानी अधिकारियों ने ट्रंप की पोस्ट को खारिज करते हुए इसे हास्यास्पद बताया है। खार्ग द्वीप ईरान के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। युद्ध शुरू होने से पहले ईरान के तेल निर्यात का लगभग 90 प्रतिशत हिस्सा इसी केंद्र से संभाला जाता था। ऐसे में इस क्षेत्र पर हमला होने की स्थिति में ईरान के ऊर्जा निर्यात और अर्थव्यवस्था पर गंभीर असर पड़ सकता है।

### ईरान के जॉर्डन हमले पर ट्रंप की चेतावनी, बोले- 'अमेरिका जोरदार जवाब देगा'

**वाशिंगटन।** जॉर्डन में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर ईरान की ओर से किए गए मिसाइल हमले के बाद अमेरिका और ईरान के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्पष्ट किया है कि वाशिंगटन इस हमले का जवाब देगा और ईरान को इसकी कीमत चुकानी पड़ सकती है। ट्रंप ने फॉक्स न्यूज से बातचीत में कहा कि अमेरिका ईरान पर ''जोरदार हमला'' करेगा। उन्होंने कहा, ''हम उन्हें कड़ा जवाब देंगे। जवाब दिया जाएगा।

ट्रंप ने दावा किया कि ईरान की लगभग सभी मिसाइलों को अमेरिकी वायु रक्षा प्रणालियों ने रोक दिया। उनके मुताबिक, एक मिसाइल को जानबूझकर आगे बढ़ने दिया गया क्योंकि उसकी दिशा किसी महत्वपूर्ण लक्ष्य की ओर नहीं थी। जॉर्डन की सेना के अनुसार, ईरान की ओर से दागी गई आठ मिसाइलों को उसके हवाई क्षेत्र में ही रोक लिया गया। ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने दावा किया कि उसने जॉर्डन स्थित किंग हुसैन और अल-अज़्राक एयरबेस को निशाना बनाया। ईरानी पक्ष के मुताबिक, इन ठिकानों पर तकनीकी ढांचे, रखरखाव सुविधाओं और लड़ाकू विमानों से जुड़े ठिकानों को निशाना बनाया गया।

### इस साल अब तक उत्तरी समुद्री मार्ग पर कार्गो ट्रैफिक में 15 फीसदी की वृद्धि : चेकुनकोव

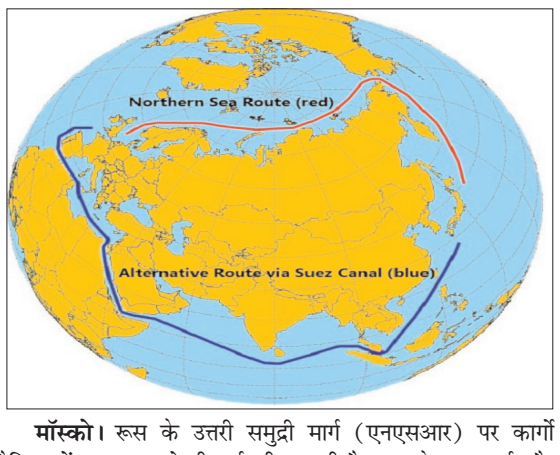


**मॉस्को।** रूस के उत्तरी समुद्री मार्ग (एनएसआर) पर कार्गो ट्रैफिक में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। रूस के सुदूर पूर्व और आर्कटिक विकास मंत्री एलेक्सी चेकुनकोव ने ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम (ईईएफ)-2026 से पहले रिया नोवोस्ती को दिए एक इंटरव्यू में बताया कि 2026 के लगभग आठ महीनों में इस मार्ग से 24.2 मिलियन टन कार्गो का परिवहन किया जा चुका है। इस दौरान कार्गो ट्रैफिक में सालाना आधार पर करीब 15 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। चेकुनकोव ने कहा कि एनएसआर पर कार्गो ट्रांसपोर्ट में इस साल वृद्धि का रुझान सकारात्मक बना हुआ है। करीब आठ महीनों में माल ढुलाई में 15 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है और अब तक 24.2 मिलियन टन कार्गो इस मार्ग से पहुंचाया जा चुका है। बीते 10 वर्षों में एनएसआर पर शिपिंग वॉल्यूम करीब 10 गुना बढ़ा है। वर्ष 2025 में इस मार्ग से कुल करीब 37 मिलियन टन माल का परिवहन हुआ था। एनएसआर रूस के उत्तरी तट के साथ गुजरने वाला एक महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है। रूस का कहना है कि अब इस रूट में रूसी जहाज मालिकों के साथ-साथ विदेशी शिपिंग कंपनियों की भी दिलचस्पी बढ़ रही है। इस मार्ग की खासियत यह है कि यह यूरोप और एशिया के बीच समुद्री परिवहन के लिए अपेक्षाकृत छोटा रास्ता उपलब्ध कराता है। इसके अलावा रेड सी और पर्शियन गल्फ में सुरक्षा से जुड़ी परिस्थितियों के कारण भी वैकल्पिक समुद्री मार्ग के रूप में एनएसआर की अहमियत बढ़ी है। चार दिवसीय ईईएफका आयोजन आगामी एक से 4 सितंबर तक रूस के व्लादिवोस्तोक में किया जाएगा। फोरम में रूस के सुदूर पूर्व के विकास, निवेश और अंतरराष्ट्रीय आर्थिक सहयोग से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। रिया नोवोस्ती इस आयोजन का जनरल मीडिया पार्टनर है।

# नेपाल जलप्रलय : अब तक 903 शव बरामद, 4,247 लापता, 10,451 लोगों को किया गया रेस्क्यू

**काठमांडू,एजेंसी।** नेपाल के रसुवा में आई विनाशकारी बाढ़ के बाद राहत, खोज और बचाव अभियान लगातार जारी है। नेपाल के गृह मंत्रालय के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की आज सुबह 11 बजे तक की रिपोर्ट के मुताबिक, अब तक 903 लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं, जबकि 4,247 लोग अब भी लापता हैं।

प्राधिकरण के अनुसार, अब तक बरामद शवों में रसुवा से 24, नुवाकोट से 95, धादिङ से 55, गोरखा से 62, नवलपरासी पूर्व से 207, नवलपरासी पश्चिम से 151, तनहुँ से 37 और चितवन से 272 शव शामिल हैं। इनमें कई अज्ञात मानव अवशेष भी शामिल हैं। नेपाल सरकार के विभिन्न निकायों में अब तक 4247 लोगों के संपर्कविहीन होने की रिपोर्ट दर्ज की गई है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक लापता लोगों में नेपाल पुलिस के 25, नेपाली सेना के 45, सशस्त्र पुलिस बल के 13, कस्टम कार्यालय के 15 और इमिग्रेशन कार्यालय के 3 कर्मचारी शामिल हैं। इसके अलावा रसुवा में 865 और नुवाकोट में 1,558 लोगों के लापता होने की जानकारी दी गई है। लापता लोगों में जलविद्युत परियोजनाओं से जुड़े 933 लोग, मकवानपुर के 65, विदेशी नागरिक 592, विदेशियों के साथ यात्रा कर रहे 127 नेपाली नागरिक, लैंगटांग राष्ट्रीय उद्यान के 3 और क्वारंटीन कार्यालय के 3 लोग भी

शामिल हैं। नेपाल सरकार के मुताबिक अब तक कुल 10,451 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। नेपाली सेना के हवाई बचाव अभियान में 252 विदेशी नागरिकों और 3,344 नेपाली नागरिकों को सुरक्षित निकाला गया। रिपोर्ट के अनुसार, 30 अगस्त तक जलविद्युत परियोजनाओं से 15 चीनी और 7 भारतीय नागरिकों को भी बचाया गया है। अब तक 411 हेलीकॉप्टर उड़ानें संचालित की जा चुकी हैं, जिनमें 31 अगस्त को 17 उड़ानें शामिल हैं। बाढ़ में कुल 267 लोग घायल हुए हैं। इनमें से 156 लोगों को अस्पताल से छुट्टी दी जा चुकी है। प्रभावित क्षेत्रों में छह सर्जिकल मेडिकल टीमें भी तैनात की गई हैं। राहत और बचाव अभियान में कुल 20,819 सुरक्षाकर्मी जुटे हुए हैं। इनमें नेपाल पुलिस के 7,894, नेपाली सेना के 8,722 और सशस्त्र पुलिस बल के 4,203 जवान शामिल हैं। प्राधिकरण ने बताया कि अज्ञात शवों को विभिन्न जिलों के 21 अस्पतालों में रखा गया है। शवों की पहचान और प्रबंधन का काम जारी है। प्रभावित इलाकों में ईंधन की उपलब्धता के तहत 25 हजार लीटर डीजल, 21 हजार लीटर पेट्रोल और 10 हजार लीटर विमान ईंधन का स्टॉक मौजूद है।

### नेपाल आपदा : 39 देशों के करीब 590 विदेशी नागरिक अब भी लापता, अब तक 323 विदेशी नागरिकों का रेस्क्यू

**काठमांडू।** हाल ही में आई विनाशकारी बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों से 323 से अधिक विदेशी नागरिकों को सुरक्षित निकाल लिया गया है, जबकि उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक 39 देशों के करीब 590 विदेशी नागरिक अब भी लापता हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि सरकार पड़ोसी देशों और अंतरराष्ट्रीय समुदाय के साथ लगातार संपर्क और समन्वय बनाए हुए है। बड़ी संख्या में विदेशी नागरिकों के अब भी लापता होने को देखते हुए मंत्रालय में एक इमरजेंसी कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है, जो संबंधित एजेंसियों के साथ-साथ लापता लोगों के परिवारों के साथ भी समन्वय कर रहा है। विदेशी नागरिकों से संबंधित सत्यापित जानकारी राजनयिक मिशनों के माध्यम से लगातार साझा और अपडेट की जा रही है। साथ ही, मिशन लापता लोगों के परिवारों से संपर्क स्थापित करने, आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने तथा पहचान और शवों की स्वदेश वापसी की प्रक्रिया में भी सहयोग कर रहे हैं। नेपाल के विदेश मंत्रालय के मुताबिक सुरंगों में फंसे लोगों को निकालने के लिए भारत और चीन की विशेषज्ञ तकनीकी टीमें नेपाल पहुंच चुकी हैं। भारत से 11 और चीन से 9 विशेषज्ञ नेपाली अधिकारियों के समन्वय में रेस्क्यू अभियान में जुटे हैं। भारत की टीम मेलुंग (चिलिमे) और स्याफ्रुबेसी में, जबकि चीन की टीम अपर त्रिशूली-3ए में सुरंग बचाव अभियान में सहयोग कर रही है। दक्षिण कोरिया की एक टीम को भी अभियान में लगाया गया है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारत से डीएनए विश्लेषण में विशेषज्ञता रखने वाले 18 फॉरेंसिक विशेषज्ञों की टीम 29 अगस्त से नेपाल में मौजूद है। इस संबंध में भी दोनों देशों के बीच समन्वय जारी है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारत, चीन, जापान, अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई), दक्षिण कोरिया और अन्य देशों तथा साझेदारों से नेपाल को बचाव और राहत के लिए महत्वपूर्ण सहायता मिल चुकी है। इस सहायता में ब्रिज यूनिट, फ्रीजर, जनरेटर सेट, सोलर लैंप, डीएनए टेस्टिंग किट, आपातकालीन राहत उपकरण, टेंट, कंबल, स्लीपिंग बैग, खाद्य सामग्री और दवाइयां आदि शामिल हैं। भारत, चीन सहित अन्य देशों से राहत सामग्री पहले ही नेपाल पहुंच चुकी है। इसके अलावा यूएई, म्यांमार, अमेरिका, कतर, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, जापान, न्यूजीलैंड, मलेशिया, सिंगापुर समेत कई देशों से और राहत सामग्री आने की प्रक्रिया जारी है।

### नेपाल की रसुवागढ़ी जलविद्युत परियोजना की सुरंग में रेस्क्यू खत्म, बचाव दल लौटा

**काठमांडू।** रसुवा की भोटेकोशी नदी में बाढ़ आने के बाद प्रभावित रसुवागढ़ी जलविद्युत परियोजना की सुरंग के अंदर खोजबीन करने पहुंची नेपाली सेना के नेतृत्व वाली रेस्क्यू टीम को कोई भी जीवित या मृत व्यक्ति नहीं मिला। इसके बाद बचाव दल वापस लौट गया। इस सुरंग में 93 लोगो के फंसे होने की जानकारी परियोजना के तरफ से दी गई थी।

सुरंग के अंतिम हिस्से में लोगों के फंसे होने की आशंका के बाद नेपाली सेना की टीम इंजीनियरों और ड्रोन टीम के साथ खोज अभियान में जुटी थी।बचाव दल ने सुरंग के अंदर अंतिम बिंदु तक पहुंचकर ड्रोन के जरिए भी व्यापक खोज की, लेकिन वहां किसी भी जीवित व्यक्ति की मौजूदगी या मृत व्यक्ति का शरीर के संकेत नहीं मिले। सुरंग के अंदर कोई व्यक्ति नहीं होने की पुष्टि के बाद नेपाली सेना ने अपना खोज अभियान समाप्त कर दिया और टीम रसुवा के धुन्चे लौट गई। इस हाइड्रोपावर परियोजना के तरफ से 93 लोगों के फंसे होने की जानकारी सरकार को दी गई थी। सुरंग में कई फिट मलबे जमा होने के कारण बचाव कार्य में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा।

# नेपाल जलप्रलयः तीन जिलों के 16 स्कूल क्षतिग्रस्त, 233 छात्र और 17 शिक्षक लापता

**काठमांडू,एजेंसी।** भोटेकोशी नदी में आई बाढ़ से नेपाल के तीन जिलों में 16 विद्यालय क्षतिग्रस्त हुए हैं, जबकि 233 छात्र और 17 शिक्षक अब तक लापता (संपर्कविहीन) हैं। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार रविवार तक मिले प्रारंभिक विवरण में रसुवा, नुवाकोट और धादिंग के 16 विद्यालयों के पूर्ण रूप से नुकसान पहुंचने की जानकारी मिली है। इन विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों और शिक्षकों समेत कुल 250 लोग संपर्कविहीन बताए गए हैं।

प्रारंभिक आंकड़ों के अनुसार, रसुवा के चार, नुवाकोट के आठ और धादिंग के चार विद्यालय प्रभावित हुए हैं। रसुवा के उत्तरगया और गोसाईंकुंड गांवपालिका, नुवाकोट की विदुर नगरपालिका तथा धादिंग की गल्छी, सिद्धलेक गांवपालिका और नीलकंठ नगरपालिका के विद्यालयों को नुकसान पहुंचा है। मंत्रालय के अनुसार, इनमें से अधिकांश विद्यालय बाढ़ में बह गए हैं, जबकि कुछ विद्यालयों के कक्षाओं में कीचड़, रेत और मिट्टी भर गई है। रसुवा के चार विद्यालय पूरी तरह क्षतिग्रस्त हुए हैं। इसी तरह नुवाकोट के चार विद्यालय पूरी तरह और चार विद्यालय आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं। नुवाकोट की विदुर नगरपालिका स्थित आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त चंडेश्वरी माध्यमिक विद्यालय के 12 छात्रों और एक शिक्षक के संपर्कविहीन होने की जानकारी है। रसुवा के नवविजयी महेंद्र माध्यमिक विद्यालय के दो शिक्षक और कोमी श्यामेवाङ्फेल माध्यमिक विद्यालय के एक शिक्षक सहित 16 छात्र भी संपर्कविहीन हैं। धादिंग में एक विद्यालय पूरी तरह

क्षतिग्रस्त हुआ है, जबकि तीन विद्यालयों को आंशिक नुकसान पहुंचा है। उत्तरगया गांवपालिका के नीलकंठ माध्यमिक विद्यालय की इमारत को नुकसान नहीं पहुंचा है, लेकिन विद्यालय के 200 छात्रों और चार शिक्षकों के संपर्कविहीन होने की जानकारी मिली है। गोसाईंकुंड गांवपालिका के कोमी श्यामेवाङ्फेल माध्यमिक विद्यालय के 16 छात्रों और एक शिक्षक के बाढ़ में लापता होने की जानकारी है। वहीं, गोसाईंकुंड तीर्थयात्रा पर गए धादिंग के चार शिक्षक भी संपर्कविहीन हैं।

मंत्रालय के अनुसार, रसुवा के नेपाल राष्ट्रीय आधारभूत विद्यालय के 10 शिक्षकों में से केवल तीन शिक्षक ही संपर्क में हैं। नुवाकोट के त्रिभुवन बहुमुखी कैंपस और त्रिभुवन त्रिशूली माध्यमिक विद्यालय के छात्रावास भी मिट्टी और मलबे में दबकर क्षतिग्रस्त हुए हैं। प्रभावित विद्यालयों में अधिकांश सामुदायिक और कुछ निजी विद्यालय हैं। नुवाकोट के त्रिशूली सामुदायिक बोर्डिंग स्कूल के भी तीन छात्र संपर्कविहीन हैं। मंत्रालय ने कहा है कि बाढ़ से हुई क्षति का पूरा विवरण अभी आना बाकी है। रसुवा के गोसाईंकुंड गांवपालिका स्थित नेपाल राष्ट्रीय आधारभूत विद्यालय पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। इस विद्यालय में 109 छात्र पढ़ते हैं। इसी तरह उत्तरगया गांवपालिका के चिप्लेटी आधारभूत विद्यालय, मॉडर्न ट्रिनिटी बोर्डिंग और मालिकादेवी आधारभूत विद्यालय पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं और बाढ़ में बह गए हैं। नुवाकोट की विदुर नगरपालिका स्थित त्रिभुवन त्रिशूली माध्यमिक विद्यालय भी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। बाढ़ में विद्यालय की इमारत बह गई। इस विद्यालय में करीब 1,600 छात्र पढ़ते हैं। हालांकि बाढ़ आने से पहले ही सभी छात्रों को घर भेज दिया गया था, इसलिए यहां मानवीय क्षति नहीं हुई। इसके अलावा चंडेश्वरी माध्यमिक विद्यालय, रामचंद्र आधारभूत विद्यालय, त्रिशूली सामुदायिक बोर्डिंग, ज्ञानकुंज बोर्डिंग, उत्तरगया पब्लिक इंग्लिश स्कूल, जेडी बोर्डिंग स्कूल और पायोनियर बोर्डिंग स्कूल को भी नुकसान पहुंचा है। धादिंग की गल्छी गांवपालिका स्थित बागेश्वरी माध्यमिक विद्यालय, सक्सेस एकेडमी, अम्लेश्वर गुरुकुल संस्कृत विद्यालय और जलेश्वर माध्यमिक विद्यालय भी बाढ़ से प्रभावित हुए हैं।

# होर्मुज के लराक पर वाशिंगटन की बमबारी, ईरान का जॉर्डन में अमेरिकी ठिकाने पर हमला

**अम्मान/तेहरान/वाशिंगटन।** होर्मुज जलडमरूमध्य के दक्षिणी ईरान के लराक द्वीप पर बमबारी के जवाब में ईरान ने जॉर्डन में अमेरिकी सैन्य ठिकाने पर हमला किया है। अमेरिका ने लगभग एक माह बाद ईरान के खिलाफ बड़ा हमला किया। इसके बाद ईरान की सेना ने जवाब दिया। हमले में रॉकेट, ड्रोन और मिसाइलों का प्रयोग किया। ताजा सैन्य टकराव से तेल कीमतों में उछाल आने की संभावना है।

अल जजीरा और सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिका ने रविवार को लराक द्वीप पर हमला किया। इसके जवाब में ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (आईआरजीसी) ने जॉर्डन में किंग हुसैन और अल-अजराक में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। आईआरजीसी ने हमले में मिसाइल और ड्रोन का इस्तेमाल किया। जुलाई के आखिर के बाद से दोनों पक्षों के बीच हिंसा में यह तेजी पहली बार आई है। आईआरजीसी ने कहा कि इन हमलों ने 'तकनीकी और मरम्मत के बुनियादी ढांचे के साथ-साथ दुश्मन के लड़ाकू विमानों की तैनाती वाली जगहों को भी नष्ट कर दिया गया। आईआरजीसी की हमले की घोषणा के तुरंत बाद जॉर्डन ने आठ मिसाइलों को रोकने (इंटरसेप्ट करने) की सूचना दी। जॉर्डन की सेना ने एक बयान में कहा, 'एयर डिफेंस सिस्टम ने उन आठ मिसाइलों को रोका जो आज, सोमवार तड़के किंगडम के हवाई क्षेत्र में घुस गई थीं।' इस दौरान किसी के घायल

होने की सूचना नहीं है। एक अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि वाशिंगटन के हमलों ने लराक पर उन लॉन्चरों को निशाना बनाया जो होर्मुज जलडमरूमध्य की ओर बारूदी सुरंगों वाले क्षेत्र में रॉकेट दागने के लिए तैयार थे। ईरान की फार्स समाचार एजेंसी ने कहा कि अमेरिकी हमले में कई सैनिक मारे गए और घायल हुए।

हाल के हफ्तों में वाशिंगटन होर्मुज पर नियंत्रण का दावा कर रहा है और कह रहा है कि तेहरान की नाकाबंदी के बावजूद अमेरिकी सैन्य सुरक्षा के तहत लाखों बैरल तेल इस जलमार्ग से गुजरा। ईरान का कहना है कि जलमार्ग बंद है। ट्रंप प्रशासन ने कहा है कि अमेरिकी मध्य कमान (सेंटकॉम) ने पिछले हफ्ते जलमार्ग के इंटरनेशनल शिपिंग रूट से समुद्री बारूदी सुरंगों को हटाने का काम पूरा कर लिया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कह चुके हैं कि अब अगर कोई जहाज या नाव नई बारूदी सुरंगें बिछाती है तो उसे तुरंत नष्ट कर दिया जाएगा। अमेरिकी अधिकारी ने कहा, 'अमेरिकी सेना इस इलाके पर बारीकी से नजर रख रही है और इस जरूरी जलमार्ग से व्यापार के निर्बाध प्रवाह की सुरक्षा के लिए तैयार है।' ये हमले ऐसे समय में हुए हैं जब ईरान और ओमान इस जलडमरूमध्य से समुद्री यातायात बहाल करने के लिए एक प्रस्तावित व्यवस्था पर बातचीत कर रहे हैं। कतर सहित क्षेत्रीय मध्यस्थों ने इन वार्ताओं का समर्थन किया है। ईरानी अधिकारियों ने बार-बार इस जलडमरूमध्य से नेविगेशन के भविष्य को वाशिंगटन के साथ व्यापक चर्चाओं और क्षेत्रीय सुरक्षा घटनाक्रमों से जोड़ा है। रविवार का हमला 29 जुलाई के बाद ईरान पर पहला अमेरिकी हमला है। इस बीच, रविवार को तेल की कीमतों में उछाल आया।

### नेपाल के बाढ़ प्रभावित इलाकों के लिए अमेरिका ने अपडेट की ट्रैवल एडवाइजरी

**काठमांडू,एजेंसी।** काठमांडू स्थित अमेरिकी दूतावास ने नेपाल यात्रा संबंधी अपनी ट्रैवल एडवाइजरी अपडेट करते हुए रसुवा जिले के रसुवागढ़ी-टिमुरे-स्याफ्रुबेंसी क्षेत्र और नेपाल-चीन सीमा नाका वाले इलाकों में किसी भी कारण से यात्रा नहीं करने की सलाह दी है। अमेरिकी दूतावास के मुताबिक 26 अगस्त को आई भीषण बाढ़ के बाद इस क्षेत्र में सड़क, यातायात और संचार सेवाएं प्रभावित हैं। प्रभावित इलाकों में खोज एवं बचाव तथा पुनर्स्थापना का काम अभी जारी है, जिसके कारण जोखिम का स्तर काफी अधिक है। इसके साथ ही आगे भी बाढ़ और भूस्खलन की आशंका जताई गई है।

अमेरिका ने प्रभावित क्षेत्र को 'लेवल-4: यात्रा न करें' श्रेणी में रखा है। इसमें भोटेकोशी, त्रिशूली और नारायणी नदी के आसपास के इलाके भी शामिल हैं। अमेरिकी दूतावास ने अपने नागरिकों को नदी किनारे, निचले इलाकों, क्षतिग्रस्त पुलों और अस्थिर पहाड़ी ढलानों से दूर रहने की सलाह दी है। साथ ही नेपाली अधिकारियों की ओर से जारी किसी भी बचाव आदेश या सुरक्षित स्थान पर जाने के निर्देश का पालन करने को कहा गया है।अमेरिकी नागरिकों को लापता लोगों की तलाश के लिए भी आपदा प्रभावित क्षेत्रों में खुद प्रवेश नहीं करने और किसी भी कारण से इन इलाकों की यात्रा नहीं करने की चेतावनी दी गई है। अमेरिकी दूतावास ने पूरे नेपाल को 'लेवल-2: अधिक सावधानी बरतें' श्रेणी में रखा है। इसका प्रमुख कारण नागरिक अशांति बताया गया है।अमेरिकी आकलन के अनुसार सितंबर, 2025 में शुरू हुए देशव्यापी प्रदर्शन फिलहाल रुक गए हैं और वर्तमान सुरक्षा स्थिति स्थिर है। हालांकि, शहरों में प्रदर्शन और स्थानीय स्तर पर अशांति दोबारा होने की संभावना जताई गई है। अमेरिका ने चेतावनी दी है कि प्रदर्शन बहुत कम समय के नोटिस पर शुरू होकर कुछ परिस्थितियों में हिंसक भी हो सकते हैं। इसलिए, अमेरिकी नागरिकों को बड़ी भीड़ और प्रदर्शनों से दूर रहने तथा स्थानीय प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की सलाह दी गई है। अमेरिकी दूतावास ने कहा है कि नेपाल में स्वास्थ्य और आपातकालीन सेवाओं की क्षमता सीमित है।

हालांकि, काठमांडू के अस्पताल देश के अन्य हिस्सों की तुलना में आम तौर पर बेहतर हैं, लेकिन वहां भीड़भाड़, जरूरी उपकरणों या दवाओं की कमी और इलाज शुरू होने से पहले भुगतान की मांग जैसी स्थितियां हो सकती हैं। अमेरिकी दूतावास ने स्पष्ट किया है कि विदेशी नागरिकों के इलाज का खर्च नेपाल सरकार नहीं उठाती। इसलिए अमेरिकी नागरिकों को जरूरी दवाएं साथ रखने, मेडिकल इवैक्युएशन यानी चिकित्सकीय निकासी को कवर करने वाला यात्रा स्वास्थ्य बीमा कराने और गंभीर स्वास्थ्य समस्या होने पर इलाज के लिए किसी दूसरे देश जाना पड़ने की संभावना के लिए तैयार रहने की सलाह दी गई है। अमेरिकी दूतावास ने नेपाल में नियमित रूप से आने वाले भूकंप, बाढ़ और भूस्खलन के खतरे का भी उल्लेख किया है।

## एक नजर

### राहुल गांधी के विरुद्ध प्राथमिकी के विरोध में गुवाहाटी में एपीसीसी ने किया प्रदर्शन

**गुवाहाटी,एजेंसी।** असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी (एपीसीसी) ने आज पूरे राज्य में ज़बरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नीत सरकार द्वारा लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ साजिश के तहत प्राथमिकी दर्ज करने की निंदा की। राहुल गांधी ने उत्तराखंड के हल्द्वानी में एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की सभा वाली जगह पर भाजपा व अन्य संगठनों के कार्यकर्ताओं द्वारा जाति-आधारित 'शुद्धिकरण' की रस्म निभाने के लिए उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की थी। एपीसीसी अध्यक्ष गौरव गोगोई के निर्देशों पर, असम के सभी ज़िला मुख्यालयों और गुवाहाटी में पार्टी के राज्य मुख्यालय 'राजीव भवन' में ज़ोरदार प्रदर्शन आयोजित किए गए। इन प्रदर्शनों में भाजपा सरकार की राजनीतिक बदले की भावना और सरकारी मशीनरी के खुलेआम दुरुपयोग का विरोध किया गया। एपीसीसी मीडिया और संचार विभाग के अध्यक्ष बेदब्रत बोरा के संचालन में हुए इस विरोध प्रदर्शन में कई वरिष्ठ नेताओं और विधायकों ने सक्रिय रूप से हिस्सा लिया। प्रमुख लोगों में कांग्रेस विधायक दल (सीएलपी) के नेता वाज़ेद अली चौधरी, एपीसीसी के पूर्व अध्यक्ष रिपुन बोरा, विधायक आफताब उद्दीन मुल्ला, मोहिबुर रहमान, अमीनुर राशिद चौधरी और नूरुल इस्लाम, एपीसीसी के महासचिव (संगठन) रमन्ना बरुवा, महासचिव शांतनु बोरा, वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री नीलामणि सेन डेका, पूर्व विधायक अमीनुल इस्लाम, गुवाहाटी शहर ज़िला कांग्रेस अध्यक्ष स्वपन दास, कामरूप ज़िला कांग्रेस अध्यक्ष प्रांजित चौधरी के साथ-साथ प्रदेश कांग्रेस और कामरूप (मेट्रो) ज़िला कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल थे।

### आकलन वर्ष 2026-27 के लिए रिकॉर्ड 7.5 करोड़ आयकर रिटर्न दाखिल

**नई दिल्ली।** आर्थिक मोर्चे पर अच्छी खबर है। आकलन वर्ष 2026-27 के लिए अब तक रिकॉर्ड 7.5 करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल किए जा चुके हैं। कारोबार या पेशेवर करदाताओं के लिए आईटीआर फाइल करने की निर्धारित समय-सीमा 31 अगस्त मध्यरात्रि तक है। आयकर विभाग ने सोमवार को 'एक्स' पर जारी एक पोस्ट में बताया कि दोपहर तक 7.5 करोड़ से अधिक आईटीआर दाखिल किए जा चुके थे। इनमें 31 जुलाई की समय-सीमा तक दाखिल किए गए 5.9 करोड़ से अधिक आईटीआर-1 और आईटीआर-2 भी शामिल हैं। पिछले साल आकलन वर्ष 2025-26 के लिए ऑडिट के दायरे में नहीं आने वाले मामलों में 16 सितंबर, 2025 की बढ़ाई गई समय-सीमा तक 7.3 करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न दाखिल किए गए थे। विभाग ने कहा कि कारोबार या पेशेवर आमदनी वाले और ऑडिट के दायरे में नहीं आने वाले करदाताओं के लिए आईटीआर दाखिल करने की समय-सीमा 31 अगस्त मध्यरात्रि को समाप्त हो रही है। ऐसे में आज रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है। इस श्रेणी के करदाता अपने लिए लागू आईटीआर-3, आईटीआर-4, आईटीआर-5 या आईटीआर-7 दाखिल कर आईटीआर-3 उन व्यक्तियों और हिंदू अविभाजित परिवारों (एचयूएफ) के लिए है, जिनकी आय स्वामित्व वाले कारोबार या पेशे से होती है। इसके अलावा आईटीआर-4 छोटे और मध्यम करदाताओं के लिए सरल फॉर्म है। वहीं, आईटीआर-5 फर्म, सीमित देयता भागीदारी (एलएलपी) और सहकारी समितियां दाखिल करती हैं।

# रेड क्रॉस सोसाइटी की गतिविधियों को और अधिक गति देने की है आवश्यकता : राज्यपाल

**लखनऊ,एजेंसी।** उत्तर प्रदेश की राज्यपाल एवं भारतीय रेडक्रॉस सोसाइटी, उत्तर प्रदेश राज्य शाखा की अध्यक्ष आनंदीबेन पटेल की अध्यक्षता में सोमवार को जन भवन, लखनऊ में भारतीय रेडक्रॉस सोसाइटी की वार्षिक सामान्य बैठक संपन्न हुई। बैठक में भारतीय रेडक्रॉस सोसाइटी, उत्तर प्रदेश राज्य शाखा द्वारा प्रदेश के विभिन्न जनपदों में संचालित सामाजिक एवं मानवीय गतिविधियों की समीक्षा की गई तथा आगामी वर्ष की कार्ययोजनाओं एवं कार्यक्रमों पर विचार-विमर्श किया गया। बैठक का प्रमुख उद्देश्य रेडक्रॉस की सेवाओं को और अधिक प्रभावी एवं जनोन्मुखी बनाते हुए स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन तथा जरूरतमंद लोगों को उपलब्ध कराई जा रही मानवीय सहायता को सुदृढ़ करना रहा।

बैठक को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि भारतीय रेडक्रॉस सोसाइटी अपने स्थापना उद्देश्यों के अनुरूप सेवा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण, आपदा प्रबंधन तथा समाज के वंचित वर्गों के कल्याण के लिए व्यापक स्तर पर कार्य करे। उन्होंने कहा कि सोसाइटी की गतिविधियों को और अधिक गति देने की आवश्यकता है। किसी भी आपदा अथवा आवश्यकता के समय जिस प्रकार सेना के जवान समाज की सहायता के लिए तत्पर रहते हैं, उसी प्रकार सोसाइटी की ऐसी विशिष्ट पहचान बननी चाहिए कि लोग उसे सेवा और मानवीय सहायता के लिए भरोसेमंद संस्था के रूप में देखें।

राज्यपाल ने पर्यावरण संरक्षण एवं स्वच्छता पर विशेष बल देते हुए निर्देश दिए कि प्रत्येक जनपद में अधिक से अधिक वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किए जाएं तथा इसके लिए स्थान चिन्हित किए जाएं। उन्होंने प्रत्येक जनपद में ऐसे स्थान भी चिन्हित करने को कहा, जहां स्वच्छता अभियान चलाकर उन्हें स्वच्छ एवं सुंदर बनाया जा सके। उन्होंने सार्वजनिक स्थानों की स्वच्छता को जनभागीदारी से जोड़ने तथा लोगों में स्वच्छता के प्रति जिम्मेदारी की भावना विकसित करने पर जोर दिया। अपने कानपुर दौरे के दौरान रेल यात्रा का उल्लेख करते हुए राज्यपाल ने बताया कि उन्होंने रेलवे स्टेशनों पर गंदगी देखी। इसके बाद जन भवन में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने नगर निगम के सहयोग से स्वच्छता अभियान चलाया, जिसमें लगभग 40 टन कूड़ा एकत्र किया गया। इस प्रकार के कार्यों से बच्चों और युवाओं में भी स्वच्छता एवं सेवा का संस्कार विकसित किया जा सकता है। उन्होंने सार्वजनिक स्थानों की स्वच्छता को सामूहिक जिम्मेदारी बनाने पर जोर दिया। राज्यपाल ने योग को जन-जन तक पहुंचाने की आवश्यकता पर भी बल दिया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 30 अगस्त, 2026 को उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में योग फेडरेशन ऑफ उज्बेकिस्तान द्वारा आयोजित विशेष योग सत्र में सहभागिता का उल्लेख करते हुए कहा कि वहां उज्बेक योग साधकों ने योग किया तथा प्रधानमंत्री ने स्वयं उनके योगासनों को देखा और उनकी सराहना की। उन्होंने कहा कि यह हमारे लिए गर्व का विषय है कि आज पूरी दुनिया भारत से योग सीख रही है और उसे अपना रही है। भारत की प्राचीन योग परंपरा विश्व को स्वस्थ जीवन का मार्ग दिखा रही है।

# प्रधानमंत्री मोदी के सेवा समर्पण के संदेश को हर घर तक पहुंचाएं कार्यकर्ता-पदाधिकारी: ईरानी

**लखनऊ,एजेंसी।** भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जन्मदिन 17 सितम्बर से शुरु करके 17 अक्टूबर तक पूरे प्रदेश में सेवा संकल्प अभियान के माध्यम से सेवा एवं जनकल्याणकारी कार्य करेगी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक के 25 वर्षों के सार्वजनिक जीवन को समर्पित इस अभियान का उद्देश्य उनके सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण और विकसित भारत के संकल्प को जन-जन तक पहुंचाना है।

सेवा संकल्प अभियान को लेकर प्रदेश स्तरीय कार्यशाला का आयोजन सोमवार को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ में किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राष्ट्रीय महामंत्री स्मृति ईरानी, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष एवं केन्द्रीय वित्तराज्य मंत्री पंकज चौधरी, उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य व ब्रजेश पाठक तथा प्रदेश महामंत्री (संगठन) धर्मपाल सिंह की उपस्थिति में आयोजित कार्यशाला में प्रदेश पदाधिकारी, प्रदेश मोर्चा अध्यक्ष, क्षेत्रीय अध्यक्ष, जिलाध्यक्ष, जिला प्रभारी तथा अभियान के जिला संयोजक व सहसंयोजक उपस्थित रहे। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय महामंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक के 25 वर्षों के सार्वजनिक जीवन की सबसे बड़ी विशेषता सत्ता नहीं, बल्कि सेवा, संकल्प और परिणाम की राजनीति रही है। जब संकल्प सेवा का होता है तो समय केवल कार्यकाल नहीं गिनता, बल्कि उसके परिणामों से इतिहास बनता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व की विशेषता यह है कि दशकों से लंबित कार्यों को दृढ़ इच्छाशक्ति और स्पष्ट संकल्प के साथ पूरा किया गया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की कार्यशैली केवल योजनाएं बनाने की नहीं, बल्कि उन्हें अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने की है। देश में डिजिटल भुगतान और यूपीआई जैसी व्यवस्थाओं ने आम नागरिक के जीवन को सरल बनाया है। आज करोड़ों असंगठित श्रमिकों को सरकारी योजनाओं और व्यवस्थाओं से जोड़ने का ऐतिहासिक कार्य भी मोदी सरकार के नेतृत्व में हुआ है। कोविड काल में वैक्सीन जैसी उपलब्धियों ने यह सिद्ध किया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की नीतियों का लाभ समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुंचा है।

## देश की जून तिमाही की 7.8 फीसदी जीडीपी वृद्धि ने फिर सिद्ध की अर्थव्यवस्था की मजबूती: प्रवीन खंडेलवाल

**नई दिल्ली।** देश की अर्थव्यवस्था ने वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही (अप्रैल-जून) में 7.8 फीसदी की प्रभावशाली वृद्धि दर दर्ज कर एक बार फिर यह साबित किया है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत विश्व की सबसे तेज़ गति से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अपनी अग्रणी स्थिति बनाए हुए है। चांदनी चौक से सांसद एवं कन्फ़ेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीन खंडेलवाल ने सोमवार को सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के जारी आंकड़ों पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए यह बात कही। खंडेलवाल ने कहा कि यह वृद्धि दर न केवल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) के अनुमान से अधिक है, बल्कि अधिकांश अर्थशास्त्रियों की अपेक्षाओं को भी पीछे छोड़ती है।

उन्होंने कहा की इस उल्लेखनीय उपलब्धि पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के देश की आर्थिक नीतियों के निर्माण और क्रियान्वयन का ही प्रतिफल है। यह वृद्धि स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत घरेलू मांग, बढ़ते निवेश, विनिर्माण क्षेत्र की प्रगति, बुनियादी ढांचे पर बढ़े हुए व्यय तथा निर्यात के बेहतर प्रदर्शन के बल पर आगे बढ़ रही है। खंडेलवाल ने कहा कि देश के व्यापार जगत के लिए यह विशेष रूप से उत्साहजनक संकेत है कि पूंजीगत निवेश (कैपिटल फॉर्मेशन) में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि उद्योग और व्यापार समुदाय भारत की विकास यात्रा पर पूरा विश्वास जता रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा अवसंरचना निर्माण, डिजिटल अर्थव्यवस्था, विनिर्माण और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में किए गए निवेश का सकारात्मक प्रभाव अब स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा है। उन्होंने यह भी कहा की वैश्विक स्तर पर भू-राजनीतिक तनाव, ऊर्जा कीमतों में उतार-चढ़ाव और अंतरराष्ट्रीय आर्थिक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत का यह प्रदर्शन अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह दर्शाता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की बुनियाद मजबूत है और देश आत्मनिर्भरता, उत्पादन, नवाचार तथा उपभोग आधारित विकास मॉडल के साथ आगे बढ़ रहा है। खंडेलवाल ने कहा की देश के व्यापारियों को इससे बड़ा लाभ होगा और निश्चित रूप से आगामी तिमाहियों में भी भारत की आर्थिक वृद्धि मजबूत बनी रहेगी। 'विकसित भारत 2047' के लक्ष्य को प्राप्त करने में व्यापार, उद्योग, एमएसएमई, स्टार्टअप्स और उपभोक्ता वर्ग की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। भारत की यह विकास गाथा न केवल आर्थिक समृद्धि का प्रतीक है, बल्कि वैश्विक मंच पर भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा का भी प्रमाण है।

# अब्बासी समाज की तरक्की के लिए एकजुटता जरूरी : इस्लाम अब्बासी

**सद्भावना टुडे, संवाददाता**

**नई दिल्ली।** अब्बासी समाज द्वारा आयोजित एक सामाजिक कार्यक्रम में समाज की एकता, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और नशामुक्ति सहित सामाजिक सुधार से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर गंभीर चर्चा हुई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए इस्लाम अब्बासी ने समाज के लोगों से आपसी मतभेदों को दूर कर एकजुट होने तथा समाज के सर्वांगीण विकास के लिए सामूहिक प्रयास करने का आह्वान किया। इस्लाम अब्बासी ने कहा कि किसी भी समाज की वास्तविक तरक्की उसकी एकता और शिक्षा पर निर्भर करती है। यदि समाज के लोग एकजुट होकर बच्चों की शिक्षा, युवाओं के भविष्य, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे मुद्दों पर गंभीरता से कार्य करें, तो सामाजिक परिस्थितियों में सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि समाज में शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाना आज की प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल होना चाहिए।

उन्होंने विशेष रूप से युवा पीढ़ी को नशे की बुराई से बचाने के लिए नशामुक्ति अभियान को व्यापक स्तर पर चलाने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि नशा केवल व्यक्ति के स्वास्थ्य को प्रभावित नहीं करता, बल्कि इससे परिवार और पूरे समाज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। समाज के जागरूक लोगों को आगे आकर युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए लगातार जागरूकता अभियान चलाने चाहिए। कार्यक्रम में शिक्षा के महत्व पर चर्चा करते हुए वक्ताओं ने कहा कि बच्चों को बेहतर और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए अभिभावकों को विशेष ध्यान देना होगा। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों की शिक्षा में सहयोग के लिए समाज के सक्षम लोगों को आगे आने की जरूरत है। वक्ताओं के अनुसार, शिक्षा ही वह माध्यम है जिसके जरिए नई पीढ़ी को बेहतर भविष्य और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा सकते हैं। स्वास्थ्य और रोजगार के मुद्दे पर भी कार्यक्रम में विचार-विमर्श हुआ। वक्ताओं ने कहा कि समाज के लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के साथ जरूरतमंद परिवारों तक स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए सामूहिक प्रयास किए जाने चाहिए। वहीं युवाओं को रोजगार के साथ-साथ कौशल विकास से जोड़ने के लिए भी ठोस पहल की आवश्यकता बताई गई। कार्यक्रम के दौरान सामाजिक सुधार और समाज के विकास से जुड़े विभिन्न विषयों पर उपस्थित लोगों ने अपने विचार रखे। इस अवसर पर अब्बासी समाज के गणमान्य लोगों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और बड़ी संख्या में समाज के लोगों ने भाग लिया। उपस्थित लोगों ने समाज की एकता को मजबूत करने तथा सामाजिक बुराइयों के खिलाफ मिलकर काम करने की आवश्यकता पर सहमति व्यक्त की। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य समाज के लोगों को एक मंच पर लाकर सामाजिक समस्याओं पर संवाद करना और उनके समाधान के लिए आवश्यक सुधारात्मक कदमों को आगे बढ़ाना रहा। इस दौरान समाज की नई पीढ़ी को शिक्षा से जोड़ने, युवाओं को नशे से दूर रखने और रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दिया गया।

# बिहार की सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं को मिलेगी नई रफ्तार

**सद्भावना टुडे संवाददाता**

**नई दिल्ली।** बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोमवार को नई दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल से मुलाकात कर बिहार की महत्वपूर्ण सिंचाई, जल संसाधन एवं बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं को गति देने के संबंध में विस्तृत चर्चा की। बैठक में उपमुख्यमंत्री सह जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से कोसी-मेची अंतर्राज्यीय रिवर लिंक परियोजना सहित केंद्रीय बजट में घोषित लंबित सिंचाई एवं बाढ़ प्रबंधन योजनाओं को शीघ्र स्वीकृति देने तथा आवश्यक केंद्रीय सहायता उपलब्ध कराने का आग्रह किया। बैठक में कोसी-मेची परियोजना को विशेष प्राथमिकता दी गई। करीब 3,652.56 करोड़ रुपये की इस महत्वाकांक्षी परियोजना का उद्देश्य कोसी बेसिन के अतिरिक्त जल का बेहतर उपयोग करते हुए उत्तर बिहार में सिंचाई सुविधाओं का विस्तार करना है। परियोजना के प्रथम चरण के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 में 395.41 करोड़ तथा 2026-27 में 570 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री ने प्रथम चरण की शेष राशि जल्द उपलब्ध कराने और दूसरे चरण के डीपीआर को मंजूरी देने की मांग की।

**पश्चिमी कोसी नहर परियोजना पर भी चर्चा**

मुख्यमंत्री ने पश्चिमी कोसी नहर परियोजना के विस्तार, नवीकरण एवं आधुनिकीकरण की प्रगति की भी समीक्षा की। बिहार सरकार ने इस परियोजना के लिए 8,338.89 करोड़ रुपये का डीपीआर केंद्रीय जल आयोग को भेजा है। केंद्रीय सहायता की प्रतीक्षा के बावजूद राज्य सरकार ने अपने संसाधनों से करीब 3,484.24 करोड़ रुपये की लागत वाले प्रथम चरण का कार्य शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री ने परियोजना की शीघ्र स्वीकृति और केंद्रीय वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का अनुरोध किया। इसके अलावा सिकरहना दायां तटबंध निर्माण योजना के लिए केंद्रीय सहायता जल्द जारी करने तथा सिंचाई एवं बाढ़ प्रबंधन की अन्य लंबित परियोजनाओं को भी शीघ्र स्वीकृति देने की मांग की गई।

**2026-27 के केंद्रीय बजट में तीन योजनाओं को शामिल करने की मांग**

मुख्यमंत्री ने आगामी केंद्रीय बजट 2026-27 में बिहार की तीन महत्वपूर्ण परियोजनाओं को शामिल करने का अनुरोध किया। इनमें इंद्रपुरी जलाशय योजना, सोन-फल्गु नदी जोड़ परियोजना तथा सारण जिला बाढ़ नियंत्रण एवं जलनिकासी परियोजना के प्रथम चरण को शामिल किया गया है। इंद्रपुरी जलाशय परियोजना से सोन नहर प्रणाली को दीर्घकालिक स्थिरता मिलने की उम्मीद है। वहीं सोन-फल्गु नदी जोड़ परियोजना के माध्यम से सोन नदी के पानी को फल्गु नदी तक पहुंचाकर गया और औरंगाबाद के सूखाग्रस्त क्षेत्रों में सिंचाई एवं पेयजल की समस्या को दूर करने में मदद मिलेगी। सारण जिला बाढ़ नियंत्रण एवं जलनिकासी परियोजना के प्रथम चरण की अनुमानित लागत 1,350.95 करोड़ रुपये है। इसके तहत प्रमुख जलनिकासी चैनलों का जीर्णोद्धार, नए रेगुलेटरों का निर्माण सहित कई संरचनात्मक कार्य किए जाने हैं।

**गाद प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय नीति बनाने की मांग**

मुख्यमंत्री ने फरक्का बराज और भारत-बांग्लादेश गंगा जल संधि से जुड़ी गाद की समस्या, नदी की धारा में बदलाव और उससे उत्पन्न बाढ़ के स्थायी समाधान के लिए राष्ट्रीय गाद प्रबंधन नीति बनाने तथा इसके लिए समर्पित कोष गठित करने का आग्रह किया। उन्होंने गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग (त्रस्नष्टष्ट) के अध्यक्ष का मुख्यालय पटना में बनाए रखने की मांग भी रखी। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार गंगा बेसिन के प्रमुख बाढ़ प्रभावित राज्यों में है, इसलिए बाढ़ नियंत्रण से जुड़े त्वरित निर्णय और प्रभावी निगरानी के लिए आयोग का पटना में रहना आवश्यक है।

**नेपाल से जुड़ी परियोजनाओं में तेजी पर जोर**

बैठक में कोसी हाई डैम, कमला बहुउद्देशीय परियोजना और बागमती बांध परियोजना पर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने नेपाल से संबंधित इन परियोजनाओं के सर्वेक्षण एवं डीपीआर तैयार करने की प्रक्रिया में तेजी लाने और संयुक्त परियोजना कार्यालय में बिहार के प्रतिनिधियों की प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करने का अनुरोध किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के समन्वित प्रयासों से बिहार की सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं को गति मिलेगी। इन योजनाओं के पूरा होने से किसानों को सिंचाई सुविधा, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों को राहत और राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलने की उम्मीद है।

# एम के सलाहकार ने किया मूनीडीह सीबीएम परियोजना का निरीक्षण, अक्टूबर 2027 से गैस बिक्री की तैयारी

**धनबाद।** प्रधानमंत्री के सलाहकार तरुण कपूर अपने दो दिवसीय धनबाद दौरे के दौरान सोमवार को पूटकी स्थित मूनीडीह पहुंचे। यहां उन्होंने कोल बेड मीथेन यानी सीबीएम ब्लॉक-1 परियोजना का निरीक्षण किया। इस दौरान बीसीसीएल के सीएमडी मनोज अग्रवाल, वेस्ट झरिया क्षेत्र के महाप्रबंधक विजय कुमार समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। तरुण कपूर ने परियोजना की तकनीकी व्यवस्थाओं और गैस उत्पादन से जुड़ी गतिविधियों की जानकारी ली। इसके बाद उन्होंने बीसीसीएल सीएमडी के साथ डोली के माध्यम से खदान के अंदर जाकर वहां चल रहे कार्यों का जायजा लिया।

मूनीडीह पहुंचने के बाद पीएम के सलाहकार तरुण कपूर ने सबसे पहले सीबीएम परियोजना के विभिन्न हिस्सों का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने उन्हें परियोजना की तकनीकी व्यवस्था, गैस उत्पादन और भविष्य की संभावनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इसके बाद तरुण कपूर बीसीसीएल सीएमडी मनोज अग्रवाल के साथ डोली के माध्यम से खदान के अंदर गए और वहां चल रहे कार्यों को करीब से देखा। निरीक्षण के दौरान परियोजना से जुड़े अधिकारियों ने गैस उत्पादन की मौजूदा स्थिति और आने वाले समय की योजनाओं से उन्हें अवगत कराया। पत्रकारों से बातचीत में तरुण कपूर ने बताया कि कोल बेड मीथेन गैस का इस्तेमाल भविष्य में सीएनजी और घरेलू गैस के तौर पर किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि पहले इस क्षेत्र का काम पेट्रोलियम विभाग के अंतर्गत आता था, लेकिन अब इससे जुड़े कार्यों को कोल इंडिया स्वयं देखेगी। तरुण कपूर के मुताबिक, मूनीडीह से निकलने वाली गैस की बिक्री अक्टूबर 2027 से शुरू करने की योजना है। गैस की बिक्री बीसीसीएल करेगी और बाद में इसे गेल अथॉरिटी को सौंपे जाने की बात कही गई है। उन्होंने बताया कि गैस को ऊर्जा गंगा पाइपलाइन के माध्यम से आगे पहुंचाया जाएगा। मूनीडीह सीबीएम परियोजना का यह निरीक्षण धनबाद के कोयला क्षेत्र में गैस उत्पादन की संभावनाओं और परियोजना के भविष्य के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

मुद्रक, प्रकाशक, स्वामी, सैफुल्लाह सिद्दिकी द्वारा आरडी प्रिंटिंग एंड पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड, ए-24, सेक्टर-08, नोएडा (यूपी), से छपवा कर एन-81, बटला हाउस, जामिया नगर पुलिस स्टेशन, जामिया नगर, नई दिल्ली-110025 से प्रकाशित किया। सर्वाधिकार सुरक्षित, किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र दिल्ली होगा। (संपादक- सैफुल्लाह सिद्दिकी)